राष्ट्रीय संस्करण



दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बेजोस ने की अंतरिक्ष की सैर
>>14

वर्ष 5 अंक 41

# दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, बुधवार, 21 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

# बकरीद पर लाकडाउन में छूट देना गैरजरूरी : सुप्रीम कोर्ट

**जताई नाराजगी** ▸ शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा-लोगों की सेहत से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लाकडाउन में छूट देने के केरल सरकार के फैसले को गैर जरूरी बताया है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार संविधान में दिए गए लोगों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि दबाव बनाने वाला किसी भी तरह का समूह या धार्मिक समूह नागरिकों के बहुमूल्य मौलिक अधिकार में दखल नहीं दे सकता। अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि बकरीद पर दी गई छूट के बाद अगर कोरोना संक्रमण फैलने का मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केरल सरकार ने बकरीद पर राज्य में लाकडाउन से तीन दिन 18,19 और 20 जुलाई को छूट दी थी। यहां तक कि 15 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले डी श्रेणी के इलाकों में भी पूरे एक दिन की छूट दी गई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दाखिल हुई थी।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की सभी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि अधिक संक्रमण दर वाले इलाकों में एक दिन की भी छूट पूरी तरह अनावश्यक थी। राज्य सरकार लोगों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बारे में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन करे।

केरल सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि व्यापारियों ने बकरीद पर होने वाली बिक्री का अनुमान लगाते हुए पहले से ही काफी सामान एकत्र कर रखे थे। विक्रेता (ट्रेडर्स) संघों ने कोरोना के कड़े नियंत्रणों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। व्यापारियों ने ये घोषित कर दिया था कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए वे पूरे राज्य में दुकानें खोलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने व्यापारी संघों से विचार विमर्श और आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक के बाद बकरीद पर शर्तों के साथ छूट देने का फैसला किया था। व्यापारी संघ ने सरकार को नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया था।

- छूट की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी
- कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए नागरिकों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे राज्य सरकार



**सख्त टिप्पणी**

- किसी समूह के दबाव में आकर नागरिकों को राष्ट्रव्यापी महामारी के सामने असुरक्षित छोड़ देना राज्य सरकार की दयनीय स्थिति को दर्शाता है
- सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादा संक्रमण दर वाले डी श्रेणी के इलाकों में भी पाबंदियों में पूरे एक दिन की छूट दे दी गई
- महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले को लागू करे केरल सरकार

फटकार में देरी (संपादकीय) पेज>>8

## जागरण विशेष

### घर पर भी सुनी जा सकेगी गर्भस्थ के दिल की धड़कन



लखनऊ : अब सामान्य स्थिति में गर्भस्थ शिशु का हाल जानने के लिए अल्ट्रासाउंड व अन्य जांचों से निजात मिलेगी। शिशु के दिल की धड़कन व अन्य गतिविधियों को छोटे से उपकरण के जरिये घर पर भी जाना जा सकेगा। (पेज-10)

## न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 5

### छोटे कलाकारों को लालच देकर अश्लील फिल्में बनाता था कुंद्रा

मुंबई : मुंबई पुलिस का कहना है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने आए छोटे कलाकारों को लालच देकर उनकी अश्लील फिल्में बनाता था। इन फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न एप एवं ओटीटी प्लेटफार्म पर किया जाता था। राज कुंद्रा एवं उसके एक सहयोगी रेयान थार्प को सोमवार की रात मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 7

### आइपीओ और शेयरों में निवेश कर सकेंगे पेंशन फंड मैनेजर

नई दिल्ली : नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में शामिल चार करोड़ से अधिक धारकों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन दिलाने के उद्देश्य से सरकार पेंशन फंड में जमा रकम के इस्तेमाल को लेकर बदलाव करने जा रही है। अब पेंशन फंड का उपयोग कंपनियों के प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) और फालो-आन पब्लिक आफर (एफपीओ) की खरीदारी में भी किया जा सकेगा।

स्पोर्ट्स ▸ पृष्ठ 12

### श्रीलंका को 2-0 से हरा कर भारत का सीरीज पर कब्जा

नई दिल्ली : भारतीय टीम ने मंगलवार को कोलंबो में श्रीलंका की ओर से मिले 273 रन के लक्ष्य को तीन विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। दीपक चाहर ने करियर का पहला अर्धशतक जड़ते हुए भारत को अंतिम ओवर में रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली।

# सियासी संग्राम में बदला जासूसी विवाद

**संसद में टकराव** ▸ विपक्ष ने दूसरे दिन भी दोनों सदनों में किया हंगामा, नहीं हुआ कामकाज

### सदन के बाहर भी विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस फोन जासूसी विवाद सियासी संग्राम में बदल गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नेताओं, जजों और पत्रकारों समेत प्रमुख हस्तियों के फोन टैप कराए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला। विपक्ष इस मुददे पर संसद में तत्काल चर्चा कराने के साथ संयुक्त संसदीय समिति से जासूसी प्रकरण की जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार यह साफ कर चुकी है कि जासूसी कराने के दावे निराधार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच जासूसी प्रकरण पर छिड़े इस संग्राम के चलते लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पायी और सदन के भीतर ही नहीं बाहर भी विपक्षी दलों ने आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया।

मंगलवार को संसद की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस की अगुआई में तमाम विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में इजरायली साफ्टवेयर पेगासस के जरिये सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया और इस पर तत्काल बहस कराने की मांग की।

लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा आदि के सदस्य पोस्टर-बैनर लेकर अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। इन पोस्टर-बैनरों पर पेगासस के जरिये विपक्षी नेताओं से लेकर जजों के फोन की जासूसी किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया था। (पेज-3 भी देखें)



लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों को शांत करते हुए। प्रेट्र

**लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा की मांग खारिज की**

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष की इस मामले पर चर्चा की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि सरकार सोमवार को ही लोकसभा में जासूसी विवाद पर बयान दे चुकी है। विपक्ष के अधिकतर दलों ने जहां जासूसी मसले पर हंगामा किया वहीं अकाली दल के सदस्यों ने कृषि कानूनों के खिलाफ वेल में आकर नारेबाजी की।

**कार्यवाही बार-बार हुई बाधित**

विपक्षी हंगामे के बाद लोकसभा दो बजे तक स्थगित हुई। इसके बाद सदन को चलाने के दो प्रयास और हुए। विपक्षी दलों का हंगामा थमता नहीं देख सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस तरह लोकसभा में हंगामे की वजह से लगातार दूसरे दिन कामकाज नहीं हुआ। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने जासूसी कांड में सरकार को घेरते हुए जबरदस्त शोर-शराबा किया और सदन दो बार ठप भी हुआ। लेकिन कोरोना महामारी पर बहस कराने के सरकार के दांव के चलते विपक्ष दोपहर डेढ़ बजे के बाद जासूसी प्रकरण के मामले को मुल्तवी कर सदन में चर्चा को तैयार हो गया।

**तृकां ने गाधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन**

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों खासकर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के फोन की जासूसी कराए जाने को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह से जासूसी मामले में सफाई मांगी।

**पेगासस की खरीद पर मांगी सफाई**

राहुल गांधी समेत प्रमुख हस्तियों के फोन की जासूसी से इन्कार करने के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार यह साफ-साफ नहीं बता रही कि उसने पेगासस साफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। सरकार की इस गोल-मोल की कोशिश से साफ है कि वह जासूसी के इस मामले पर पर्दा डालना चाहती है और विपक्ष इसीलिए संयुक्त संदसीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी जासूसी प्रकरण को लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक करार देते हुए पड़ताल की पैरोकारी की।

## राज्यसभा में सरकार के नए सेनापतियों ने दिखाया दम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विपक्ष के पास मुद्दे भी कई हैं और फिलहाल उनमें एकजुटता भी दिख रही है। लेकिन जिस तरह मानसून सत्र के दूसरे ही दिन राज्यसभा में शुरुआती अवरोध के बाद कामकाज शुरू हो गया उसे सरकार शुभ संकेत मान रही है। माना जा रहा है कि अगले दो दिनों में लोकसभा में भी कामकाज सुचारू हो सकता है। यह अरसे बाद हुआ है कि इतनी जल्दी सदन में कामकाज नियमित हो सका है। दो दिन पहले ही राज्यसभा में भाजपा ने नए नेता सदन के रूप में पीयूष गोयल और उपनेता के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी का चयन किया है। बताया जाता है कि मंगलवार को पेगासस के मुद्दे पर अवरोध और स्थगन के बीच गोयल और नकवी ने सभी दलों के बड़े नेताओं से अनौपचारिक चर्चा की और यह समझाया कि कोरोना पर चर्चा से भागना सही नहीं होगा। विपक्ष को यह बात समझ में आ गई और तत्काल चर्चा शुरू हो गई। यानी गाड़ी पटरी पर आ गई है। जाहिर है कि लोकसभा में भी विपक्ष के नेताओं पर दबाव होगा कि वह शोर शराबे की बजाय अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आगे आएं। ऐसे में गुरुवार-शुक्रवार से नियमित कामकाज शुरू हो सकता है।

# कोरोना पर राजनीति से ऊपर सोचें : पीएम

**सर्वदलीय बैठक**

- कोरोना महामारी से मिलकर लड़ें केंद्र और राज्य : मोदी
- कांग्रेस, अकाली दल व वाम दलों ने किया बैठक से किनारा
- खड़गे बोले, संसद के दोनों सदनों में सरकार को रखने चाहिए तथ्य



दी नसीहत : नरेंद्र मोदी। फाइल

**कांग्रेस कोमा में, आरोपों का प्रभावी जवाब दें भाजपा सांसद**

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से विपक्ष के कोरोना महामारी के प्रबंधन में गुमराह करने वाले आरोपों का सक्रियता से जवाब देने के लिए कहा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोमा में चली गई है और भाजपा के सत्ता में आने को पचा पाने में असमर्थ है। (पेज-3)

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र व राज्यों से अपील की कि वे कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर एक टीम के रूप में काम करें। पीएम कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस समेत कुछ दलों ने इस बैठक से किनारा कर लिया।

मोदी ने कहा, कोरोना से प्रभावित होने वाले लोगों के मामले में भारत तमाम दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ब्रिटेन सरीखे देशों में संक्रमण फिर से उभरने का खतरा सामने आया है। पीएम ने कहा, कुछ अन्य कंपनियों की वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने वाली हैं। सरकार टीकाकरण को गति देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तीन घंटे तक चली बैठक में कोविड प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण भी दिया। इसके बाद सवालों का दौर शुरू हुआ और तमाम दलों की ओर से सुझाव भी दिए गए।

शिवेसना और तृणमूल कांग्रेस ने क्रमशः महाराष्ट्र व बंगाल में और अधिक टीकों की मांग की, जबकि बीजद सरीखे कुछ दलों ने कहा कि सरकार को घरेलू वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया तेज करनी चाहिए।

तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता एन. नागेश्वर राव ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण आबादी को बहुत प्रभावित किया है, ऐसे में सरकार को टीकाकरण अभियान तेज करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पीएम ने कोरोना से लड़ने के लिए अतिरिक्त सक्रियता-गंभीरता दिखाई है और इसका प्रमाण है उनके द्वारा 20 से ज्यादा बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी व सपा शामिल रहे। अकाली दल और वाम दलों ने बैठक में भाग नहीं लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उनकी पार्टी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नहीं कर रही है, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि सरकार को कोरोना को लेकर तथ्य संसद के दोनों सदनों के भीतर रखने चाहिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे।

# जज ने चीफ जस्टिस के खिलाफ ही जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ कलकत्ता हाईकोर्ट में अभूतपूर्व घटनाक्रम, केस ट्रांसफर किए जाने पर बिफरे जज

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और कोर्ट प्रशासन के खिलाफ ही आदेश पारित कर दिया। बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से नाराज न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा था कि मैं ऐसे सर्कस का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को खूब फटकार लगाई बल्कि बार-बार आ रही दिक्कतों के लिए शो काज नोटिस भी जारी कर दिया था।

दरअसल, 16 जुलाई को जिस मामले की सुनवाई करते हुए भट्टाचार्य ने तकनीकी गड़बड़ी को लेकर टिप्पणी की थी, उक्त मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दो न्यायाधीश की पीठ को हस्तांतरित कर दिया। इसे लेकर ही भट्टाचार्य ने बिंदल और कोर्ट प्रशासन के खिलाफ आदेश पारित किया है।

**आदेश में जज ने यह लिखा:** भट्टाचार्य ने सोमवार को पारित दस पेज के आदेश में कहा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस रोस्टर बनाने के अधिकारी होते हैं। वह कोर्ट का प्रशासन तय करते हैं, लेकिन कि क्या वह अपनी प्रशासनिक क्षमता के तहत रातों रात किसी मामले को दूसरी बेंच या जज को सौंप सकते हैं। चीफ जस्टिस मास्टर आफ रोस्टर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ मास्टर आफ आल नहीं हो सकता है। मेरे आदेश पर असिस्टेंट कोर्ट आफिसर ने रजिस्ट्रार जनरल को बताया है कि उनके पास यह ताकत नहीं है कि वह यह तय कर सके कि कौन सा केस किस बेंच को सौंपा जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'चुत्जपा' को शीर्ष संस्थानों में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पारदर्शीता का अभाव समस्याएं पैदा करता है। यह न्यायिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। चुत्जपा हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ धृष्टता या दुस्साहस होता है।

# हर तीन में से दो लोगों में मिली कोरोना की एंटीबाडी

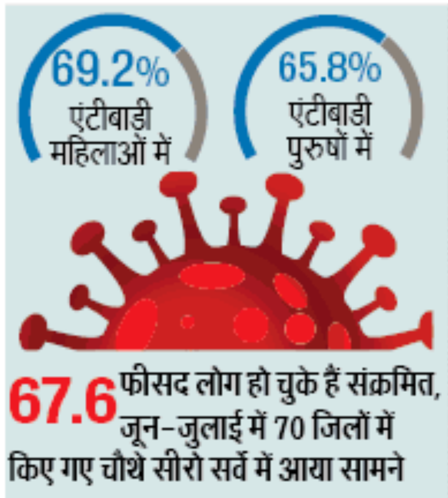
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में हर तीन में से दो व्यक्ति में कोरोना की एंटीबाडी बन चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के सीरो सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। सर्वे के अनुसार, अब भी देश में करीब 40 करोड़ यानी 33 फीसद ऐसे लोग हैं, जिनमें कोरोना की एंटीबाडी नहीं पाई गई है और इनके कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा है। इसको देखते हुए लोगों से गैरजरूरी यात्रा टालने व कोरोना से बचाव के नियमों के सख्ती से पालन की अपील की गई है।

आइसीएमआर के महानिदेशक डा. बलराम भार्गव ने बताया कि चौथा राष्ट्रीय सीरो सर्वे जून-जुलाई में 70 जिलों में कराया गया। इनमें 6-17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इसमें 67.6 फीसद में कोरोना की एंटीबाडी पाई गई। अर्थात देश की दो तिहाई आबादी सार्स-कोव-2 से संक्रमित हो चुकी है।

इससे पहले दिसंबर-जनवरी में कराए गए तीसरे सीरो सर्वे में 24.1 फीसद, अगस्त-सितंबर 2020 में हुए दूसरे सीरो सर्वे में 7.1 और मई-जून में किए गए पहले सीरो सर्वे में केवल 0.7 फीसद लोगों में कोरोना की एंटीबाडी पाई गई थी।

**हर्ड इम्युनिटी की दहलीज पर देश:** सामान्य तौर पर माना जाता है कि 70 फीसद आबादी में एंटीबाडी बनने के बाद समाज में संक्रमण के खिलाफ हर्ड इम्युनिटी यानी सामुदायिक प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। इस तरह भारत में हर्ड इम्युनिटी की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन देश की बड़ी आबादी को देखते हुए आइसीएमआर इसका का दावा करने से बच रहा है।




**67.6** फीसद लोग हो चुके हैं संक्रमित, जून-जुलाई में 70 जिलों में किए गए चौथे सीरो सर्वे में आया सामने

**सीरो सर्वे के नतीजे**

- शहरी इलाकों में रहने वाले 69.6 फीसद और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 66.7 फीसद में एंटीबाडी मिली
- छह से नौ साल के 57.2 फीसद और 10 से 17 साल के 61.6 फीसद बच्चों में भी पाई गई कोरोना की एंटीबाडी
- 18 से 44 साल के 66.7 फीसद, 45 से 60 साल के 77.6 फीसद और 60 साल से ऊपर के 76.7 फीसद में एंटीबाडी मिली

फिर साबित हुई टीके की अहमियत पेज>>6

## चेतावनी

**आइटी मंत्रालय की एजेंसी सीईआरटी ने जारी की चेतावनी, माइक्रोसाफ्ट से जुड़े उत्पादों को लेकर खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत, हजारों किलोमीटर दूरे बैठे साइबर अपराधी आपके कंप्यूटर से चुरा सकते हैं अहम सूचनाएं**

# आपके विंडो सिस्टम पर साइबर हमलावरों की नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगर आप माइक्रोसाफ्ट से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय से जुड़ी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विंडो सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। साइबर हमलावर आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर अहम सूचनाएं चुरा सकते हैं।

सीईआरटी के मुताबिक माइक्रोसाफ्ट विंडोज, माइक्रोसाफ्ट आफिस, एक्टेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (ईएसयू), डेवलपर्स टूल्स, एसक्यूएल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, माइक्रोसाफ्ट डायनेमिक्स, सिस्टम सेंटर और माइक्रोसाफ्ट एप्स हमलवारों के निशाने पर हैं। माइक्रोसाफ्ट विंडोज के माध्यम से हमलावर दूर से ही कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं।

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से इस प्रकार की चेतावनी जारी करने के बाद गत सोमवार को अमेरिका ने चीन पर माइक्रोसाफ्ट के एक्सचेंज को हैक करने का आरोप लगाया। हालांकि चीन ने अमेरिका के आरोप को गलत ठहराया है। इससे पहले भी सीईआरटी समय-समय पर मालवेयर संबंधी चेतावनी जारी करती रहती है। भारत में रैनसमवेयर हमले की चेतावनी भी पहले ही दी गई थी।



**भारत में 300 फीसद बढ़े साइबर हमले**

पिछले एक साल में भारत में साइबर हमले की संख्या में 300 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में आइटी मंत्रालय की एजेंसी सीईआरटी सभी प्रकार की साइबर आशंकाओं को लेकर समय-समय पर चेतावनी जारी करती रहती है।

**बिजली क्षेत्र को बचाने का अभ्यास**

सप्लाई चेन को साइबर हमले से बचाने के लिए सरकारी एजेंसी लगातार तैयारी कर रही है। पिछले सप्ताह बिजली क्षेत्र पर साइबर हमला होने की स्थिति से उबरने का अभ्यास किया गया। सीईआरटी के इस अभ्यास कार्यक्रम में नए आइटी मंत्री राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी हिस्सा लिया। इस अभ्यास सत्र का नाम साइबर शाक-2 दिया गया था। इस सत्र में हिस्सा लेने वाले विशेषज्ञों को बिजली क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक की स्थिति में साइबर अटैक को चिन्हित करने, उसे विफल करने और उसका मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

# नक्सलियों ने नौ ग्रामीणों को अगवा किया, छुड़ाने गए 25 लोग भी लापता

नईदुनिया, सुकमा

- 17 जुलाई को दो और 18 जुलाई को सात ग्रामीण किए गए अगवा
- गांव में पहुंची फोर्स को नहीं मिला एक भी पुरुष, महिलाओं ने नहीं दी कोई जानकारी
- सर्व आदिवासी समाज ने नक्सल संगठन से सभी को रिहा करने की अपील

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कुंदेड़ गांव के नौ लोगों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया। वहीं, इनको छुड़ाने गए गांव के पटेल और मुखिया समेत 25 लोग भी लापता हैं। इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने नक्सल संगठन से सभी को सकुशल रिहा करने की अपील की है।

सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनील शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई को दो और 18 जुलाई को सात लोगों को नक्सली अगवा कर अपने साथ ले गए। इसके अलावा 25 ग्रामीण नक्सलियों से वार्ता की बात कहकर गए हैं, जो अभी तक गांव नहीं लौटे हैं। इस सूचना के बाद फोर्स को गांव में भेजा गया लेकिन एक भी पुरुष नहीं मिला। खेतों में काम कर रही महिलाओं ने ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी। इसके बाद फोर्स लौट आई। सभी लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है।

**अगवा हुए हैं शिक्षादूत, सेल्समैन और छात्र :** सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने बताया कि नक्सलियों ने जिन लोगों को अगवा किया है, उनमें दो शिक्षादुत हैं। इसके अलावा एक सेल्समैन के साथ कुछ छात्रों को भी नक्सली अपने साथ लेकर गए हैं।

नेटवर्क नहीं इसलिए नहीं मिल रही जानकारी पेज>>5

## निजी कोचिंग संस्थानों को देना होगा 18 फीसद जीएसटी

नई दिल्ली, आइएएनएस : चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कास्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) की तैयारी कराने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को 18 फीसद जीएसटी देना होगा। केरल स्थित अपीलेट अथारिटी आन एडवांस रूलिंग (एएएआर) ने एएआर केरल द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए ऐसे संस्थानों को शिक्षण संस्थान मानने से इन्कार कर दिया है।

दरअसल, कोच्चि स्थित लाजिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने केरल एएआर द्वारा मई में दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी। फैसला देते हुए एएएआर ने कहा, अपीलकर्ता किसी तरह की प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। ना ही वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसे में उसे शिक्षा संस्थान नहीं माना जा सकता है। एएएआर ने स्पष्ट किया कि कालेजों, विवि द्वारा संचालित वाले डिग्री पाठ्यक्रमों को जीएसटी की छूट मिलती रहेगी।

**44** नए कोरोना मरीज मिले हैं मंगलवार को दिल्ली में। पांच मरीजों की मौत हो गई। 37 मरीज स्वस्थ हुए। मृत्यु दर 1.74 फीसद पर स्थिर रही। पिछले 24 घंटों में 63,019 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 0.07 फीसद सैंपल पाजिटिव मिले।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 21 जुलाई, 2021

# एक दशक से कागजों में ही बन-बिगड़ रहा ड्रेनेज मास्टर प्लान

**अव्यवस्था** ▶ 2009 में आइआइटी दिल्ली ने दी थी रिपोर्ट, 2019 में दिल्ली सरकार ने किया स्वीकार, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला

**2009 में तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने भी दिए थे निर्देश**

**2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी नए प्लान पर दिया था जोर**

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

इसे विडंबना ही कहेंगे कि देश की राजधानी एक दिन की जोरदार बारिश भी नहीं झेल पाती। नालों की सफाई न होने से सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं तो अंडरपास और सड़कों पर जलभराव हो जाता है। यह जलभराव न केवल हादसों, बल्कि दिल्लीवासियों की परेशानी का सबब भी बनता है। बावजूद इसके हैरत की बात यह है कि आज तक दिल्ली का अपना ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं बन सका है और एक दशक से भी अधिक समय से यह कागजों से जमीन पर उतरने का ही इंतजार कर रहा है।

आइआइटी दिल्ली ने राजधानी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिश भी की गई थी। 2009 में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने भी स्थानीय निकायों और अन्य सभी एजेंसियों से दिल्ली के वाटरशेड और ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा था। इसके बाद 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कहा कि जल निकासी मास्टर प्लान आखिरी बार 1976 में बना था, जबकि तेजी से बदलते शहर के विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए नई योजना तैयार की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक भी शहर का मास्टर प्लान अटका हुआ है, जबकि मध्यम स्तर की वर्षा में भी दिल्ली को बड़े पैमाने पर जलभराव का सामना करना पड़ रहा है।

**दिसंबर 2016 में ड्रेनेज मास्टर प्लान का ड्राफ्ट हुआ था तैयार :** खास बात यह कि आइआइटी के विशेषज्ञों की टीम ने दिसंबर 2016 में ड्रेनेज मास्टर प्लान का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया, जिसकी प्रमुख सिफारिशों में से एक दिल्ली के प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को बहाल करना थी। 2019 में दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जमीन पर शायद ही कुछ बदला हो। नालों का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रारंभिक कदम उठाए गए थे, लेकिन महामारी ने उनके क्रियान्वयन को रोक दिया। ऐसे में यह योजना, जिसे अंतिम रूप देने में तकरीबन एक दशक का समय लगा, अभी भी काफी हद तक कागजों पर ही अटकी हुई है।

**गायब हैं 18 बड़े प्राकृतिक नाले :** यमुना जिये अभियान के संयोजक मनोज मिश्रा ने बताया कि 1976 की जल निकासी योजना में चिह्नित किए गए 18 बड़े प्राकृतिक नाले गायब हैं। इस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए काफी समय, संसाधन व धन का उपयोग किया गया था, लेकिन इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसी एक एजेंसी को नालों के प्रबंधन और प्लान को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। प्लान में मानसूनी-जल निकासी प्रणाली को सीवेज व ठोस कचरे से मुक्त रहने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया था। अन्य प्रमुख सिफारिशों में सीवरेज सिस्टम व मानसूनी-पानी की नालियों को अलग करना, एकीकृत ढांचा, सतह से वर्षा जल को आसपास के पार्कों या जलाशयों में ले जाने के लिए पाइप बिछाना शामिल है। दिल्ली की बहु निकाय व्यवस्था और एक सामान्य ढांचा न होने से भी साल दर साल शहर की जल निकासी प्रबंध प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बाबत मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन महामारी ने इसे लागू करने में देरी की है।

## तीन ही दिन में खत्म हुआ सूखा, सामान्य से ज्यादा हुई बारिश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बीते 24 घंटों में ही 38.4 मिमी बारिश रिकार्ड हुई है, जो पिछले 11 वर्ष में एक दिन में सबसे अधिक है

▶ जुलाई में सामान्य बारिश 210.6 मिमी दर्ज की जाती है, जबकि मंगलवार तक हो चुकी है 315.5 मिमी

दिल्ली में इस बार मानसून देरी से भले ही सक्रिय हुआ हो, लेकिन तीन ही दिनों की बारिश ने दिल्ली का सूखा मिटा दिया है। 14, 19 और 20 जुलाई की बारिश ने जुलाई की सामान्य बारिश का आंकड़ा पार कर सरप्लस की स्थिति बना दी है। बारिश का यह दौर अभी जारी रहने का पूर्वानुमान है।

जुलाई में दिल्ली में सामान्यतः 210.6 मिमी बारिश होती है, जबकि मंगलवार रात साढ़े आठ बजे तक 315.5 मिमी हो चुकी थी। बीते 24 घंटों में ही 38.4 मिमी बारिश रिकार्ड हुई है, जो पिछले 11 वर्ष में एक दिन में सबसे अधिक बारिश है। मंगलवार सुबह साढ़े आठ से रात साढ़े आठ बजे तक भी 60.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। बुधवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा।

मंगलवार को भी सुबह से ही दिल्ली को बादलों ने घेर लिया था और तेज बारिश का दौर जारी था। इस वजह से सुबह के समय दफ्तर के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मौसम बदला और तेज धूप निकलने की वजह से वातावरण में उमस और गर्मी बढ़ गई। शाम होते-होते मौसम ने फिर करवट ली और शाम पांच बजे ही अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया और रुक-रुक कर देर शाम तक बारिश होती रही। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश का रिकार्ड 79.5 मिमी नजफगढ़ में रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 31.9 व न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 79 से 98 फीसद रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिन के समय धूप निकलने से उमस भरी गर्मी का अहसास हो सकता है। हालांकि, इससे तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा। अधिकतम 34 एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।



आइटीओ पर शाम को हुई बारिश के दौरान छाता लेकर जाते लोग। ध्रुव कुमार

## आज से 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए लाल किला बंद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों व सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार से लेकर 15 अगस्त तक लाल किला पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। इस बात की जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने दी है।

एएसआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला को पहले ही बंद कर दिया गया है। पहले एक अगस्त के आसपास लालकिला को बंद करते थे, लेकिन इस बार अभी से इसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के संसद घेराव के आह्वान को देखते हुए ऐसा किया गया है। लाल किला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना काल में पिछले वर्ष जिस प्रकार से समारोह का आयोजन हुआ था। कुछ ऐसी ही तैयारियां समारोह की इस बार भी हैं।

**15 जुलाई से बंद करने के मिले थे निर्देश**

एएसआई के अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें 15 जुलाई से पर्यटकों के लिए लाल किला बंद करने के निर्देश दिए थे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों व सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था। पुलिस से मिले निर्देशों को देखते हुए 21 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक लाल किला को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

## न्यूज गैलरी

### जल मंत्री ने 24 घंटे पानी आपूर्ति योजना का लिया जायजा

नई दिल्ली : दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में 24 घंटे पानी आपूर्ति करने की योजना की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने पानी की बर्बादी को रोकने और नागरिकों की सुविधाओं के लिए विभाग में सभी स्तरों पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय पर जोर दिया। उन्होंने पंपिंग स्टेशन से घरों में पानी आपूर्ति तक की तकनीक पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने और काम में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने शहर के जल निकायों और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। अधिकारियों को काम की गुणवत्ता को बेहतर करने को कहा। (राब्यू)

### 'बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत करने का प्रयास'

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के स्कूलों में आयोजित की जा रही विशेष पीटीएम के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुनापार के स्कूलों का दौरा कर अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई, उनके सामाजिक-भावनात्मक कल्याण और आनलाइन कक्षाओं को लेकर बात की। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों की भावनाएं व शिक्षा प्रभावित हुई है। अब पीटीएम के माध्यम से आनलाइन कक्षा और छात्रों की सामाजिक और मानसिक सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। (जासं)

### जामिया के शिक्षकों व छात्रों ने दानिश सिद्दीकी को किया याद

नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जामिया शिक्षकों एवं छात्रों ने फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को याद किया। शुक्रवार को अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष को कवर करते समय दानिश ने कंधार में जान गंवा दी थी। कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने दानिश को वास्तविक जीवन का नायक कहा। कहा कि हमें दानिश को हमेशा मुस्कान के साथ याद रखना चाहिए। शहीदों पर कभी आंसू नहीं बहाना चाहिए। घोषणा की कि जामिया में दानिश के फोटो की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दानिश की सहपाठी व सहायक प्रोफेसर सोनाली शर्मा ने यादें साझा कीं। (जासं)

## डेढ़ साल में आ गया दिल्ली दंगे का पहला फैसला, आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

**बड़ा मामला**

▶ टीवी की दुकान में डकैती, लूटपाट व दंगा करने का था आरोप

▶ पुलिस की कार्रवाई में रहीं खामियां, चश्मदीद नहीं कर सके थे शिनाख्त

▶ फरवरी, 2020 में दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की जान गई थी

दिल्ली दंगे में डेढ़ साल के भीतर आए पहले फैसले में आरोपित को बरी कर दिया गया, लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। आरोपित सुरेश उर्फ भटूरा पर दंगे के दो और मामले चल रहे हैं। फरवरी, 2020 में दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे।

मालूम हो कि इस मामले में नौ मार्च, 2021 को आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद लंबा ट्रायल चला। कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बाद आठ बार सुनवाई टाली गई। नौवीं तारीख पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अपने फैसले में कहा कि चश्मदीद गवाह आरोपित को पहचान नहीं सका। लिहाजा उसे बरी किया जाता है।

**यह था आरोप :** आरोप था कि सुरेश उर्फ भटूरा ने 25 फरवरी, 2020 की शाम बाबरपुर रोड स्थित एक टीवी की दुकान में लोहे की राड लेकर दंगाई भीड़ के साथ डकैती डाली। तोड़फोड़ भी की थी। दुकान भगत सिंह की थी, जिसे आसिफ ने किराये पर ली हुई थी। आसिफ की शिकायत पर 28 फरवरी, 2020 को केस दर्ज हुआ था। भगत सिंह चश्मदीद और बीट कांस्टेबल गवाह थे।

कोर्ट ने कहा, 25 फरवरी की शाम को वारदात के वक्त जब कांस्टेबल ने सुरेश को देखा था तो थाना पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं दर्ज किया गया। सात मार्च को पुलिसकर्मियों ने अपने अधिकारियों को बिना बताए सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुए डकैती के सामान को सील क्यों नहीं किया। यह आरोपित को बरी करने के लिए पर्याप्त आधार है। सुरेश का कहना था कि वह घोषित बदमाश है, इसलिए पुलिस ने उसे जबरन इस मामले में फंसाया।

**निशुल्क केस लड़ा**

यह दंगे का पहला केस है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील ने निशुल्क केस लड़ा और फैसला सुनाया गया। वकील राजीव प्रताप सिंह का कहना था कि पुलिस ने इस केस में सिर्फ सुरेश को गिरफ्तार किया है, जबकि दंगा कई लोग मिलकर करते है।

**इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा**

पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर सुरेश के खिलाफ 147 (दंगा करने), 143 (गैरकानूनी सभा का सदस्य होने), 427 (किसी को नुकसान पहुंचाने), 454 (संपत्ति में अनाधिकार प्रवेश) के अलावा 149 और 395 (डकैती) की धारा में केस दर्ज किया था।

## एम्स में बर्ड फ्लू से 11 वर्ष के बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती 11 वर्ष के बच्चे की बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) से मौत हो गई। बच्चा (एच5एन1) वायरस से संक्रमित था। देश में इस वर्ष बर्ड फ्लू से यह पहली मौत है।

जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम निवासी इस बच्चे को तबीयत खराब होने पर दो जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। बच्चा डी-5 वार्ड में भर्ती था। सोमवार को उसकी मौत हो गई। वायरस का पता लगाने के लिए एम्स ने सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनसे मंगलवार को एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई। डाक्टर ने बताया कि एच5एन1 वायरस खास तौर पर पक्षियों और मुर्गे-मुर्गियों में होता है। यह पक्षियों में बहुत तेजी से फैलता है और उनसे मनुष्य में भी फैल सकता है। इस वायरस की पहली बार पहचान 1996 में चीन में की गई थी। यह इस साल ऐसा पहला मामला है, जब किसी इंसान की मौत इस वायरस से हुई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में जनवरी माह में बर्ड फ्लू के कई मामले आए थे, तब लाल किले में 14 कौवे और संजय झील में चार बतख मरी मिली थीं। लैब में भेजे गए आठ नमूनों में सबकी रिपोर्ट पाजिटिव आई थी।

## उप्र में अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त जमीन की रजिस्ट्री

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1,334 हेक्टेयर जमीन की नियाल के नाम हुई रजिस्ट्री

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री के साथ प्रदेश में एक नया रिकार्ड बना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी एकमुश्त जमीन की रजिस्ट्री हुई है। नोएडा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (नियाल) इस जमीन को जल्द ही विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को निर्माण कार्य के लिए सौंप देगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए छह गांव रोही, पारोही, बनबारीवास, दयानतपुर, किशोरपुर, रन्हेरा की 1334 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की गई है। यह जमीन जिला प्रशासन ने नागरिक उड्डयन विभाग के नाम पर अधिगृहीत की थी। प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नियाल का गठन किया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने शनिवार को लखनऊ में 1334 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री नियाल के नाम पर कर दी। अधिकारियों का दावा है कि यह प्रदेश में एक मुश्त क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से जमीन की यह सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री पर 96 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क दिया गया है। जमीन की रजिस्ट्री से सबसे अधिक स्टांप शुल्क मिलने का रिकार्ड भी गौतमबुद्ध नगर के नाम पर दर्ज है। नोएडा में वेव समूह को सिटी सेंटर की जमीन की रजिस्ट्री के लिए करीब 365 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी दी गई थी।

**नजदीक है नोएडा एयरपोर्ट का शिलान्यास**

नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी औपचारिकताएं जिस तेजी से पूरी की जा रही हैं, उसके अनुसार नोएडा एयरपोर्ट का शिलान्यास करीब है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यमुना प्राधिकरण इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के चयन में जुटा है। प्राधिकरण ने कंपनियों से इसके लिए प्रस्ताव मांगे थे। इसमें प्रधानमंत्री की जनसभा के कार्यक्रमों का अनुभव होने की शर्त रखी गई है। 18 कंपनियों ने सोमवार व मंगलवार को प्राधिकरण में प्रस्तुतिकरण दिया है।

## दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य ने लगाया मंत्री पर प्रताड़ित करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य (ड्रेनेज) आरएस नेगी ने जल मंत्री सत्येंद्र जैन पर अपमानित व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप है कि मंत्री उन्हें आंतरिक बैठक में कनिष्ठ अधिकारियों के सामने अपमानित करते हैं। यही नहीं उन्हें गलत तरीके से पद से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

नेगी ने शिकायत में कहा है कि चयन समिति की सिफारिश व उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें अगस्त, 2017 में जल बोर्ड में सदस्य (ड्रेनेज) बनाया गया था। चयन समिति की सिफारिश पर चयनित होने वाले सदस्य की नियुक्ति सेवानिवृत्ति तक के लिए होती है, लेकिन उनके साथ यह नियम लागू नहीं किया जा रहा है। उन्हें समय से पहले ही पद से हटाया जा रहा है। इसे उन्होंने अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को परेशान करने वाला कदम बताया है। बोर्ड की आंतरिक बैठक में कनिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें बार-बार अपमानित किया जाता है। साथ ही उन्हें विभाग की समिति के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया है। उन्हें जानकारी दिए बिना ही पहले जनवरी में और अब 15 जून को सदस्य ड्रेनेज की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया है।

उन्होंने दावा किया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने जल बोर्ड में श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं। उनके प्रयास से सीवर लाइन का विस्तार हुआ है। कई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का काम भी पूरा हुआ है। यमुना को स्वच्छ बनाने की परियोजनाओं को लेकर मंत्री के साथ उनकी कुछ असहमति थी, लेकिन इस वजह से प्रताड़ित किया जाना गलत है। इस संबंध में जल मंत्री का पक्ष जानने के लिए उन्हें ईमेल व वाट्सएप से संदेश भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

## नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सचिव बर्खास्त

जागरण संवाददाता, नोएडा

▶ लीज बैक व रिटायर्ड कर्नल के साथ हुए विवाद में पहले हुए निलंबित

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टालरेंस नीति पर काम करते हुए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। 2008 में नोएडा प्राधिकरण में तैनात प्रशासनिक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। प्राधिकरण में तैनाती के दौरान तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र पर लीज बैक घोटाला करने का आरोप लगा था। सूत्रों के मुताबिक यह घोटाला करीब 3,800 करोड़ रुपये का था, जिसकी जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने शासन को प्रेषित की थी। इसके अलावा अगस्त 2018 में रिटायर्ड कर्नल के साथ हुए विवाद में भी तत्कालीन सचिव ने सुर्खियां बटोरी थी। उस दौरान वह मुजफ्फरनगर में बतौर एडीएम तैनात थे।

दरअसल, प्राधिकरण में लीज बैक करने के नाम पर वर्ष 2011 में हुए घोटाले में तीन लाख इक्यासी हजार वर्गमीटर से अधिक जमीन नियमों को दरकिनार कर बाहरी लोगों समेत तीन निजी कंपनियों के नाम कर दी गई। अंतर विभागीय जांच में पर्दाफाश हुआ था कि गांव के गैर निवासी व निजी कंपनियों को 175 वर्गमीटर से 15,340 वर्गमीटर के भूखंडों की लीज बैक की गई। एक्सप्रेस-वे पर शहदरा गांव के पास स्थित इस जमीन की कीमत बाजार दर के हिसाब से 3800 करोड़ रुपये आंकी गई थी। लीज बैक के नियमों का उल्लंघन कर जमीन दिए जाने के मामले में उस दौरान प्राधिकरण के नायब तहसीलदार मनोज कुमार को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया गया।

वहीं घोटाले को अंजाम देने के आरोप में तत्कालीन प्राधिकरण सचिव हरीश चंद्र और तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी (लैंड) अजय श्रीवास्तव को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति की गई थी।

> मामला संज्ञान में आया है। जब तक आफिशियल पत्र नहीं आता कुछ नहीं कहा जा सकता।
>
> -प्रवीण मिश्र, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण

**रिटायर्ड कर्नल को जेल भिजवाने के बाद हुआ निलंबन**

अगस्त 2018 में रिटायर्ड कर्नल को फर्जी मामले में जेल भिजवाना मुजफ्फरनगर के एडीएम हरीश चंद्र को भारी पड़ गया था। मामले में संज्ञान लेते हुए शासन ने एडीएम को निलंबित कर दिया था। इनके द्वारा किए गए सेक्टर-29 स्थित घर में अवैध निर्माण को भी ढहाया गया था। दरअसल, एडीएम हरीश चंद्र नोएडा के सेक्टर-29 में पहली मंजिल पर रहते थे। भूतल पर रिटायर्ड कर्नल वीएस चौहान रहते थे। एडीएम घर पर अवैध निर्माण करा रहे थे। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद था। 14 अगस्त को कर्नल के पार्क में टहलते वक्त एडीएम की पत्नी ने उन्हें गुंडा कह दिया था। कर्नल ने इसका विरोध जताया तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप लगा था कि एडीएम ने थाना सेक्टर-20 में कर्नल के खिलाफ पत्नी से छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के तहत न केवल मामला दर्ज करवाया, बल्कि पुलिस पर दबाव बनाकर उन्हें जेल भी भेजवा दिया था। कुछ दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद नोएडा में रह रहे हजारों भूतपूर्व सैन्यकर्मी कर्नल के बचाव में एकजुट हो गए। सैन्यकर्मियों के विरोध पर तत्कालीन एसएसपी ने उस समय के थाना सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी को पहले ट्रांसफर किया, फिर बाद में पद से हटा दिया। इतना ही नहीं दो दिन बाद नोएडा पुलिस ने कर्नल की शिकायत पर एडीएम, उनकी पत्नी व बेटे समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली।

## कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास के लिए मांगे प्रस्ताव

**निर्देश**

एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिर के सभी बारीदारों को प्रस्ताव पेश करने को कहा, अदालतों में लंबित मंदिर से जुड़े विभिन्न मामलों का रिकार्ड पेश करने का जिला न्यायाधीशों को दिया निर्देश

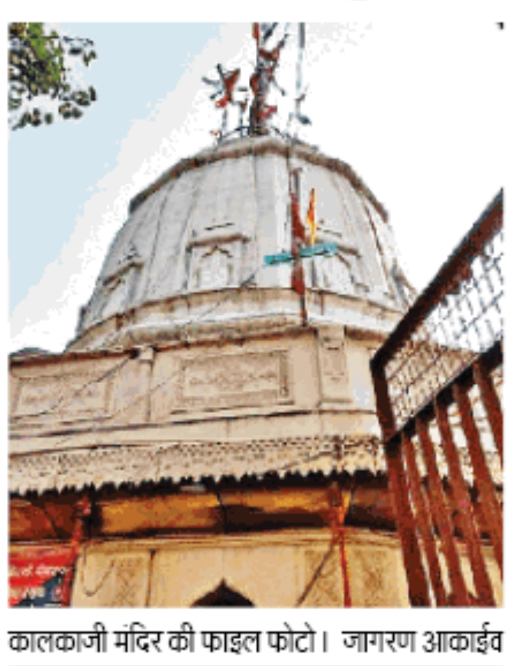
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

कालकाजी मंदिर परिसर की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे की असंतोषजनक स्थिति को लेकर गंभीर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। एक याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सफाई और पुनर्विकास को लेकर समय-समय पर कई निर्देश दिए हैं, लेकिन स्थानीय आयुक्त व कोर्ट रिसीवर की ताजा रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मंदिर की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

पूजा सेवा के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने की मांग को लेकर बारीदार बिशन स्वरूप की याचिका पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि त्योहार के समय लाखों भक्त मंदिर जाते हैं। इसके अलावा हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सफाई समेत अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सभी बारीदारों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने भी सफाई और पुनर्विकास के मुद्दे पर सहमति जताई है। ऐसे में मंदिर के सभी बारीदारों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं से पीठ ने कहा कि अगर उनके पास पुनर्विकास को लेकर कोई प्रस्ताव है तो दाखिल करें।

इसके अलावा पीठ ने सभी बारीदारों को अदालत में पेश होने के लिए कहा, ताकि एक प्रभावी आदेश पारित किया जा सके। पीठ ने निर्देश दिया कि बारीदारों की पूजा सेवा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब इस अदालत में होगी। पीठ ने सभी निचली अदालत के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि बारीदारों की पूजा सेवा से जुड़े सभी मामलों का इलेक्ट्रानिक रिकार्ड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजें।

पीठ ने कहा कि जहां तक धर्मशाला, तहबाजारी और दुकानदारों से जुड़े मामले का सवाल है इस संबंध में तीस हजारी और साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश एक रिपोर्ट पेश करें कि कहां कितने मामले लंबित हैं। मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।



कालकाजी मंदिर की फाइल फोटो। जागरण आकाईव

**तीन प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं**

- मंदिर परिसर के नवीनीकरण व पुनर्विकास के साथ आसपास नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता आदि का बंदोबस्त करना
- अधिकार, व्यवसाय और आवंटन के साथ दुकानदारों, तहबाजारी धारकों और धर्मशालाओं से राजस्व वसूली के तरीकों पर मतभेद।
- बारीदारों और पूजा सेवा अधिकारों के संबंध में उत्पन्न होने वाला कानूनी मामले, खासतौर पर महिलाओं के पूजा सेवा संचालन का अधिकार

## खान चाचा रेस्तरां का पंजीकरण निलंबित करने पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन कान्संट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में खान चाचा व टाउन हाल रेस्तरां के पंजीकरण को निलंबित करने के आदेश को चुनौती देने वाली नवनीत कालरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश लेने को कहा है। रेस्तरां के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लेने पर अफसरों पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, आप लोगों को अदालत आने के लिए मजबूर करते हैं। आपको एक आदेश पारित कर देना चाहिए था। पीठ ने सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

नवनीत कालरा ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) द्वारा 11 मई को जारी किए आदेश को चुनौती दी है। कालरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने नौ जून को जवाब प्रस्तुत किया था और इसके बाद से अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि कालरा ने 17 जून को उन्हें फिर से लिखा, लेकिन आज तक उन्होंने न तो निलंबन वापस लिया और न ही कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लिया। उन्होंने दलील दी कि निलंबन दिल्ली ईटिंग हाउस पंजीकरण विनियमों के प्रविधानों के खिलाफ है, क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के स्तर पर निलंबन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। उन्होंने कहा केवल प्राथमिकी दर्ज करने के आधार पर पंजीकरण को निलंबित करने का कोई प्रविधान नहीं है। दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने मामले में निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की।

**47.18** फीसद ज्यादा रही जून में घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की तादाद मई की तुलना में। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मुताबिक, बीते माह घरेलू मार्गों पर हवाई सेवा देने वाली एयरलाइंस का कुल पैसेंजर लोड 31.13 लाख हो गया, जो मई में 19.84 लाख था।



# कांग्रेस कोमा में, आरोपों का प्रभावी जवाब दें भाजपा सांसद : पीएम मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से विपक्ष के कोरोना महामारी के प्रबंधन में गुमराह करने वाले आरोपों का सक्रियता से जवाब देने के लिए कहा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पार्टी कोमा में चली गई है और भाजपा के सत्ता में आने को पचा पाने में असमर्थ है।

भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अत्यंत गैरजिम्मेदाराना व्यवहार दिखा रहा है। महामारी से निपटने में अपनी सरकार पर विपक्ष के हमले पर मोदी ने कहा कि कोविड-19 संकट राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय मुद्दा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भूखा नहीं रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सुचारु रूप से चले। समाचार एजेंसी एएनआइ


नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी। साथ में गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य नेता। प्रेट्र

के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से लोगों के सामने सरकार के काम की सच्चाई और तथ्य पेश करने को कहा ताकि विपक्ष का झूठ लोगों के सामने आ सके।

**प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के रवैये पर चिंता जताई :** बैठक का ब्योरा साझा करते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस के रवैये पर चिंता जताई। कांग्रेस अभी तक यह विश्वास करती है कि सत्ता में रहने का अधिकार केवल उसके पास है। करीब 100 साल बाद दुनिया महामारी की स्थिति का सामना कर रही है। पहले ऐसी स्थिति में लोगों को अन्न संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसबार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भूखे पेट नहीं सोए।

## राज्यों ने ही केंद्र को दिए हैं कोरोना महामारी से मौत के आंकड़े

**संसद में सरकार**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना काल में मौत के आंकड़े छिपाने, आक्सीजन की कमी से मौत जैसे कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी आंकड़े राज्यों की ओर से ही केंद्र को भेजे जाते हैं। अचरज की बात तो यह है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को यह नहीं बताया कि किसी मरीज की मौत आक्सीजन की कमी से हुई है।

मंगलवार को राज्यसभा में कोरोना पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजनीति से बचने की सलाह देते हुए कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मौत के जो आंकड़े आए वो राज्यों की ओर से ही आए। केंद्र तीसरी लहर से भी बचाव की पूरी तैयारी में जुटा है। 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया है, जिससे सभी राज्यों में जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएगी। इसका पूरा खाका तैयार हो गया है।

राज्यसभा में चली चार घंटे की बैठक की शुरुआत विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने सरकार को कोरोना से जुड़े प्रबंधन पर पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री समस्याएं सुलझाने में विफल रहे हैं। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया। बता दें कि हाल ही में कैबिनेट विस्तार में स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन की छुट्टी कर दी गई थी। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने सरकार पर कोरोना से जुड़ी मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप भी लगाया। शिवसेना सासंद संजय राउत ने भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार से कोरोना से हुए मौतों की जानकारी मांगी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि देश वैक्सीन के उत्पादन में काफी समय से शीर्ष पर है। इसलिए कोई इसका श्रेय न ले।

> मनसुख मांडविया के इस व्यापक भाषण में कोविड-19 से संबंधित कई पहलुओं को व्यावहारिक और संवेदनशील तरीके से शामिल किया गया है। मैं आप सभी से उनकी टिप्पणियों को सुनने का अनुरोध करता हूं।
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने विपक्ष के मौत के आंकड़े छिपाने के आरोपों का कड़ा जवाब दिया और कहा कि मौत से जुड़ी जो जानकारी केंद्र के पास आती हैं, वह राज्यों की ओर से ही मुहैया कराई जाती हैं। हमनें किसी भी राज्य सरकार को मौत की जानकारी छिपाने के लिए नहीं कहा। बल्कि राज्यों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि कोरोना से हुई कोई मौत दर्ज नहीं हुई तो उसे दोबारा दर्ज करा सकते हैं।

**दूसरी लहर में चरम पर पहुंची आक्सीजन की मांग :** स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने माना कि दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के वक्त आक्सीजन की मांग बहुत बढ़ गई थी। केंद्र ने हर राज्यों को पर्याप्त आक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश की। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रदेश ने केंद्र को यह नहीं बताया कि किसी की मौत आक्सीजन की कमी से हुई। इस पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री ने सदन को गुमराह किया है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे।

# विपक्ष के जासूसी के आरोपों पर भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा

### राज्य स्तर पर विपक्ष की स्तरहीन राजनीति को बेनकाब करने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद सत्र के ठीक पहले पेगासस स्पाइवेयर से जासूसी के आरोप लगाकर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति को सरकार ने साजिश का हिस्सा करार दिया है। पूरे देश में भाजपा ने इसे विपक्ष की साजिश के रूप में प्रचारित करने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को डेढ़ दर्जन से ज्यादा राज्यों के भाजपा मुख्यमंत्रियों और जहां राज्य सरकारें नहीं हैं वहां के नेता विपक्ष या बड़े नेताओं ने प्रेसवार्ता की और कहा कि जिस तरह यह विवाद ठीक संसद सत्र के पहले उठाया गया है उससे साफ है कि सरकार के कामकाज को रोकने का यह षड्यंत्र है। ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्रोनोलाजी समझने की बात कही थी।

केंद्रीय स्तर पर विपक्ष के आरोपों का करार जवाब देने के बाद मंगलवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कांफ्रेंस की। जिन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है, वहां सदन में भाजपा के नेता विपक्ष ने प्रेस कांफ्रेंस की। उनका कहना था कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि विकास की गति को अवरुद्ध किया जा सके।

अपने-अपने राज्यों में भाजपा मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष की नकारात्मक और स्तरहीन राजनीति को देश के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि पेगासस मामले में सिर्फ एक डाटा में मिले मोबाइल नंबरों का हवाला देकर जासूसी का हौवा खड़ा किया गया जबकि डाटा में मिले मोबाइल नंबर का पेगासस स्पाइवेयर के जरिये जासूसी किए जाने का कोई सुबूत नहीं है। पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी इन आरोपों को पहले ही निराधार बता चुकी है। आरोप लगाया जा रहा है कि पेगासस स्पाइवेयर वाट्सएप के माध्यम से किसी भी मोबाइल में घुसकर पूरा डाटा चुरा लेता है।

बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उस समय वाट्सएप की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि पेगासस स्पाइवेयर उसके सुरक्षा तंत्र को भेदने में सक्षम नहीं है।

मुख्यमंत्रियों ने कहा कि आरोप में कहीं यह नहीं बताया गया है कि जासूसी किस तरह से की गई और किसने की। सिर्फ झूठे आरोप लगाकर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है।

## अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में शामिल है विपक्ष : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पेगासस जासूसी मामले को लेकर जारी हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में शामिल बताया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल देश में जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह उनकी कुत्सित भावना का ही परिचायक है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही है, आज विपक्ष में रहकर अपने उन्हीं मंसूबों के अनुसार आगे बढ़ रही है।

विपक्ष के हंगामे के कारण संसद सत्र स्थगित होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की सनसनीखेज चीजों को परोसकर समाज में एक विषाक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह राजनीति के गिरते हुए स्तर का परिचय देता है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कुछ महत्वपूर्ण होना होता है, यह विपक्षी दल दुनिया में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कुत्सित कोशिश में लग जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने और भारत को अस्थिर करने के जिन मंसूबों के साथ विपक्ष काम कर रहा है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के माध्यम से भारत को अस्थिर व अस्त-व्यस्त करने की यह कोई पहली घटना नहीं है। योगी ने कहा कि संसद एक मंच है बात रखने का, लेकिन अगर इसे शोरगुल का मंच बना लिया जाए तो यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराने की परंपरा रही है। इस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े अनेक ऐसे सदस्यों को स्थान मिला है, जिन्हें आजादी के बाद कभी नेतृत्व का मौका नहीं मिला था। आज जब उस तबके को प्रधानमंत्री ने मौका दिया तो विपक्ष को यह सब रास नहीं आ रहा है। इस घटना के लिए विपक्ष को जनता और देश से माफी मांगनी चाहिए।


पेगासस मामले को लेकर उप्र के मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर तीखा हमला

# कुमारस्वामी की सरकार गिराने में जासूसी का सहारा लिया : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- खड़गे ने जताई आशंका, मप्र समेत कई अन्य राज्यों में फोन जासूसी के जरिये सरकारें गिराई गई होंगी
- कांग्रेस का दावा कुमारस्वामी, सिद्धारमैया व परमेश्वरन के निजी सचिवों के फोन की जासूसी की गई

पेगासस फोन जासूसी विवाद का सियासी दायरा बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस ने कर्नाटक की जेडीएस-कांग्रेस की गठबंधन सरकार गिराने के लिए केंद्र सरकार पर पेगासस साफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जेडीएस-कांग्रेस सरकार के पतन से पहले इनके शीर्ष नेताओं के सचिवों के फोन की पेगासस के जरिये निगरानी किए जाने की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की यह हरकत, लोकतंत्र के अपहरण जैसी है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह भी आशंका जाहिर की है कि भाजपा ने मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में जासूसी के जरिए वहां की सरकारें गिराई होंगी।

कर्नाटक में 2019 में सत्ता परिवर्तन की उठापटक के समय सूबे के कांग्रेस और जेडीएस नेतृत्व के करीबी लोगों के फोन पेगासस के सर्विलांस पर होने की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, कर्नाटक में नेता विपक्ष सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने इस प्रेस कांफ्रेंस में सवाल उठाया कि कुमारस्वामी की सरकार गिराने में पेगासस साफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद क्या गृहमंत्री अमित शाह को पद पर रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है, कि मोदी सरकार ने आपरेशन कमल के जरिए लोकतंत्र का अपहरण और प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। जासूसी कांड को उठाने की क्रोनोलाजी समझने के गृहमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि इसकी क्रोनोलाजी यह है कि कर्नाटक की चुनी हुई कांग्रेस-जेडीएस सरकार को खरीद फरोख्त के जरिए गिराने के लिए पेगासस साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से सरकार संसद में बहस से बच रही है। पेगासस फोन जासूसी कांड पर आई नई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक में 2019 के राजनीतिक उथल पुथल के समय जेडीएस नेता मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, कांग्रेस नेता उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिवों के फोन नंबरों को कथित तौर पर निगरानी के लक्ष्य के रूप में चुना गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशंका जताई कि केवल कर्नाटक ही नहीं कई राज्यों में पेगासस साफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सरकारें गिराई गई होंगी। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को जासूसी तंत्र में बदल रही है और पीएम मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह चुनाव जीतने के बाद भी दूसरे दलों की सरकारें गिराने के लिए जासूसी का सहारा ले रहे हैं। कर्नाटक के फोन जासूसी विवाद पर प्रेस कांफ्रेंस से पहले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर लंबी बातचीत की। हालांकि यह बैठक जासूसी प्रकरण से ज्यादा कर्नाटक में मुख्यमंत्री येद्युरप्पा को बदले जाने को लेकर भाजपा में चल रही अंदरूनी हलचल को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूबे में भाजपा की अंदरूनी उठापटक पर कांग्रेस की करीबी निगाह है और हाईकमान भी सूबे के नेताओं के साथ भविष्य की सियासी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है।


पेगासस फोन जासूसी विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर मंगलवार को राज्यसभा में सरकार को घेरने का प्रयास करते नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एएनआइ

# राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं रोहिंग्या घुसपैठिए

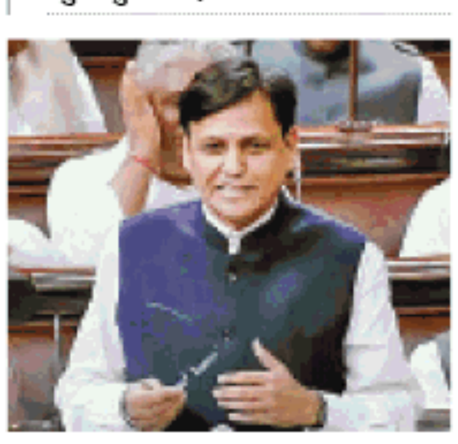
नई दिल्ली, प्रेट्र : रोहिंग्या घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा कर रहे हैं और रिपोर्ट है कि उनमें से कुछ गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रितेश पांडे के सवाल के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी।

गृह राज्यमंत्री ने कहा, 'शरणार्थी (रोहिंग्या समेत) राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा कर रहे हैं। कुछ रोहिंग्या घुसपैठियों के गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने की रिपोर्ट मिली है।' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या को भारत से डिपोर्ट नहीं करने का अनुरोध करते हुए एक रिट याचिका दाखिल कराई गई है। उन्होंने कहा, 'यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, अदालत ने रोहिंग्या को वापस भेजे जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है।'

नित्यानंद ने कहा कि भारत ने शरणार्थियों की हैसियत संबंधी 1951 के संयुक्त राष्ट्र समझौते और 1967 प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल नहीं है। शरण लेने वाले समेत सभी विदेशी नागरिक विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 और नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए प्रविधानों और नियम एवं आदेश द्वारा प्रशासित हैं। बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश करने वाले और जिनके दस्तावेज की अवधि समाप्त हो गई है, वे घुसपैठिए हैं।

**लोकसभा प्रश्नोत्तर**

- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं कुछ घुसपैठिए


नित्यानंद राय फाइल फोटो/इंटरनेट मीडिया

### म्यांमार के लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं देगा मिजोरम

एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में नित्यानंद ने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा से म्यांमार के कुछ नागरिकों के भारत में प्रवेश करने की रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि मिजोरम सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन्हें काम देने का फैसला लिया है। यह सवाल पूछा गया था कि क्या मिजोरम सरकार ने हाल ही में भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों को मनरेगा के तहत काम देने का फैसला लिया है?

### अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा जाति आधारित गणना नहीं

नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया कि सरकार ने जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त जाति के अनुसार जनसंख्या की गणना नहीं कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि संविधान के प्रविधान के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं में अजा और जजा के लिए सीट आरक्षित की गई हैं। यह उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार है।

### सीएपीएफ में डाक्टरों के 525 पद रिक्त

एक लिखित सवाल का उत्तर देते हुए नित्यानंद ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में डाक्टरों के 525 पद रिक्त हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल अधिकारी चयन बोर्ड (एमओएसबी) के माध्यम से स्पेशलिस्ट और जेनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारी की नियमित तौर पर नियुक्ति की जा रही है।

### उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना में 80 लोगों की मौत

नित्यानंद राय ने एक लिखित सवाल का उत्तर देते हुए लोकसभा को बताया कि सात फरवरी को उत्तराखंड में ऋषिगंगा नदी में हुए भूस्खलन के बाद करीब 80 शव मिल चुके हैं और 204 लोग लापता हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद भूस्खलन हुआ था।

### स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए 40,000 करोड़ मंजूर

भाजपा सदस्य दिलीप सैकिया और रमेश चंदर कौशिक के लिखित सवाल का उत्तर देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र ने कोविड-19 की रोकथाम और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटित कोष के अतिरिक्त है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने लक्षद्वीप के लोगों को पेश आ रही कठिनाइयों से संबंधित एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र शासित लक्षद्वीप के लोगों की समस्याओं की पहचान एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर उसके समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

# अगले सप्ताह भारत आएंगे अफगान सेना के प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : अफगान सेना के प्रमुख जनरल वली मुहम्मद अहमदजई 27 जुलाई से तीन दिनों की भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेशी सेना की वापसी के बीच पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के आक्रामक रुख अख्तियार करने को देखते हुए वह द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने की संभावनाएं तलाशेंगे। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जनरल अहमदजई अपने समकक्ष जनरल एमएम नरवने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों से विस्तृत बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, 'अफगान सेना प्रमुख तीन दिनों के दौरे पर 27 को भारत पहुंचने वाले हैं। वह 30 जुलाई को स्वदेश वापस लौटेंगे। इस दौरे का मुख्य जोर रक्षा सहयोग मजबूत करने पर होगा।' एक मई से अमेरिकी सेना की वापसी शुरू होने के बाद से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तालिबान ने बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू कर दी है। इस स्थिति को देखते हुए अफगानिस्तान अपने सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख सहयोगियों से संपर्क कर समर्थन जुटा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने अफगानिस्तान को पांच सैन्य हेलीकाप्टर मुहैया कराए हैं। अफगानिस्तान अपनी हवाई ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

अफगानिस्तान ने सोवियत काल के हेलीकाप्टरों और ट्रांसपोर्ट विमानों को संचालन में लाने के लिए भारत से सहायता मांगी है। ये हेलीकाप्टर और विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं हैं। मास्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध के कारण अफगानिस्तान विमान और हेलीकाप्टरों के स्पेयर पार्ट्स जुटाने के लिए भी हाथ-पांव मार रहा है।


जनरल वली मुहम्मद अहमदजई। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

**अच्छी पहल**

अक्टूबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था प्रस्ताव, ताकि अपने परिवार के साथ ज्यादा रह सकें जवान, इससे न केवल उनका तनाव घटेगा, बल्कि आत्महत्या जैसी घटनाओं को भी रोका जा सकेगा

# 100 दिन के अवकाश पर मंत्रालय ने जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों के जवानों को कम से कम 100 दिन का अवकाश देने का प्रस्ताव किया था ताकि जवान अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिता सकें। गृह मंत्री के इस प्रस्ताव पर मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने पूछा है कि उस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की दिशा में साफ्टवेयर तैयार करने को लेकर क्या प्रगति हुई।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अक्टूबर 2019 में शाह ने इस तरह का प्रस्ताव रखा था ताकि दूरदराज, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों को अधिक से अधिक आराम मिल सके। कहा गया कि अगर इस प्रस्ताव को लागू किया गया तो जवानों में प्रसन्नता का संचार होगा, उनका तनाव दूर होगा और उनमें आत्महत्या जैसी घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। बता दें कि अभी जवानों को 75 दिन का अवकाश मिलता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव को पूरी तरह लागू किया जाना बाकी है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बलों से जवानों की तैनाती और उनके स्थानांतरण को लेकर इस संबंध में साफ्टवेयर तैयार करने की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उनकी रोटेशन के आधार पर पोस्टिंग की जा सकेगी।

बता दें कि केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों अथवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में दस लाख से अधिक जवान हैं जो असम राइफल्स के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ तथा एसएसबी में तैनात हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा बल (आइटीबीपी) तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने इस संबंध में अपने-अपने साफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स में साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।

गृह मंत्री के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा के लिए जल्द ही मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की जाएगी और संबंधित साफ्टवेयर के काम करने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। इस तरह का भी विचार है कि तैनाती वाले स्थानों में ऐसी सुविधा विकसित की जाए ताकि जवान के परिवार वाले वहां कुछ दिन गुजार सकें। इससे भी जवानों में तनाव घटाने में मदद मिलेगी।


गृह मंत्री के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा के लिए जल्द ही होगी बैठक। फाइल/इंटरनेट मीडिया

## अटल, आडवाणी के पास रहा कमरा नड्डा को मिला

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को संसद में कमरा आवंटित हो गया है। यह कमरा कभी पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पास रह चुका है। कमरा नंबर चार, भाजपा संसदीय दल के कार्यालय के बगल में है।

वाजपेयी को यह कमरा एनडीए अध्यक्ष के रूप में मिला था। 2007 के बाद, जब वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी तब यह आडवाणी को आवंटित कर दिया गया। 2014 में भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, आडवाणी की नेमप्लेट इस कमरे से हटा दी गई, क्योंकि एनडीए ने कोई अध्यक्ष नहीं चुना था। प्लेट को बाद में बहाल कर दिया गया था। चूंकि आडवाणी ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए पिछले दो वर्षों से कमरे का उपयोग नहीं किया जा रहा था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को पार्टी के दो अन्य नेताओं के साथ कमरे में आए। कमरे के बाहर लगीं अटल, आडवाणी नेमप्लेट हटा दी गईं।

**कह के रहेंगे** माधव जोशी



**27** अगस्त को होगी ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित ओडिशा प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। यह परीक्षा बालेश्वर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में आयोजित होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 21 जुलाई, 2021

# सिद्धू ने नहीं मांगा समय, माफी मांगने तक नहीं मिलूंगा : कैप्टन

## तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने की अमरिंदर के साथ मुलाकात

### कैप्टन से मुद्दे सुलझाने के बाद ही मुझसे मिलें सिद्धू : मोहिंदरा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है। कैप्टन ने स्पष्ट कहा कि सिद्धू ने उनसे मिलने के लिए समय नहीं मांगा है। उन्होंने दोहराया कि उस समय तक सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक वह अपने ट्वीट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते।

मंगलवार को एक बार फिर तीन वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ब्रह्म मोहिंदरा, ओपी सोनी और विजय इंदर सिंगला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले कैबिनेट में नंबर दो का दर्जा रखने वाले ब्रह्म मोहिंदरा भी कैप्टन के रास्ते पर ही आगे बढ़े। उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत तो किया लेकिन साथ ही कहा कि जब तक सिद्धू कैप्टन के साथ अपने मुद्दों को नहीं सुलझा लेते तब तक वह (मोहिंदरा) सिद्धू से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कैप्टन कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। कैप्टन का साथ देना उनका कर्तव्य है। इसलिए जब तक सिद्धू व कैप्टन के बीच मुद्दों का समाधान नहीं होता तब वह नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से परहेज करेंगे।


कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल/इंटरनेट मीडिया

उल्लेखनीय है कि सिद्धू अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अभी तक कैप्टन से नहीं मिले हैं। वह चार दिन से राज्य में लगातार मंत्रियों व विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि वह बड़ा दिल दिखाते हुए सिद्धू की ओर से किए गए ट्वीट को भूल जाएं, जैसा कि सुखपाल सिंह खैहरा के मामले में किया है। एक अन्य मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने भी कहा कि जब कैप्टन ने प्रताप सिंह बाजवा और खैहरा को माफ कर दिया तो सिद्धू के मामले में भी उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए।

## कैप्टन व सिद्धू में दूरियां मिटा सकते हैं पीके

**कांग्रेस का अंतर्कलह**

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

कांग्रेस हाईकमान ने भले ही फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन उसे चिंता है कि सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ कैसे चलें। दोनों नेताओं में चल रहे शक्ति प्रदर्शन से दो खेमों में बंट गई पार्टी को एक बनाए रखना बड़ी चुनौती है। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दोनों ध्रुवों की दूरियां घटाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रशांत किशोर कैप्टन के करीबी रहे हैं। पिछले चुनाव में प्रशांत ने ही अमरिंदर के लिए रणनीति बनाई थी। माना जाता है कि प्रशांत नवजोत सिंह सिद्धू के भी करीबी हैं। हाल ही में राहुल गांधी की अगुआई में जिस बैठक में सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया, उसमें प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में उनका यही सुझाव था कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपकर अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। उनका मानना था कि दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं।

हाईकमान पहले ही इस फार्मूले पर काम कर रहा था और आखिर उसने किया भी वही। लेकिन, सिद्धू को अध्यक्ष बनाते ही उनके व अमरिंदर के बीच खाई और बढ़ती नजर आ रही है। सिद्धू ने अभी तक न तो कैप्टन से मुलाकात की है और न ही कैप्टन ने उन्हें बधाई दी है। कैप्टन अड़े हुए हैं कि जब तक सिद्धू उनके व सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर माफी नहीं मांगते, वह उनसे नहीं मिलेंगे।

ऐसे में कांग्रेस हाईकमान अब दोनों को एक मंच पर लाने का जिम्मा पीके को सौंप सकता है। पिछले कुछ समय से हाईकमान में पीके की पैठ बढ़ी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों की रणनीति का जिम्मा सौंप सकती है। हाईकमान को इससे बेहतर और कोई 'मध्यस्थ' नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत दोनों नेताओं को करीब नहीं ला पाए।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर अपने प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर की सुनते हैं। पिछले दिनों जब वह कलह के निपटारे के लिए गठित कमेटी के साथ बैठक के लिए दिल्ली गए तो प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। सिद्धू की भी उनसे अच्छी बनती है। सिद्धू को कांग्रेस में लाने में भी उनका रोल रहा है। इसलिए पूरी संभावना है कि वह दोनों में सेतु का काम करें, दोनों नेताओं के दिलों की दूरियां मिटाने में अहम भूमिका निभाएं।

## आखिर कहां चूके कप्तान !

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में समीकरण बदलने लगे हैं। सिद्धू के बढ़ते काफिले में कैप्टन के करीबी रहे नेताओं के भी शामिल होना यह बताता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से भी चूक हुई है। कैप्टन के लिए अब वैसी स्थिति नहीं है जैसी 2015 में थी। उस समय प्रताप सिंह बाजवा के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान थी और उनकी पीठ पर राहुल गांधी का हाथ था, तो भी कैप्टन कमजोर नहीं पड़े। लेकिन इस बार सियासत का चक्र उलटा घूम गया है।

कैप्टन के सिपहसालार रहे तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सरकारिया, सुखजिंदर रंधावा ही आज उनसे दूर हो गए हैं। जब सिद्धू ने कैप्टन को पंजाब का और राहुल गांधी को अपना का कप्तान बताया था तो सबसे पहले बाजवा ने विरोध किया। कैप्टन इससे काफी खुश हुए और उन्होंने बाजवा से यहां तक कहा कि उन्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बाजवा तब कैप्टन के ट्रबल शूटर हुआ करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मंत्रियों के विभाग बदले जाने थे, तब बाजवा ने कैप्टन से पूछा कि क्या उनका भी विभाग बदला जा रहा है। कैप्टन के भरोसा देने के बावजूद अगले दिन ही उनसे हाउसिंग विभाग ले लिया गया। इससे बाजवा नाराज हो गए। उन्होंने कैप्टन को संदेश भेजा कि जिसने (सिद्धू) आपके खिलाफ बयान दिया उसको तो सजा मिली, लेकिन जो साथ था, उसे भी सजा मिली।

सुखबिंदर सिंह सरकारिया विधायकों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड के मुद्दे पर नाराज हुए। चर्चा यह भी है कि सरकारिया इससे भी नाराज थे कि कैप्टन ने खनन के लिए अलग निदेशालय बना दिया था। रंधावा बेअदबी कांड की धीमी चल रही जांच को लेकर खासे चिंतित थे। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ कैप्टन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, लेकिन उन्हें कांग्रेस सरकार और शिरोमणि अकाली दल के मिले होने के संकेत से चिंता थी। दूसरी तरफ, सुखबीर बादल कैप्टन से ज्यादा जाखड़ पर हमले बोल रहे थे। जाखड़ ने तो यहां तक कहा कि और कुछ नहीं तो ट्रांसपोर्ट पालिसी को लागू करवा दिया जाए।

## भाजपा के वोटरों को 'मूर्ख' कहने पर गरमाई गुजरात की सियासत

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं परेश धनाणी

गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनाणी ने भाजपा को वोट देने वालों को 'मूर्ख' कहा तो प्रदेश की राजनीति गरमा गई। भाजपा ने इसे मतदाताओं का अपमान बताते हुए कहा है कि धनाणी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस के राज में दाल-रोटी के भी लाले पड़ते थे।

रूपाणी ने कहा कि क्रूड का भाव बढ़ने के कारण पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़े हैं। गुजरात में कोरोना के तीन करोड़ टीके लग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में दाल-रोटी के भी लाले थे। कांग्रेस हमेशा जनता का अपमान करती रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता कांग्रेस को भलीभांति पहचान चुकी है। इसलिए अब भाजपा के पक्ष में ही मतदान करती है।

महंगाई के विरोध में अहमदाबाद में सोमवार को आयोजित कांग्रेस की जनचेतना रैली को संबोधित करते हुए धनाणी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के बढ़ते दामों के चलते गरीब व मध्यम वर्ग का जीना दुश्वार हो गया है। धनाणी ने कहा कि हमें पेट्रोल, डीजल सौ रुपये लीटर बेचो, लेकिन वर्षों से भाजपा को वोट देने वाले 'मूर्खों' को तो 50 रुपये लीटर दो।

धनाणी की इसी बात को भाजपा ने मुद्दा बना लिया। भाजपा के मीडिया प्रभारी यज्ञेश दवे ने कहा कि धनाणी व कांग्रेस नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मतदाता को 'मूर्ख' बताकर धनाणी ने गुजरात की जनता का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। उधर, कांग्रेस विधायक अमरीश डेर ने धनाणी का बचाव करते हुए कहा है कि कई भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि वोट देकर वे 'मूर्ख' बन गए। धनाणी उनकी ही बात कर रहे थे, लेकिन वे संदर्भ देना भूल गए।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मंगलवार को राज्य के विभिन्न शहरों में जनचेतना रैली व सभाओं का आयोजन किया। अहमदाबाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावडा व नेता विपक्ष परेश धनाणी सहित कई वरिष्ठ नेता पालडी स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से साइकिल लेकर निकले तथा लाल दरवाजा पहुंचे जहां एक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के दाम बढ़ने से दैनिक उपभोग की वस्तुओं के भी दाम आसमान पहुंच गए हैं।

## उत्तर प्रदेश कांग्रेस से निकाले गए पुराने नेताओं की घर वापसी शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र और नेकचंद्र का निष्कासन रद, पार्टी में वापस
- राजेंद्र सिंह सोलंकी की भी हो चुकी है वापसी

अनुशासनहीनता के आरोप में नवंबर, 2019 में कांग्रेस से निकाले गए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से निष्कासन रद किये जाने के बाद पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र और नेकचंद्र पांडेय मंगलवार को कांग्रेस में वापस आ गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित चौधरी ने गुलदस्ते देकर और पटका पहना कर दोनों पुराने सिपाहियों का पार्टी में वापस आने पर स्वागत किया। इन दोनों नेताओं के साथ ही निष्कासित किये गए राजेंद्र सिंह सोलंकी पिछले हफ्ते कांग्रेस में वापस हो चुके हैं।

पुराने नेताओं की वापसी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ आगमन से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रियंका ने लखनऊ में कांग्रेस के जिला/शहर अध्यक्षों, पूर्व विधायकों व सांसदों के साथ बैठक की थी, जिसमें पुराने नेताओं की टीस उभरी थी कि पार्टी के नए पदाधिकारी उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। प्रियंका ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनका सम्मान बरकरार रहेगा। उन्होंने कुछ पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया था। यह भी कहा था कि पुराने नेताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा।


प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे से जोड़ा जा रहा है पुराने नेताओं की घर वापसी को। फाइल

कांग्रेस ने अपने 10 वरिष्ठ नेताओं को नवंबर, 2019 में अनुशासनहीनता के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इन नेताओं ने 14 नवंबर, 2019 को पूर्व सांसद संतोष सिंह के आवास पर पार्टी की दिशा-दशा को लेकर बैठक की थी। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कांग्रेस ने संतोष सिंह, पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी व सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी सिराज मेहदी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, नेकचंद्र पांडेय व विनोद चौधरी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एसपी गोस्वामी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी और गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। इनमें से रामकृष्ण द्विवेदी का पिछले साल अप्रैल में निधन हो चुका है। निधन से कुछ दिन पहले मानवीय संवेदनाओं को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने उनका निष्कासन रद कर दिया था।

कांग्रेस में वापसी के बाद भूधर नारायण मिश्र ने कहा- 'कुछ गलतफहमियां थीं, जिनके कारण पार्टी से निकाले गए थे। मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस की नीतियों व नेतृत्व में मेरी आस्था है और रहेगी। दुर्भाग्य से पार्टी के रजिस्टर से मेरा नाम कट गया था, लेकिन दिल कांग्रेस में बसा था। पार्टी ने ससम्मान बुलाया तो मैं वापस आ गया।' उधर कांग्रेस से निष्कासित सिराज मेहदी और संतोष सिंह ने वापसी पर कहा कि पार्टी ने वापसी के लिए माफी मांगने की शर्त रखी थी जो उन्हें गंवारा नहीं है।

## योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चार-पांच नए चेहरे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- हाईकमान के साथ स्वतंत्र देव और बंसल का मंथन, बढ़ेगा कुछ का कद
- जितिन प्रसाद का एमएलसी बनना लगभग तय, दो-तीन दिन में घोषणा

योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब उसकी रूपरेखा तैयार है। केंद्र की तरह बड़े फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम है। सिर्फ चार-पांच नए चेहरे शामिल करने पर सहमति की चर्चा है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए मौजूदा मंत्रियों का कद काम के आधार पर घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

उप्र विधानसभा चुनाव की तैयारी सरकार और भाजपा संगठन को समन्वय के साथ करनी है। लिहाजा, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर हाईकमान से चर्चा करने के लिए सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली पहुंच गए। मंगलवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में सब कुछ तय कर लिया गया।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरह बड़े फेरबदल से पार्टी बचना चाहती है, क्योंकि चुनाव करीब ही है। अभी टीम योगी में मुख्यमंत्री सहित कुल 53 मंत्री हैं। इनमें 23 कैबिनेट, नौ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 21 राज्यमंत्री हैं। चूंकि मानक के अनुसार कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसलिए सात स्थान अभी खाली हैं। हालांकि सात की बजाए सिर्फ चार या पांच नए मंत्री बनाए जाने का विचार है। इनके साथ ही कामकाज के आकलन और क्षेत्रीय-जातीय संतुलन के आधार पर कुछ मंत्रियों का कद बढ़ाया-घटाया जा सकता है। यह विस्तार और बदलाव इसी सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है।

दिल्ली में विधान परिषद सदस्य के चार नामों पर भी मंथन हुआ। इनमें हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जाना लगभग तय है। एमएलसी के मनोनयन की घोषणा दो या तीन दिन में हो सकती है।

## मेरे समय में एनएसओ की सेवा नहीं ली महाराष्ट्र सरकार ने : फड़नवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- राज्य सरकार के प्रचार विभाग की टीम 2019 में गई थी इजरायल
- कृषि विकास के उद्देश्य से हुई थी अधिकारियों की वह यात्रा

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि उनके मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र सरकार ने कभी एनएसओ की सेवा नहीं ली। फड़नवीस ने यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत द्वारा सोमवार को पूछे गए सवालों के जवाब में कही।

फड़नवीस ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र सरकार ने एनएसओ की कोई सेवा नहीं ली। राज्य सरकार के प्रचार विभाग (डीजीआइपीआर) की एक टीम 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एवं नई सरकार बनने से पहले इजरायल गई जरूर थी। लेकिन यह टूर कृषि विकास के उद्देश्य से हुआ था।

पिछले कुछ दिनों से भारत में खबरें चल रही हैं कि इजरायल के पेगासस स्पाईवेयर के जरिये भारत में कुछ लोगों के मोबाइल फोन हैक किए गए। यह स्पाईवेयर (फोन हैक करनेवाला साफ्टवेयर) इजरायल का एनएसओ समूह बनाता है एवं कुछ सरकारों को इसका लाइसेंस आतंकियों एवं अपराधियों पर नजर रखने के लिए देता है।


देवेंद्र फड़नवीस ने दिया जवाब। फाइल

बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने पूछा था कि क्या पेगासस स्कैंडल फड़नवीस की सरकार के दौरान हुआ था? क्या मंत्रालय में बैठने वाला कोई आइपीएस अधिकारी इसके पीछे काम कर रहा था? डीजीआइपीआर के अधिकारी किसकी अनुमति से इजरायल गए थे? उन्होंने वहां कौन सी ट्रेनिंग ली? क्या यह पेगासस से संबंधित थी? सावंत का कहना था कि इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए।मंगलवार को पत्रकारों ने जब इन सवालों के संबंध में फड़नवीस से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एनएसओ के जरिये किसी व्यक्ति की जासूसी करवाए जाने से साफ इन्कार कर चुकी है। सभी को उस पर भरोसा करना चाहिए। फड़नवीस ने कहा कि हम देख रहे हैं कि एक-दो मीडिया समूह चीन से मिल रही फंडिंग के जरिये ऐसी अफवाहें फैलाने में लगे हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। विशेषकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

## बिहार-उप्र में फूलन देवी का शहादत दिवस मनाएगी वीआइपी

**राज्य ब्यूरो, पटना :** विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) 25 जुलाई को बिहार एवं उत्तर प्रदेश में फूलन देवी का शहादत दिवस मनाएगी। कार्यक्रम के दौरान पार्टी उत्तर प्रदेश के 18 प्रमंडलों में फूलन देवी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित करेगी। यह जानकारी वीआइपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने दी।

सहनी ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व वीरांगना फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त, 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शेखपुरा पुर्वा में एक मल्लाह के घर में हुआ था। गांव के कुछ विशेष वर्ग ने उन्हें प्रताड़ित किया, बावजूद इसके उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। संघर्ष करके संसद तक का सफर तय किया। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में निषाद समाज में अलख जगाने का काम किया। आज फूलन देवी जीवित होतीं तो उनकी और निषाद समाज की देश के राजनीति में एक अलग जगह होती।

## अदाणी एयरपोर्ट का मुख्यालय मुंबई से हटाने पर राजनीति गरमाई

**मुंबई, प्रेट्र:** अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) का मुख्यालय मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित करने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने फैसले की आलोचना करते हुए इस कदम को देश की आर्थिक राजधानी के महत्व को जानबूझकर कम करने का प्रयास बताया है। वहीं कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (एमआइएएल) और निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का मुख्यालय मुंबई में ही रहेगा। समूह के एयरपोर्ट का कारोबार संभालने वाली एएएचएल ने पिछले सप्ताह ही जीवीके समूह से एमआइएएल का प्रबंधन लिया है।

**विवाद**
- कांग्रेस बोली, जानबूझकर कम किया जा रहा आर्थिक राजधानी का महत्व
- कंपनी ने कहा, शहर में ही रहेगा एमआइएल और निर्माणाधीन नवी मुंबई एयरपोर्ट का हेड क्वार्टर

फैसले की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने मंगलवार को कहा, 'यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक संदेश है। एयरपोर्ट पर हुआ डांडिया नृत्य बहुत कुछ बताता है। मुंबई के महत्व को कम करने के लिए पिछले सात वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।' उन्होंने दावा किया कि इसी तरह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया था। सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी किसी उद्योग या उद्योगपति के बीच भेद नहीं किया। कई उद्योगपति महाराष्ट्र आए और राज्य का हिस्सा बन गए।

मुंबई एयरपोर्ट पहले आंध्र प्रदेश स्थित जीवीके कंपनी के पास था। कंपनी ने कभी भी अपना मुख्यालय आंध्र प्रदेश स्थानांतरित नहीं किया और ना ही एयरपोर्ट पर कुचिपुड़ी नृत्य का आयोजन किया। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश में चल रही महाविकास अघाड़ी की प्रमुख सहयोगी है।

## मुकुल को पीएसी का चेयरमैन बनाने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में सुवेंदु

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** नंदीग्राम से भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल राय को विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी इस हफ्ते दो मामले दर्ज करना चाहते हैं। मामला दर्ज करने से पहले वह संवैधानिक विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई भाजपा विधायकों से भी इसे लेकर चर्चा की है। दूसरी ओर सुवेंदु अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, सुवेंदु ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमरनाथ को दी गई चेतावनी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एसपी से कहा है कि आप ऐसा कुछ भी काम मत करो, जिसकी वजह से आपको जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग या फिर बारामूला में ड्यूटी के लिए भेज दिया जाए।

**मिशन 2024**

शहीद दिवस पर पहली बार दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात, उप्र और तमिलनाडु में भाषण का होगा प्रसारण, 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाने की रणनीति

## ममता के भाषण का विभिन्न राज्यों में प्रसारण

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) रणनीति बना रही है। इसके तहत टीएमसी 21 जुलाई को शहीद दिवस पर अपने सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम के जरिए अलग-अलग राज्यों में विभिन्न भाषाओं में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के भाषण का प्रसारण करके देशभर के लोगों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है।

टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनर्जी के भाषण को बंगाल में बड़े पर्दों पर प्रसारित किया जाएगा। पहली बार उनके भाषण का तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरे साल बिना भीड़ के वर्चुअल तरीके से ही लोगों को संबोधित करेंगी। दरअसल, टीएमसी 1993 में कोलकाता में युवा कांग्रेस की रैली में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों की याद में शहीद दिवस मनाती है।


ममता शहीद दिवस पर आज वर्चुअल तरीके से ही लोगों को संबोधित करेंगी। फाइल/इंटरनेट मीडिया

**गुजरात में पर्दे पर प्रसारित करने की योजना :** टीएमसी नेता ने बताया कि बंगाल में भाषण बांग्ला में प्रसारित किया जाएगा, जबकि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय भाषाओं में अनुवादित भाषण प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के गढ़ गुजरात में भी कई जिलों में बनर्जी के भाषण को बड़े पर्दे पर प्रसारित करने की योजना है और इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए पार्टी की ओर से गुजराती में पुस्तिका भी वितरित की गई है। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा के अभियान की कमान संभाली थी। अब गुजरात और अन्य राज्यों में दीदी का संदेश फैलाने की हमारी बारी है। पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कार्यक्रम की योजना है। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने हैं।

**अन्य राज्यों में टीएमसी की पहुंच बढ़ाने की कवायद :** मुख्यमंत्री के भतीजे सांसद और हाल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए अभिषेक बनर्जी ने भी अन्य राज्यों में टीएमसी की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया था। भाजपा से टीएमसी में लौटे मुकुल राय को देशभर में पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया है। इधर, अन्नाद्रमुक नेता जयललिता की तरह बनर्जी को 'अम्मा' बताते हुए चेन्नई में पोस्टर लगाए गए हैं। टीएमसी दक्षिणी राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले ममता ने खुद ही एलान किया कि वह 21 जुलाई के कार्यक्रम के बाद नई दिल्ली का दौरा करेंगी। जहां वह 'पुराने और नए मित्रों' से मुलाकात करेंगी। वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य शीर्ष विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं।

## भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, वामपंथी दलों को हम से हाथ मिलाना ही होगा : पार्थ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध करने वाली कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के व्यापक गठबंधन का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी आम चुनावों में प्रमुख भाजपा विरोधी ताकत होंगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

ममता नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में प्रभावशाली मंत्री चटर्जी ने कहा कि टीएमसी एक पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है, इसलिए इसमें वरिष्ठों और युवाओं का सही संतुलन हो सकता है। विधानसभा चुनावों में भाजपा पर जीत के बाद टीएमसी में वापसी करने के इच्छुक नेताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामले दर मामले फैसले किए जाएंगे, लेकिन कहा कि अगर टीएमसी को जीत नहीं मिलती तो क्या वे लौटना चाहते।


पार्थ ने कहा, ममता बनर्जी देश में सबसे भरोसेमंद, भाजपा विरोधी चेहरा हैं

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी देश में सबसे भरोसेमंद, भाजपा विरोधी चेहरा हैं। मेरी यह अपील है कि सभी भाजपा विरोधी ताकतों को एक साथ आना चाहिए। वाम और कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चटर्जी ने कहा कि ममता और तृणमूल 2024 में भाजपा विरोधी प्रमुख ताकत होंगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाल में लोकसभा सदस्य और बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाए जाने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है। मई में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के तुरंत बाद अभिषेक को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने अपनी यात्रा 1998 में शुरू की थी। अब हम पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। यह भविष्य को ध्यान में रखते हुए ...अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए किया जा रहा है जो आने वाले समय में कमान संभाल सके। चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद पार्टी को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए इस पीढ़ीगत बदलाव की देखरेख कर रही हैं।

# छोटे कलाकारों को लालच देकर उनकी अश्लील फिल्में बनाता था राज कुंद्रा

**कसा शिकंजा** ▸ विभिन्न एप एवं ओटीटी प्लेटफार्म पर किया जाता था फिल्मों का प्रदर्शन

### कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के पति को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

मुंबई पुलिस का कहना है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने आए छोटे कलाकारों को लालच देकर उनकी अश्लील फिल्में बनाता था। इन फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न एप एवं ओटीटी प्लेटफार्म पर किया जाता था। राज कुंद्रा एवं उसके एक सहयोगी रेयान थार्प को सोमवार की रात मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने दोनों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के विषय में पत्रकारों से बात करते हुए मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भरांबे ने कहा कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि छोटे कलाकारों को शार्ट फिल्मों एवं वेब सीरीज में काम देने के नाम पर बोल्ड सीन करने को कहा जाता था। जिसे बाद में उनकी मर्जी के बिना अश्लील फिल्मों में बदल दिया जाता था। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये इन फिल्मों का प्रसारण किया जाता था। मुंबई के मालवणी इलाके में एक एफआइआर दर्ज होने के बाद इस मामले में राज कुंद्रा से पहले नौ और लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें एक व्यक्ति उमेश कामत भी है, जो राज कुंद्रा की कंपनी वियान का भारत में काम देखता था। मोबाइल एप पर अश्लील फिल्में अपलोड करने का काम उमेश कामत ही करता था।


अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय ले जाया गया। प्रेट्र

पुलिस को कुंद्रा की कंपनी का संबंध लंदन स्थित एक और कंपनी केनरिन से भी होने का पता चला है। केनरिन हाटशाट्स नामक एप का संचालन करती थी, जिस पर सब्सक्रिप्शन के जरिये अश्लील सामग्री देखी जा सकती थी।

मुंबई पुलिस को पता चला है कि राज कुंद्रा ब्रिटेन में रहने वाले एक कारोबारी के साथ मिलकर अश्लील फिल्मों का काम कर रहा था। उक्त कारोबारी के साथ राज कुंद्रा की अश्लील फिल्मों के व्यवसाय को लेकर अक्सर चैट होती थी। उस व्यक्ति के साथ चैट में राज कुंद्रा इस बात का पूरा रिकार्ड रखता था कि वीडियो, लाइव रिकार्डिंग इत्यादि से कितना पैसा आ रहा है? इस वाट्सएप चैट में राज कुंद्रा उक्त कारोबारी से अश्लील वीडियो को लोकप्रिय करने के लिए मार्केटिंग कंपनियों की मदद लेने पर भी चर्चा करते पाया गया है। अश्लील वीडियो अपलोड करने के लिए भी ब्रिटेन के ही एक आइपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता था। माना जा रहा है कि इस चैट में सामने आई बातें आने वाले समय में मुंबई पुलिस के लिए बड़ा सुबूत बन सकती हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार मुंबई पुलिस इस प्रकरण में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भूमिका की भी जांच कर रही है। लेकिन अब तक उसे शिल्पा की भूमिका के सुबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने यह अपील भी जारी की है कि जिन कलाकारों का शोषण हुआ है, वे स्वयं पुलिस के पास आकर अपना बयान दर्ज कराएं, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। इस बीच एक टीवी चैनल पर एक माडल ने खुद सामने आकर आरोप लगाया है कि एक बार एक वीडियो चैट के दौरान राज कुंद्रा के सहयोगी उमेश कामत ने उसे कपड़े उतारकर आडिशन देने को कहा था। राज कुंद्रा पहले क्रिकेट सट्टेबाजी में भी दोषी पाया जा चुका है।

# कश्मीर में एक और पुलवामा जैसी साजिश नाकाम, 30 किलो की आइईडी बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में एक और पुलवामा दोहराने की साजिश को सजग सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। सोमवार देर शाम श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र टेंगपोरा बंड में 30 किलो की आइईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद की। श्रीनगर-बारामुला हाईवे से करीब 700 मीटर दूरी पर रखी आइईडी को सुरक्षाबलों ने मंगलवार को सुरक्षित जगह पर निष्क्रिय कर दिया है। इसके अलावा श्रीनगर में सेंट्रल जेल के पास पुलिस दल पर आतंकियों ने हमला किया। इस दौरान पुलिस दल बाल-बाल बच गया। जवाबी कार्रवाई पर आतंकी भाग गए।

जानकारी के अनुसार, सेना को बीती शाम अपने खुफिया तंत्र से पता चला था कि आतंकी टेंगपोरा बाईपास इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। वह कोई बड़ा आइईडी धमाका करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आइईडी भी तैयार कर ली है। देर शाम श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र टेंगपोरा बंड पर पुलिस ने सेना की 24 आरआर जवानों के साथ तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान हाईवे से करीब 700 मीटर की दूरी पर टेंगपोरा बंड पर छिपाई गई आइईडी को बरामद कर लिया। बम निरोधक दस्ते ने मंगलवार सुबह इसे सुरक्षित तरीके से नकारा बनाया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह आइईडी थी, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आतंकी इसे श्रीनगर-बारामुला हाईवे से गुजरने वाले सुरक्षाबलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। अगर वह अपने मकसद में कामयाब रहते तो घाटी में फिर 14 फरवरी 2019 जैसे पुलवामा आतंकी हमले जैसी घटना हो जाती। मंगलवार दोपहर बाद पुलिसकर्मियों का एक दल डाउन-टाउन में सेंट्रल जेल से कुछ ही दूरी पर सैदाकदल इलाके से गुजर रहा था। पुल के पास घात लगाए बैठे आतंकियों ने उनपर गोलियों की बौछार कर दी।

### आतंकी प्रशिक्षण लेने पाक जा रहे 14 युवक पकड़े

**राज्य ब्यूरो, श्रीनगर :** गुमराह होकर आतंकी बनने का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान जाने की फिराक में बैठे अनंतनाग के 14 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने मंगलवार को जिला पुलिस लाइन में एक समारोह के दौरान इन सभी युवकों को काउंसिलिंग के बाद उनके स्वजन के हवाले कर दिया। युवकों की पहचान गुप्त रखी गई है। अनंतनाग के एसएसपी इम्तियाज हुसैन मीर के मुताबिक, अनंतनाग जिले के ये सभी युवक 18-22 साल के हैं।

### यह जिहाद नहीं जहालत है

**राज्य ब्यूरो, श्रीनगर :** यह जिहाद नहीं, जहालत है। अगर माजिद को जिहाद के मायने पता होते तो आज उसके बच्चे यूं यतीम नहीं होते, उसकी बीबी बेवा नहीं होती। यह बात चक सदीक खान से चंद किलोमीटर दूरी पर बसे मेलीबाग (शोपियां) में एक बुजुर्ग ने माजिद के घर से बाहर निकलते हुए कही। माजिद गत रविवार की रात को चक सदीक खान में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों में शामिल है। दूसरा आतंकी 10 लाख का इनामी इश्फाक अहमद डार था, जो वर्ष 2017 से सुरक्षाबलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इश्फाक पुलिस की नौकरी छोड़ आतंकी बना था।

30 वर्षीय माजिद इकबाल बट इसी साल 25 मई को आतंकी बना था। आतंकी बनने से पूर्व वह लोड कैरियर चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका छह वर्षीय बेटा अयान माजिद और तीन साल की बेटी है। बुजुर्ग माता-पिता के अलावा उसका 13 साल का भाई और एक बहन भी है। उसके घर से लापता होने पर उसकी बीबी ने इंटरनेट मीडिया पर उससे लौटने की अपील की थी।

# संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच दूसरी बैठक भी बेनतीजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कृषि कानूनों के विरोध में संसद भवन के बाहर धरना देने के मसले पर दिल्ली पुलिस व संयुक्त किसान मोर्चा के बीच मंगलवार को दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। सिंघु बार्डर के निकट एक रिसोर्ट में हुई बैठक में संसद की जगह किसी अन्य जगह पर धरना देने व उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम करने के पुलिस के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी।

बैठक के बाद मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का आदि ने 22 जुलाई से दो सौ लोगों के जत्थे के साथ संसद के बाहर धरना देने की बात को दोहराया। हालांकि नेताओं ने यह भी कहा कि पुलिस के सुझावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि बुधवार तक कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस व संयुक्त मोर्चा के बीच पहली बैठक रविवार को हुई थी।

**तकरार बढ़ने की आशंका :** जिस तरह से दो बैठकों के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है और मोर्चा के नेता संसद के बाहर धरना-प्रदर्शन पर आमादा हैं, उससे तकरार बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में जमकर उपद्रव मचाया था।

## चौटाला की पगड़ी और टिकैत के परने में दिखा सियासत का 'हरा' रंग


हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (दाएं) व भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। जागरण

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद पहली बार आम जनता में पहुंचे इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला का अंदाज ही कुछ जुदा था। हरे रंग की पगड़ी पहने चौटाला जब पलवल और गाजीपुर बार्डर पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे तो हरा परना पहने भाकियू अध्यक्ष राकेश टिकैत ने उनकी अगुवानी की। दोनों के बीच काफी देर तक गुफ्तगू भी हुई। इस दौरान चौटाला की जुबां पर दिल का दर्द आ ही गया। पहली बार किसानों के बीच पहुंचे चौटाला ने कहा कि उन पर अपात्र लोगों को नौकरियां देने का इल्जाम गलत लगा था। उनकी टीस यहीं नहीं थमी। कहा, नौकरी पाने वाले तो तरक्की कर गए और नौकरी दिलाने वाला सजा पर सजा काटता रहा। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें 3200 बच्चों के घरों का चूल्हा आबाद रखने की सजा मिली है। इसका उन्हें कोई गम नहीं है। अबकी बार हमारी सरकार बनने पर हर पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए चाहे उन्हें फांसी पर लटकना पड़े। कोई वोट दे या न दे, इसकी हमें कतई भी चिंता नहीं होगी।

## किसान संगठनों से वार्ता का विकल्प हमेशा खुला है : तोमर

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** सरकार ने कहा है कि पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों के समाधान पर प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के साथ चर्चा के लिए वह हमेशा तैयार रहेगी। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित कई सवालों का लिखित जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के साथ मुद्दे का समाधान निकालने के लिए सरकार अब तक 11 बार बातचीत कर चुकी है।

कृषि मंत्री ने कहा, 'सरकार गंभीरता, संवेदनशीलता और सक्रियता से किसान यूनियनों के साथ मुद्दों का समाधान निकालने में जुटी है। विभिन्न दौर की वार्ता में सरकार ने लगातार किसान यूनियनों से कृषि कानूनों के प्रविधानों पर चर्चा करने का आग्रह किया है ताकि यदि किसी प्रविधान पर कोई आपत्ति है तो उसके समाधान की दिशा में प्रगति हो सके।' तोमर ने कहा कि लेकिन किसान यूनियन केवल कृषि कानूनों को रद करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'सरकार किसान यूनियनों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मुद्दों का समाधान के लिए दरवाजा खुला रखेगी।'

### आंदोलन की आड़ में अफीम की तस्करी, पूर्व सरपंच गिरफ्तार

**संवाद सहयोगी, फिरोजपुर :** कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसान दिल्ली की सरहद पर डेरा जमाए हुए हैं, वहीं आंदोलन की आड़ में कुछ लोग तस्करी करने में भी लगे हैं। ऐसा ही मामला थाना कुलगढ़ी में दर्ज किया गया है। इसमें किसानी के साथ आढ़त का काम करने वाले दो कार सवार तस्करों को दो किलो अफीम के साथ काबू किया गया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जिन कार सवारों को गिरफ्तार किया है उनमें एक गांव झोक नोध सिंह वाली का अकाली दल समर्थित पूर्व सरपंच प्रगट सिंह है। उसके साथ एक साथी भी पकड़ा गया। दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

# कोआपरेटिव से जुड़े संविधान संशोधन सही : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद से पारित 97वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को सुनाया गया फैसला सहकारिता क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित होगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के एक हिस्से को राज्य का विषय बताते हुए खारिज कर दिया गया है। जबकि 97वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया है।

मल्टी स्टेट कोआपरेटिव मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने और सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन आदि के बारे में नियमित करने का पूरा अधिकार रहेगा। लेकिन संविधान संशोधन से अनुच्छेद नौ (बी) को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों का अधिकार बताते हुए उन्हें राज्य के भीतर सहकारी संस्थाओं के गठन, समितियों के चुनाव कराने और अन्य प्रबंधन का हक दिया है। इसे राज्य का विषय बताते हुए संबंधित अनुच्छेद को रद कर दिया है। संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह संशोधन 15 फरवरी, 2012 से लागू भी हो गया था। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19 (1) (सी) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43 (बी) और भाग नौ (बी) को भी शामिल किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में 19 (1) सी और 43 (बी) को बरकरार रखते हुए संविधान संशोधन को कायम रखा है, जबकि नौ (बी) को हटा दिया गया है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला एक के मुकाबले दो के बहुमत से सुनाया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा, 'हमने सहकारी समितियों से संबंधित संविधान के भाग नौ (बी) को हटा दिया है, लेकिन संशोधन को बचा लिया गया है।' न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, 'न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने आंशिक असहमति वाला फैसला दिया है।' केंद्र ने 2013 में 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रविधानों को निष्प्रभावी करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सहकारी समितियों के संबंध में संसद कानून नहीं बना सकती।

## चीफ जस्टिस के घर से कैमरे हटाने को हाई कोर्ट गए पूर्व चीफ जस्टिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

**निजता की दी दुहाई**

- चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया चीफ जस्टिस के घर के सामने लगे कैमरों की रेंज से बाहर है याची का मकान
- कहा- नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को लेकर नीति तैयार की जाए।

कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एनके सोढ़ी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोठी के सामने लगे कैमरे को हटाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने कहा कि इन कैमरों की परिधि में याची का मकान नहीं आता है, क्योंकि उनकी रेंज 30 मीटर है। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि विस्तृत आदेश आने बाकी हैं।

जस्टिस सोढ़ी ने याचिका में बताया कि उनका मकान चीफ जस्टिस के मकान के सामने है। वहां लगे कैमरों के दायरे में उनका मकान भी आता है, जो सीधे तौर पर निजता के हनन का मामला है। उन्होंने 22 मार्च और 17 मई को मांगपत्र दाखिल करते हुए इन्हें हटाने की अपील की थी। दो बार मांगपत्र देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। उन्होंने अपील की कि चीफ जस्टिस के घर के बाहर खंभों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को हटाया जाए। इसके साथ ही नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को लेकर नीति तैयार की जाए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि चीफ जस्टिस की सुरक्षा में तैनात वाहनों के कारण उसके घर आने जाने में परेशानी हो रही है।

## दुनिया में बेहतर सस्ती एसी यात्रा के लिए 806 कोच तैयार करेगा रेलवे

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** दुनिया में सबसे सस्ती और बेहतरीन वातानुकूलित (एसी) यात्रा पेश करने के लिए रेलवे इस वित्त वर्ष में 806 वातानुकूलित थ्री-टीयर इकोनोमी क्लास कोच तैयार करेगा। वर्तमान में ऐसे 25 कोच संचालन में हैं। इनमें से 10 पश्चिम रेलवे में, सात उत्तर मध्य रेलवे, पांच उत्तर पश्चिम रेलवे और तीन उत्तर रेलवे में इस्तेमाल हो रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ये कोच सस्ते होंगे और इनका किराया वर्तमान एसी थ्री और गैर एसी स्लीपर क्लास के बीच होगा। अधिकारी ने कहा कि रेलवे की तीन कोच फैक्ट्रियों रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला, इंटिग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और मार्डन कोच फैक्ट्री रायबरेली से ऐसे कोच एक साथ तैयार किए जाएंगे। आरसीएफ द्वारा कोच की संकल्पना तैयार की गई और अक्टूबर 2020 में युद्धस्तर पर डिजाइन का काम शुरू किया गया। नए कोच ज्यादा यात्रियों को ढो सकेंगे, क्योंकि बर्थों की संख्या 72 से बढ़ाकर 83 की गई है। एक अधिकारी ने कहा, '2021-22 के अंत तक हमारे पास 806 एसी थ्री टीयर इकोनोमी क्लास कोच होंगे।

# नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला

नईदुनिया, नारायणपुर

छत्तीसगढ़ के जिला नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर आमदई घाट इलाके में मंगलवार सुबह नक्सलियों ने घात लगाकर आइटीबीपी की रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) पर हमला कर दिया। हालांकि आइटीबीपी जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग गए। मगर करीब एक घंटे चली मुठभेड़ में राजस्थान के करौली जिले के कोडिया गांव निवासी आइटीबीपी 45वीं बटालियन के जवान शिवनारायण मीणा शहीद हो गए, जबकि हिमाचल प्रदेश निवासी जवान केशवराम घायल हो गए। घायल जवान का उपचार नारायणपुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इस वारदात में नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप बाल-बाल बचे हैं।

जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर आमदई घाट नक्सल प्रभावित इलाका है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक चंदन कश्यप का इस इलाके में दौरे का कार्यक्रम था। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) तैनात की गई थी। सुबह करीब 11 बजे चंदन कश्यप का काफिला आमदई व शिवमंदिर के बीच के रास्ते से जैसे ही गुजरा घात लगाए नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवान संभल पाते इससे पहले ही जवान शिवनारायण मीणा गोली की चपेट में आ गए। वह मौके पर ही शहीद हो गए। गोलीबारी के दौरान पहाड़ी पर चढ़कर मोर्चा लेने के प्रयास में केशवराम के पैर में गोली लग गई।

बस्तर आइजी सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सलियों की गोलीबारी का जवाब जवानों ने बहादुरी से दिया। मौके पर करीब एक घंटे तक रह-रहकर फायरिंग होती रही। इसके बाद नक्सली भाग गए। घायल जवान की हालत सामान्य है। नक्सलियों की तलाश में अतिरिक्त फोर्स को रवाना किया गया है। एएसपी नीरज चंद्राकर ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। नक्सलियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है।

### नेटवर्क नहीं इसलिए नहीं मिल रही जानकारी

प्रथम पृष्ठ से आगे

जगरगुंडा से तीन किमी दूर स्थित कुंदेड़ गांव सात पारा (मोहल्लला) में बंटा है। सलवा जुडूम (नक्सलियों का एक आंदोलन) के समय इस गांव के अधिकांश लोग जगरगुंडा कैंप में रहने आ गए थे, लेकिन सलवा जुडूम बंद होने के बाद धीरे-धीरे लोग गांव चले गए। यह इलाका नक्सल प्रभावित है और यहां पर नेटवर्क नहीं है।

लिहाजा कोई जानकारी निकल कर बाहर नहीं आ रही है। यहां के लोग अक्सर नक्सली बैठकों में जाते हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल होगा कि इतने लोगों को नक्सलियों ने अगवा किया है या फिर बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया है।

**बंधक सलवा जुडूम कार्यकर्ता की हत्या :** नक्सलियों ने दो दिन पहले पदेड़ा के साप्ताहिक बाजार से अगवा किए गए सलवा जुडूम कार्यकर्ता वंजा गुट्टी (35) की हत्या कर दी। उसका शव मंगलवार सुबह पदेड़ा में सड़क किनारे जंगल से कोतवाली पुलिस ने बरामद किया। वंजा गुट्टी ने नक्सलियों के भय से 2013 में गांव छोड़ दिया और पत्नी कमला व दो बच्चों के साथ जिला मुख्यालय में बने राहत शिविर विजय नगर में रहने लगा था।

**अनूठी पहल**

# बकरीद से पहले गोदान, गो माता का सम्मान

**मुस्लिम बंधुओं ने हनुमान वाटिका मंदिर की गोशाला को दान की गाय, गोशाला संचालकों ने गाय का दूध पिलाकर किया का स्वागत**

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

राजधानी में रामलीला मैदान के साथ लगते हनुमान वाटिका मंदिर की गोशाला मंगलवार को ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। यहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के पदाधिकारियों ने विधि-विधान से गो दान किया। इससे पहले मंत्रोच्चार के साथ गाय की आरती कर रोली लगाई गई। बकरीद पर गाय की कुर्बानी की जगह उसे मां मानकर दान करने और उसका सम्मान करने के संदेश के साथ हुए कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने गोशाला की गायों को गुड़ और चारा खिलाया। इससे अभिभूत गोशाला के लोगों ने गाय का दूध पिलाकर सभी का स्वागत किया।

मंच के राष्ट्रीय संगठन संयोजक गिरीश जुआल, राष्ट्रीय संयोजक मुहम्मद अफजाल, गो प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय संयोजक मुहम्मद फैज खान के साथ गोशाला पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोशाला संचालक पंडित प्रमोद को गाय दान की। मुहम्मद फैज खान ने कहा कि पैगंबर हजरत मुहम्मद ने कहा है कि गाय का दूध शिफा (स्वास्थ्यवर्धक) है, गाय का घी दवा है और गाय का मांस बीमारी है। इसे देखते हुए मुस्लिम समाज को गाय की कुर्बानी देने के बजाय उसे मां के समान सम्मान देना चाहिए। यह देश की एकता व अखंडता के लिए भी आवश्यक है।


नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में बकरीद की पूर्व संध्या पर श्रीराम हनुमान वाटिका मंदिर गोशाला में गाय दान करने के बाद गायों को गुड़ एवं चारा खिलाते मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी। ध्रुव कुमार

### देशभर में दिख रही बदलाव की बयार

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस प्रयास का असर देश में दूसरी जगहों पर भी दिखा। सोमवार को ही अधिवक्ता सिराज कुरैशी के नेतृत्व में हैदराबाद में गो दान हुआ। उत्तर प्रदेश समेत देशभर में दस स्थानों पर भी गो दान कार्यक्रम किया गया है। बकरीद पर गुरुवार को देशभर में एक हजार से अधिक स्थानों पर गायों को गुड़-चना खिलाकर उनके प्रति प्रेम व सम्मान प्रदर्शित किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वर्षों से गायों के प्रति मुस्लिम समाज को जागरूक कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व एक राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें 11 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपे गए थे। गिरीश जुआल बताते हैं कि इससे प्रणब मुखर्जी काफी आशान्वित हुए थे। गो सेवक मुहम्मद फैज ने ढाई साल में 17 हजार किमी की पैदल यात्रा कर गाय के महत्व के बारे में जागरूक किया था। मेवात जैसे क्षेत्र में 15 हजार मुस्लिम गो पालकों का सम्मेलन भी इस मुहिम का मील का पत्थर रहा है।

## असमानता के खिलाफ लड़नी होगी लंबी लड़ाई



असमानता किसी भी समाज के लिए दंश है। इससे लड़ने की दिशा में सरकारें लगातार प्रयास भी कर रही हैं। हालांकि अब भी तस्वीर बहुत सुखद नहीं है। आक्सफैम इंडिया की ओर से जारी इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को लेकर चिंता बढ़ाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

### चिंता का अहम कारण

- सामान्य वर्ग की तुलना में एससी वर्ग के 12.6 फीसद ज्यादा बच्चों के शरीर का विकास औसत से धीमा
- समाज के 20 फीसद उच्च तबके की तुलना में 20 फीसद सबसे निचले तबके में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले तीन गुना

### कोरोना काल का संकट

**50%** से ज्यादा एससी एवं एसटी परिवारों को नान-कोविड मेडिकल सुविधाएं पाने में दिक्कत हुई

**18.2%** सामान्य वर्ग के परिवारों को इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा

### स्वास्थ्य व्यवस्था में पीछे

- स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 67.8% हिस्सा लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, जबकि वैश्विक औसत मात्र 18.2% है
- दो दशक में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं की उपलब्धता 31.2 फीसद से घटकर 8.9 फीसद पर पर आ गई
- सरकारी अस्पतालों में आउट-पेशेंट केयर में दवाओं की उपलब्धता 17.8 फीसद से घटकर 5.9 फीसद पर आई

इनपुट : प्रेट्र

दैनिक जागरण
बुधवार 21 जुलाई, 2021
www.jagran.com


# पहले प्राथमिक स्कूल खोले जाएं : आइसीएमआर

**सुझाव** ▸ भार्गव ने कहा– बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता कोरोना, शिक्षकों समेत स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य

## कई यूरोपीय देशों में कभी बंद नहीं हुए बच्चों के प्राथमिक स्कूल

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद भले ही कुछ राज्यों ने नौवीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को धीरे-धीरे खोलने का एलान किया हो, लेकिन आइसीएमआर ने उच्चतर शिक्षा के बजाय प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई पहले शुरू करने की सलाह दी है।

आइसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव चौथे सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है। उच्चतर कक्षाओं के बजाय प्राथमिक कक्षाओं को पहले शुरू करने की वैज्ञानिक वजह बताते हुए डाक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस जिस एस रिसेप्टर के सहारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़ता है, वह बच्चों में कम होता है।

इसीलिए संक्रमित होने के बावजूद बच्चों पर उसका प्रतिकूल असर कम दिखता है। उन्होंने कहा कि चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट से भी यह साबित होता है। उन्होंने कहा कि सीरो सर्वे में छह से नौ



बलराम भार्गव ने बताई संक्रमण। फाइल फोटो

साल के 57.2 फीसद बच्चों में और 10 से 17 साल के 61.7 फीसद बच्चों में कोरोना की एंटीबाडी पाई गई है, जो लगभग उतनी ही है, जितनी बिना वैक्सीन लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों मिली है। लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने वालों में 18 साल से कम उम्र वालों की संख्या नगण्य है।

डाक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर से लेकर तीसरी लहर तक यूरोप के कई देशों, जिसने स्कैंडिनेवियाई देश भी शामिल हैं, ने प्राथमिक स्कूलों को बंद नहीं किया और वहां लगातार कक्षाएं चलती रहीं। भारत में प्राथमिक कक्षाओं को पहले शुरू करने की सलाह देते हुए उन्होंने शिक्षकों समेत सभी स्टाफ को वैक्सीन का दोनों डोज अनिवार्य रूप से देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों और बच्चों को ले जाने वाली बसों में कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी।

## देश में 125 दिनों बाद मिले सबसे कम 30 हजार नए केस

**जेएनएन, नई दिल्ली**

केरल और पूर्वोत्तर को छोड़ दें तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पूरे देश में स्थिति सामान्य हो रही है। केरल में भी नए मामले 10 हजार से नीचे आ गए हैं। पूर्वोत्तर में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ज्यादा मामले आ रहे हैं। हालांकि, उन राज्यों में भी हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। पूरे देश की बात करें तो 125 दिनों बाद 30 हजार नए केस मिले हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में पहली बार 111 दिनों बाद सबसे कम 374 मौतें हुई हैं। 117 दिनों बाद सक्रिय मामले भी घटकर 4,06,130 रह गए हैं। इस दौरान सक्रिय मामलों में 15,535 की कमी आई है।

**गुजरात में बीएसएफ के 52 जवान संक्रमित** : गुजरात में दो हफ्ते के दौरान सीमा सुरक्षा बल के 52 जवानों को संक्रमित पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बनासकांठा जिले के पालनपुर स्थित बटालियन के 433 में से 52 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं।

▸ **बीते 24 घंटे में 111 दिन बाद सबसे कम 374 पीड़ितों की मौत**

**देश में कोरोना की स्थिति**

| | |
|---|---|
| 24 घंटे में नए मामले | 30,093 |
| कुल सक्रिय मामले | 4,06,130 |
| 24 घंटे में टीकाकरण | 52.56 लाख |
| कुल टीकाकरण | 41.18 करोड़ |



तीसरी लहर की चेतावनी के बीच गुजरात के अहमदाबाद में वैक्सीन लेता एक व्यक्ति। एएफपी

**मंगलवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति**

| | |
|---|---|
| नए मामले | 30,093 |
| कुल मामले | 3,11,74,322 |
| सक्रिय मामले | 4,06,130 |
| मौतें (24 घंटे में) | 374 |
| कुल मौतें | 4,14,482 |
| ठीक होने की दर | 97.37 फीसद |
| मृत्यु दर | 1.33 फीसद |
| पाजिटिविटी दर | 1.68 फीसद |
| सा. पाजिटिविटी दर | 2.06 फीसद |
| जांचें (सोमवार) | 17,92,336 |
| कुल जांचें (सोमवार) | 44,73,41,133 |

**मंगलवार शाम छह बजे तक किस राज्य में कितने टीके**

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 4.70 लाख |
| गुजरात | 3.95 लाख |
| महाराष्ट्र | 1.83 लाख |
| बिहार | 1.18 लाख |
| छत्तीसगढ़ | 1.16 लाख |
| हरियाणा | 0.82 लाख |
| हिमाचल | 0.74 लाख |
| राजस्थान | 0.72 लाख |
| दिल्ली | 0.71 लाख |
| उत्तराखंड | 0.70 लाख |
| जम्मू-कश्मीर | 0.44 लाख |

**अब तक वैक्सीन की 41 करोड़ 18 लाख डोज दी गई** : मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक वैक्सीन की 41.18 करोड़ डोज लाभार्थियों को दी जा चुकी हैं। केंद्र ने टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 42.15 करोड़ डोज उपलब्ध कराए हैं। इनमें से अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2.11 करोड़ डोज बची हुई हैं। जल्द ही इन्हें 71.40 लाख डोज और मुहैया करा दी जाएंगी।

## गुजरात में कोरोना का टीका नहीं लगाने पर दुकानदार गिरफ्तार

**राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद** : गुजरात के कच्छ में कोरोना का टीका नहीं लगाने पर एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने दुकानदारों और व्यवसाय करने वालों को 31 जुलाई तक टीका लगाने का आदेश जारी किया है। दूसरी तरफ, पुलिस कह रही है कि दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा था और ग्राहक शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे।

कांडला मरीन पुलिस थाने के कांस्टेबल उदेसिंह ठाकोर ने 17 जुलाई को गश्त के दौरान जनरल स्टोर चलाने वाले एक दुकानदार के खिलाफ सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के तहत आइपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि दुकानदार ने टीका नहीं लगवाया तथा मास्क के बिना दुकान पर बैठा था। जिलाधिकारी की अधिसूचना का हवाला देते हुए कांस्टेबल ने दुकानदार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस से इस संबंध में जवाब मांगा गया तो उसने बताया कि जिलाधिकारी की अधिसूचना के तहत मास्क नहीं लगाने व कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई।

**बीएसएफ कैंप में 50 से अधिक जवान संक्रमित** : नगालैंड से बीएसएफ कैंप में आए एक हजार बीएसएफ जवानों में से करीब साढ़े चार सौ का कोरोना टेस्ट किया गया। 52 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए।

## फिर साबित हुई टीके की अहमियत

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

सीरो सर्वे ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की अहमियत भी साबित कर दी है। इसके अनुसार जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उनमें से केवल 62.3 फीसद में ही कोरोना के खिलाफ एंटीबाडी पाई गई। जबकि वैक्सीन की एक डोज लेने वालों में से 81 फीसद में और दोनों डोज लेने वालों में से 89.9 फीसद में एंटीबाडी पाई गई।

**प्राथमिकता तय करने का मिला लाभ** : स्वास्थ्यकर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के बेहतर नतीजे भी सीरो सर्वे में देखने को मिला। सबसे पहले वैक्सीन लेने वाले स्वास्थ्यकर्मियों में से 85 फीसद में एंटीबाडी मिली, जबकि हकीकत यह है कि इनमें से 10.5 फीसद ने एक भी डोज नहीं और 13.4 फीसद ने केवल एक डोज ली है। 76.1 फीसद स्वास्थ्यकर्मी दोनों डोज ले चुके हैं।

**टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर** : नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्कफोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल ने कहा कि सीरो सर्वे की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि संक्रमण के अलावा टीकाकरण के माध्यम से भी कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्युनिटी विकसित की जा सकती है। उन्होंने आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार तेज होने का भरोसा देते हुए कहा कि जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक सभी को कोरोना के उचित व्यवहार के माध्यम से तीसरी लहर को रोकना होगा।

**कितने लोगों में हुआ सीरो सर्वे** : चौथा सीरो सर्वे भी उन्हीं 21 राज्यों के 70 जिलों कराया गया जहां पहले के तीनों सीरो सर्वे कराए गए थे। इनमें से हर जिले से 10 गांव या वार्ड में से 40-40 लोगों को चुना गया। इस तरह से हर जिलों से 400 लोगों के खून के नमूने में एंटीबाडी का परीक्षण किया गया। लेकिन पहली बार छह से नौ साल के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया।

**राज्यों को स्थानीय स्तर पर सीरो सर्वे कराने की सलाह** : डा. भार्गव ने कहा कि विभिन्न राज्यों के जिलों में संक्रमण की स्थिति अलग-अलग हैं। इसीलिए राज्यों को स्थानीय स्तर पर सीरो सर्वे कराकर कोरोना संक्रमण की सही स्थिति का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने की रणनीति बनाने की सलाह दी गई है।

## कोविड काल में आर्थिक मदद करेगी टीम फार ह्यूमैनिटी

**जेएनएन, नई दिल्ली** : कोविड से देश में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है, बच्चे अनाथ हुए हैं। परिवार के कमाऊ सदस्य की जान चली गई जिससे लोगों के सामने बड़े पैमाने पर घर चलाने का संकट आ खड़ा हुआ है।

ऐसे लोगों की मदद को धन एकत्र करने के लिए देश-दुनिया के खेल, मार्केटिंग व कारपोरेट समुदाय को साथ लाने की पहल 'टीम फार ह्यूमैनिटी' के तहत की गई है। इसके तहत एकत्र राशि कोविड के कारण कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को दी जाएगी। फंडरेजर 'गिव इंडिया' पर एक लिंक (https://fundraisers.giveindia.org/fundraisers/team-for-humanity) उपलब्ध कराया गया है जहां लोग आर्थिक योगदान कर सकते हैं। इससे बड़े नाम जुड़े हैं। लुइस हैमिल्टन, उसेन बोल्ट,स्पेनिश फुटबाल लीग ला लीगा, इंग्लिश फुटबाल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, जानसन एंड जानसन, टाइटन, स्पोटिफाइ, सोनी म्युजिक आदि आगे आए हैं।

## आक्सीजन की बर्बादी रोकेगा आइआइटी का खास उपकरण

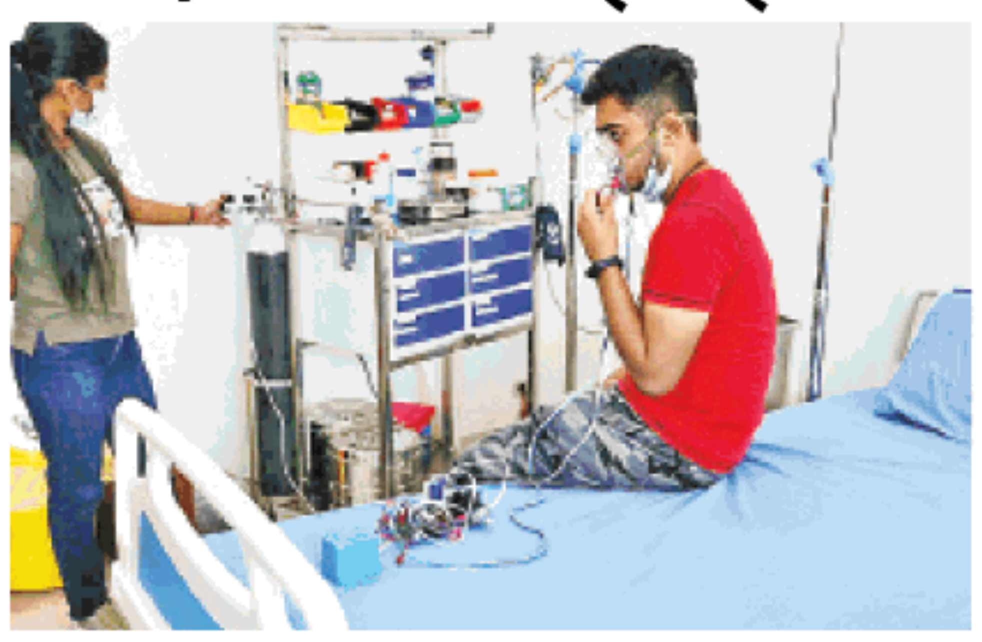
**जागरण संवाददाता, रूपनगर**

कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की मांग कई गुणा बढ़ गई है। संभावित तीसरी लहर के संकट का मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रोपड़ ने एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण 'एमलेक्स' विकसित किया है, जो सिलेंडर से आक्सीजन की बर्बादी को काफी हद तक रोक देगा।

आइआइटी रोपड़ में विकसित यह उपकरण रोगी को सांस लेने के दौरान आक्सीजन की आवश्यक मात्रा की ही आपूर्ति करता है। जब रोगी कार्बन डाइआक्साइड छोड़ता है तो यह उपकरण थोड़ी देर के लिए आक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। इससे आक्सीजन की काफी बचत होती है। यह उपकरण सिलेंडर की लाइफ को तीन गुणा तक बढ़ा देता है।

इस उपकरण को आइआइटी रोपड़ के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में तैनात डा. अशीष साहनी के नेतृत्व में पीएचडी के शोधार्थियों मोहित कुमार, रविंदर कुमार और अमनप्रीत चंद्र ने इजाद किया है।

गौरतलब है कि देश भर में महामारी



आइआइटी रोपड़ के वैज्ञानियों द्वारा तैयार किया गया एमलेक्स यंत्र को इस्तेमाल करके दिखाते हुए टीम के सदस्य। जागरण

से पहले लिक्विड मेडिकल आक्सीजन की मांग 700 टन प्रति दिन थी। पिछले साल पहली लहर में यह चार गुणा बढ़कर 2,800 टन प्रति दिन हो गई। दूसरी लहर में यह मांग सात गुणा से बढ़कर 5,000 टन प्रतिदिन तक पहुंच गई।

**कैसे होती थी बर्बादी, अब कैसे होगी बचत** : दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच), लुधियाना के शोध एवं विकास विभाग के डायरेक्टर के डा. जीएस वंडर ने बताते हैं कि सिलेंडर से आक्सीजन लेने वाले मरीज के मुंह पर मास्क लगा होता है, जिसमें छिद्र होते हैं। यह छिद्र प्रेशर कम करने के लिए होते हैं, लेकिन इन छिद्रों से उस समय आक्सीजन की बर्बादी होती है, जब मरीज सांस छोड़ता है। सांस लेने के मुकाबले सांस छोड़ने में दोगुना समय लगता है। ऐसे में सिलेंडर से लगातार आक्सीजन चलती रहती है और सांस छोड़ने के वक्त सिलेंडर से निकलने वाली आक्सीजन बर्बाद हो जाती है। एमलेक्स उपकरण मरीज के सांस छोड़ने के वक्त सिलेंडर की सप्लाई को रोक देता है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा उपकरण लगाने के बाद तीन घंटे चलने वाला आक्सीजन सिलेंडर नौ घंटे तक चल सकता है।

**सांस लेने व छोड़ने के साथ मेल करके काम करती है प्रणाली** : आइआइटी रोपड़ के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में तैनात डा. अशीष साहनी ने बताया कि यह प्रणाली आक्सीजन के प्रवाह को रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ मेल करके काम करती है। यह उपकरण दो इनपुट व आउटपुट कनेक्टर व आक्सीजन सप्लाई लाइन के बीच जुड़ सकता है। स्टैंडर्ड आकार के कनेक्टर से भी उपकरण आसानी से काम करता है। इसका प्रयोग पार्टेबल बिजली सप्लाई (बैटरी) के साथ-साथ लाइन सप्लाई (220 वोल्ट) से भी किया जा सकता है। आइआइटी रोपड़ के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव आहूजा ने कहा कि अपनी तकनीक को पेटेंट करवाने के बारे में सोचने का समय नहीं है। अभी कोरोना संक्रमण से निपटना जरूरी है।

# राष्ट्रीय फलक

## मैक्स सर्विसेज के शरद व मल्लिका की गिरफ्तारी पर बढ़ाई रोक

**जागरण संवाददाता, नैनीताल** : हाई कोर्ट ने हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक को दो सप्ताह और बढ़ाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र में अदालत से पूर्व के आदेश को रिकाल करने या वापस लेने का अनुरोध किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जांच में दोनों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों के आधार पर आइपीसी की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। इस अपराध में दोषी साबित होने पर सात साल से अधिक सजा का प्रावधान है। ऐसे में अब अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले का निर्णय इन पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से दो सप्ताह में आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में शरद पंत व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई।

## 29 हजार कार्ड सरहद पर सेना के जवानों का बढ़ाएंगे हौसला

**राज्य ब्यूरो, जम्मू**

▸ **गुजरात से एनसीसी कैडेट्स द्वारा भेजे गए कार्ड उत्तरी कमान पहुंचे**

▸ **कारगिल विजय दिवस पर ये कार्ड लद्दाख में तैनात जवानों को दिए जाएंगे**

कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के प्रति सम्मान जताने और वर्तमान में लद्दाख में सरहद पर डटे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गुजरात के एनसीसी कैडेट्स द्वारा भेजे गए 29,566 कार्ड उत्तरी कमान मुख्यालय ऊधमपुर पहुंच गए हैं। यह कार्ड कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भेजे गए हैं। इन्हें मंगलवार को सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय ऊधमपुर में कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने गुजरात एनसीसी निदेशालय के अधिकारियों से स्वीकार किए। वह सैनिकों के लिए कार्ड बनाकर भेजने वाले युवाओं की भावनाओं से खूब प्रभावित हुए हैं।

कारगिल के वीरों को गुजरात का आभार मुहिम के तहत ये कार्ड स्कूलों व कालेजों में पढ़ रहे एनसीसी कैडेट्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। यह कार्ड जब जवानों के हाथों में पहुंचेंगे तो उनका हौसला सातवें आसमान पर होगा। तीन जुलाई को शुरू हुई इस मुहिम को लंदन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड ने निष्ठा का प्रमाणपत्र दिया है। ये कार्ड 17 जुलाई को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अरविंद कपूर की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए थे। अब उत्तरी कमान से ये कार्ड लद्दाख में नियंत्रण रेखा व वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों तक पहुंचाएगी।

कार्ड भेजने वाले एनसीसी कैडेट्स के जज्बे की सराहना करते हुए वाईके जोशी ने कहा कि एक सच्चा सिपाही देशवासियों के प्यार की खातिर दुश्मनों से लड़ता है। वह तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। ये कार्ड सरहद पर तैनात जवानों के साथ उनके परिवारों का भी हौसला बढ़ाएंगे।

## अब पोस्टमैन की मदद से घर बैठे आधार कार्ड का फोन नंबर अपडेट कराएं

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : आधार कार्ड में त्रुटियों को ठीक कराने की प्रक्रिया और आसान होने जा रही है। अब आप घर बैठे पोस्टमैन की मदद से अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकेंगे। बता दें कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आधार अपडेट करते समय ओटीपी मोबाइल नंबर पर ही आता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने इस तरह की व्यवस्था की है ताकि आधार कार्ड धारक अपने मोबाइल नंबर को पोस्टमैन के माध्यम से अपडेट करा सकें। यह सेवा पूरे देश में स्थापित 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नेटवर्क में कार्य कर रहे 1.46 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के माध्यम से उपलब्ध होगी।

आइपीपीबी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जे वेंकटरामु ने एक बयान में बताया कि इससे दूरदराज इलाकों तक हमारी पहुंच बढ़ेगी और डिजिटल डिवाइड की खाई को कम किया जा सकेगा।

## अनुग्रह राशि की गाइड लाइन तय करने को मांगा और समय

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोरोना से मौत के मामले में अनुग्रह राशि की गाइड लाइन तय करने के लिए चार सप्ताह का और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया है।

कोर्ट ने गत 30 जून को कोरोना से मौत पर परिजनों को अनुग्रह राशि या मुआवजा पाने के हक पर मुहर लगाते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) को निर्देश दिया था कि वह छह सप्ताह के भीतर डीएमए एक्ट की धारा 12(3) के मुताबिक कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि या मुआवजा देने के बारे में गाइड लाइन तय करे।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में गाइड लाइन तय करने के लिए चार सप्ताह का समय और दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा दिये जाने के बारे में गाइड लाइन तय करने पर एनडीएमए में विचार विमर्श चल रहा है। सक्रिय रूप से प्रक्रिया जारी है और काफी आगे बढ़ चुकी है। गाइड लाइन को अंतिम रूप देने से पहले मामले पर कुछ और गहराई से परीक्षण करने की जरूरत है। जल्दबाजी में गाइड लाइन तय करने से अनपेक्षित नतीजा हो सकता है। सरकार ने कहा है कि इसे देखते हुए कोर्ट छह सप्ताह का दिया गया वक्त चार सप्ताह के लिए और बढ़ा दे ताकि एनडीएमए एक समग्र नीति बना सके। सुप्रीम कोर्ट ने गत 30 जून को कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा या अनुगृह राशि दिए जाने के बारे में दिए फैसले में कहा था कि न्यूनतम राहत की गाइड लाइन तय करना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) का विधायी कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में गाइड लाइन न जारी करना एनडीएमए का अपने विधायी कर्तव्य निर्वहन में नाकाम रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को आदेश दिया था कि वह छह सप्ताह के भीतर कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि देने के बारे में न्यूनतम राहत की गाइड लाइन जारी करे।

## तीलू रौतेली पुरस्कार में शामिल होंगी कोरोना योद्धा

**राज्य ब्यूरो, देहरादून** : वीरबाला तीलू रौतेली के नाम पर वर्ष 2006 से प्रारंभ किए गए तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार में इस बार कोरोना योद्धा के तौर पर कार्य करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। आठ अगस्त को दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए प्रदेश के सभी जिलों से अब तक 120 महिलाओं व किशोरियों के आवेदन आए हैं।

महिला सशक्तीकरण के तहत समाज सेवा, खेल, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं व किशोरियों को प्रदेश सरकार हर साल पुरस्कृत करती है। पहली बार इस पुरस्कार में कोरोना योद्धा भी शामिल किए गए हैं। यानी, कोरोनाकाल में बतौर कोरोना योद्धा उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को भी यह पुरस्कार मिलेगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए आए आवेदनों का परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार के तहत अभी तक 21 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इस बार पुरस्कार की राशि दस हजार और बढ़ाई जा सकती है।

## बुद्धिजीवियों के फोरम ने की उप्र के कोविड मैनेजमेंट की सराहना

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ**

▸ **राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का विरोध करने वालों को दिखाया आईना**

बुद्धिजीवियों के फोरम ने योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की सराहना की है। राष्ट्र विरोधी ताकतों और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध करने वालों को आईना भी दिखाया है।

फोरम आफ कन्सर्न्ड सिटिजन के बैनर तले 151 रिटायर्ड आइएएस अफसरों और जजों के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी पत्र में कहा गया है कि योगी सरकार ने जिस तरह से उप्र में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया, वह पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए की किस तरह कोविड के दौरान योगी सरकार ने 40 लाख प्रवासियों के भरण पोषण की व्यवस्था की। उनके इलाज के साथ ही उन्हें घर पहुंचाने का भी इंतजाम किया।

राज्यसभा के पूर्व महासचिव व उप्र के मुख्य सचिव रहे योगेंद्र नारायण के नेतृत्व में राष्ट्र विरोधी ताकतों और अपराधियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर सवाल करने वालों को फोरम ने आड़े हाथों लिया है। यह कहते हुए कि ऐसे लोगों को योगी सरकार बनने से पहले और बाद की एनसीआरबी रिपोर्ट देखनी चाहिए। फोरम ने उस आरोप को भी खारिज किया है, जिसमें कहा गया है कि उप्र सरकार पुलिस मुठभेड़ के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। कुछ पूर्व नौकरशाह राजनीतिक कारणों से सरकार पर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं।

## कल्याण सिंह की हालत नाजुक, देखने पहुंचीं राज्यपाल

**जागरण संवाददाता, लखनऊ** : उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (लखनऊ) में भर्ती प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल जाना। एसजीपीजीआइ के डाक्टरों के अनुसार शनिवार से पूर्व सीएम की तबीयत चिंताजनक बनी है। उन्हें अभी भी आइसीयू में आक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सोमवार की रात उनकी तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद से परिवार के लोग अस्पताल में डटे हैं। हालांकि मंगलवार को कई जांचों के बाद डाक्टरों ने उनके शरीर के सभी रासायनिक पैरामीटर आंशिक नियंत्रित होने की बात कही है। एसजीपीजीआइ के निदेशक प्रो. डा. आरके धीमन ने बताया कि दो-तीन दिनों से पूर्व सीएम का बीपी अनियंत्रित हो रहा था। यूरिन संक्रमण व अन्य इन्फेक्शन भी थे।

## हस्तिनापुर के हर टीले में दफन है इतिहास

**जागरण संवाददाता, मेरठ**

विश्व के सबसे बड़े युद्ध यानी महाभारत के भुगोल एवं साक्ष्य को लेकर इतिहासविद गोते लगा रहे हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान (एएसआइ) ने हाल में बड़ी उम्मीदों के साथ हस्तिनापुर (मेरठ) में डेरा डाला है। इतिहासविदों ने माना है कि हर टीले में इतिहास दफन है। अधीक्षण पुरातत्वविद मेरठ मंडल डीबी गणनायक की अगुवाई में आधुनिक उपकरणों के जरिए यहां उत्खनन का पहला चरण शुरू कर दिया गया है। अमृतकूप के पास स्थित टीले में एक गोलाकार आकृति मिली है, जिसमें नए साक्ष्य मिल सकते हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने पांडव टीले में ट्रेंच से मिट्टी हटाई, जहां से कुछ बर्तन मिले हैं। प्राचीन दीवारों की सफाई कर नए सिरे से व्यापक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से खनन की तैयारी की गई है। ट्रेंच लगाकर आधा दर्जन स्थानों को चिह्नित किया गया है।



मेरठ : हस्तिनापुर में पांडव टीले पर मिली गोलाकार आकृतिनुमा दीवार। जागरण

> पहले हस्तिनापुर की ऐतिहासिकता को लेकर प्रश्न खड़े किए गए थे, जिसे प्रो. बीबी लाल ने 1950-51 के खनन से दूर कर दिया। साबित हुआ कि यह पुराणों में वर्णित वही हस्तिनापुर है। यहां हर टीले में अंदर इतिहास के नए पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। सिनौली उत्खनन ने महाभारत को पूरी तरह स्थापित करते हुए इतिहास के कई पन्नों को भी बदल दिया।
>
> – डा. अमित पाठक, इतिहासविद

एएसआइ के संयुक्त निदेशक डा. संजय मंजुल और असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर आरती ने बताया कि सितंबर के बाद हस्तिनापुर में उत्खनन का नया युग शुरू होगा। यहां सिनौली जैसे महाभारतकालीन साक्ष्य मिल सकते हैं।

**बूढ़ी गंगा में मिले थे महाभारतकालीन बर्तन** : 1950-51 में भारतीय पुरातत्व के पितामह प्रो. बीबी लाल ने हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया। इस दौरान इतिहासकारों के बीच यह बहस छिड़ी कि क्या यह वही कौरव-पांडवों वाला हस्तिनापुर है? प्रो. बीबी लाल ने उत्खनन कराया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के टुकड़े मिले, जो करीब चार हजार वर्ष पुराने आंके गए। इतिहासकार डा. अमित पाठक कहते हैं कि ऐसे बर्तन दुनिया के किसी सभ्यता में पहली बार मिले। प्रो. बीबी लाल ने बूढ़ी गंगा में उत्खनन कराया और बोरवेल से यही बर्तन दोबारा मिले। इससे महाभारतकालीन विकसित सभ्यता की पुष्टि हो गई। बाद में यह सभ्यता गंगा की बाढ़ में बह गई थी।

**सिनौली में मिले थे 5000 साल पुराने रथ** : डा. अमित पाठक बताते हैं कि 2005 और 2018 में हस्तिनापुर से 80 किलोमीटर दूर बागपत के सिनौली में खनन कराया गया। यहां पर 116 शव दफन मिले, जो दुनिया में पहली बार देखे गए। यहीं पर करीब पांच हजार साल पुराना एक रथ मिला, जिसे महाभारत काल की ऐतिहासिकता का सबसे बड़ा साक्ष्य माना गया। एक ताबूत भी मिला, जिसकी एएसआइ अब तक पड़ताल कर रही है।

**ये है बूढ़ी गंगा** : महाभारत काल में गंगा नदी इसी स्थान (बूढ़ी गंगा) से होकर बहती थी। वर्तमान में गंगा नदी इस धारा से सात किलोमीटर की दूरी पर बहती है। अब इसमें पानी नहीं बहता है। केवल बरसात के दिनों में बूढ़ी गंगा में जलभराव हो जाता है।

### अनिवार्य हालमार्किंग की योजना में बदलाव नहीं

**नई दिल्ली :** केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हालमार्किंग की योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अनिवार्य हालमार्किंग की योजना वापस लेने की अधिसूचना से संबंधित खबरें पूरी तरह निराधार हैं। स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की अनिवार्य हालमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से देशभर के 256 जिलों में शुरू की गई थी। (प्रेट्र)

कोरोना काल में सड़क निर्माण में बड़ी तेजी आई। इस दौरान देश ने 24 घंटों में 2.5 किमी चार-लेन हाईवे का निर्माण कर विश्व रिकार्ड बनाया है।
– नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री



| | | |
|---|---|---|
| सेंसेक्स | 52,198.51 | ▼ 354.89 |
| निफ्टी | 15,632.10 | ▼ 120.30 |
| सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 47,100 | ▲ ₹253 |
| चांदी प्रति किलोग्राम | ₹65,730 | ▼ ₹61 |
| डॉलर | ₹74.61 | ▼ ₹0.27 |
| क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल | $ 68.86 | |

# आइपीओ और शेयरों में निवेश कर सकेंगे पेंशन फंड मैनेजर

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में शामिल चार करोड़ से अधिक धारकों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन दिलाने के उद्देश्य से सरकार पेंशन फंड में जमा रकम के इस्तेमाल को लेकर बदलाव करने जा रही है। अब पेंशन फंड का उपयोग कंपनियों के प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) और फालो-आन पब्लिक आफर (एफपीओ) की खरीदारी में भी किया जा सकेगा। रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट में भी पेंशन फंड के निवेश की इजाजत मिल सकती है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ऐसा होता है तो एनपीएस से जुड़े 4.37 करोड़ धारकों को रिटायरमेंट के दौरान पहले के मुकाबले अधिक रकम मिल सकती है। एनपीएस फंड में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के कर्मचारी पूंजी निवेश करते हैं। अभी एनपीएस का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंड मैनेजरों को सीमित जगहों पर इस फंड की रकम के निवेश की इजाजत हैं। अभी एनपीएस फंड से 5,000 करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी में ही निवेश की जा सकती है। इसके अलावा कारपोरेट डेट और सरकारी सिक्युरिटीज में निवेश की इजाजत है। पीएफआरडीए के मुताबिक अब बाजार में सूचीबद्ध होने वाली नई कंपनियों के आइपीओ और पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के एफपीओ में भी पेंशन फंड को फंड मैनेजर निवेश कर सकेंगे। हालांकि यह सब पीएफआरडीए की निगरानी में होगा और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि अपने बुढ़ापे के लिए निवेश कर रहे निवेशकों के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। इसलिए पीएफआरडीए अगले कुछ दिनों में पेंशन फंड के निवेश के नए आयाम को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है।

पीएफआरडीए अपने रिटायरमेंट फंड को एक करोड़ तक ले जाने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएफआरडीए के मुताबिक अब तक पेंशन फंड के इक्विटी निवेश से 11.31 फीसद का रिटर्न मिला है जबकि कारपोरेट डेट से 10.21 फीसद तो सरकारी सिक्युरिटीज से 9.69 फीसद का रिटर्न मिला है। पीएफआरडीए ने चालू वित्त वर्ष में एनपीएस से एक करोड़ नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हालांकि पहली तिमाही में सिर्फ 1.60 लाख लोग ही एनपीएस से जुड़ पाए हैं।

**4.37** करोड़ हैं कुल एनपीएस ग्राहक

**2.90** करोड़ हैं अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर

### कहां-कहां कर सकेंगे निवेश

नए नियमों के तहत पीएफएम आइपीओ, एफपीओ और आफर फार सेल लाने वाली कंपनियों के निवेश कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एनएसई और बीएसई के शीर्ष 200 शेयरों में भी निवेश कर सकेंगे। पीएफआरडीए का मानना है कि फंड मैनेजरों को कहां निवेश करना है, उन्हें इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

### कहां कितना रिटर्न

अभी तक शेयर बाजार में निवेश से 11.31 फीसद का रिटर्न मिला है। जबकि कारपोरेट डेट से 10.21 फीसद रिटर्न मिला है। सबसे कम 9.69% का रिटर्न सरकारी प्रतिभूतियों से मिला है।

### एक करोड़ ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य

पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा कि हम चालू वित्तीय वर्ष में सब्सक्राइबर बेस में एक करोड़ की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अकेले अटल पेंशन योजना के तहत 90 लाख ग्राहक जोड़े जाएंगे। दूसरी लहर के बावजूद पहली तिमाही में हम 1.60 लाख ग्राहक जोड़ने में सफल रहे।

### खतरे भी कम नहीं

ज्यादातर निवेशक सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न से अवगत हैं। लेकिन, सिस्टमैटिक विदड्राल के बारे में अनजान हैं। अगर किसी निवेशक की रिटायरमेंट की तारीख बाजार में बुरी खबरों के साथ मेल खाती है, तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एनपीएस निवेशकों ने इसका सामना इसलिए नहीं किया है, क्योंकि यह योजना केवल 14 साल पहले शुरू हुई है। नियामक को यह ध्यान रखना होगा कि सेवानिवृत्ति पर पोर्टफोलियो को नुकसान न हो।

# पेट्रो कीमतों में बड़ी राहत जल्द

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** जल्द ही केंद्र सरकार और आम ग्राहक, दोनों राहत की सांस लेने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल यानी कच्चे तेल की कीमतों ने हर रिपोर्ट का झुठलाते हुए गोता लगाया है। पिछले आठ दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 77.60 डालर प्रति बैरल से घट कर 68.40 डालर प्रति बैरल पर आ गई है। यह पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल के दाम में सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी वजह से देश की सरकारी तेल कंपनियां भी जल्द ही पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कमी करेंगी। अगर पिछले आठ दिनों में क्रूड के दाम में हुई सिर्फ 8.20 डालर की गिरावट के आधार पर ही आकलन करें तो भी पेट्रोल की खुदरा कीमत में चार रुपये प्रति लीटर और डीजल में पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती की सूरत बन रही है।

अगर ऐसा होता है तो सरकार को भी राजनीतिक तौर पर काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर तब जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्षी दल लगातार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है। मंगलवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय टैक्स की वजह से 3.35 लाख करोड़ रुपये वसूलने के मुद्दे को उठाया था। सरकार को दूसरी राहत यह होगी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के सस्ता होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल व डीजल की कीमतें स्वतः नीचे आएंगी और सरकार के राजस्व संग्रह पर कोई असर नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व संग्रह का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम उत्पाद ही हैं। आम ग्राहक पेट्रोल और डीजल का जितना खुदरा मूल्य चुकाता है, उसमें 60 फीसद हिस्सा केंद्र व राज्य के खजाने में चला जाता है।

बहरहाल, पिछले हफ्तेभर में क्रूड की कीमतों में गिरावट के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, तेल उत्पादक देशों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में विवाद खत्म होने से वैश्विक स्तर पर क्रूड उत्पादन में चार लाख बैरल प्रति दिन की वृद्धि की गई है। दूसरी वजह यह है कि कई देशों में लाकडाउन लगाए गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय कारोबारी समुदाय में निराशा है कि रोजगार के पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा।

**अच्छी खबर**



- एक दिन में सात फीसद घटा कच्चे तेल का दाम
- पेट्रोल में चार और डीजल कीमतों में पांच रुपये तक की राहत संभव

## सालाना नष्ट हो जाती है डेढ़ लाख करोड़ की कृषि उपज

**जाब्यू, नई दिल्ली :** देश में सालाना लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की कृषि उपज खेत से खलिहान तक पहुंचने के रास्ते में नष्ट हो जाती है। इस क्षति को रोकना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम यानी फसल कटने के बाद बाजार तक पहुंचने के तंत्र में सुधार के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लुधियाना स्थित इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीफेट) ने वर्ष 2015 में एक अध्ययन किया था। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान कुल लगभग एक लाख करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। जबकि लगभग 17,000 करोड़ रुपये मूल्य का फल और 15,000 करोड़ रुपये मूल्य की सब्जियां सड़ जाती हैं।

इस नुकसान को रोकने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का उपयोग शुरू किया गया।

# 'सारथी' देगा किसानों को बोआई से उपज बिक्री तक की जरूरी जानकारी

### यह डिजिटल प्लेटफार्म किसानों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलाजी से लैस करने के साथ उसे डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए 'किसान-सारथी' मोबाइल एप की शुरुआत की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालय की यह संयुक्त पहल किसानों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। इस डिजिटल प्लेटफार्म पर किसानों को फसलों की बोआई से लेकर उपज की बिक्री तक की जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस एप के माध्यम से खाद्यान्न के साथ-साथ बागवानी उपज की खरीद-बिक्री भी की जा सकेगी। मौसम की जानकारी से लेकर किसानों को हरसंभव सलाह भी इस प्लेटफार्म पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

'किसान सारथी' के माध्यम से किसान सीधे विषय विशेष के विज्ञानियों से सीधी बात भी कर सकता है। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा. अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका अहम रही है। इसके डिजिटल कारपोरेशन आफ इंडिया ने अपने राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जोड़ने में मदद की है। देश के 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) इसके नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इसके माध्यम से दूरदराज के किसानों को जोड़ना आसान हो जाएगा। जिले के केवीके से जुड़े विज्ञानियों से इस प्लेटफार्म पर सवाल पूछे जा सकते हैं।

सीजन में फसलों की बोआई के उपयुक्त समय और खेती में डाली जाने वाली खाद व बीज के बारे में इस एप के माध्यम से वैज्ञानिक सलाह ली जा सकती है। इतना ही नहीं, फसलों में लगने वाली बीमारियों से बचाव और रोकथाम के उपाय भी पूछे जा सकते हैं। फसलों के तैयार होने के बाद उसकी उपज की बाजार अथवा गोदामों तक ढुलाई करने और बाजार में बिक्री आदि में भी इस डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग फायदेमंद साबित होगा। मंडियों में खाद्यान्न व फल और सब्जियों के बाजार भाव की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

सारथी पर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उपज को पहुंचाने में भारतीय रेलवे की भी मदद ली जा सकेगी। किसान सारथी की सफलता में आइसीएआर के विज्ञानियों की भूमिका अहम होगी, जिनके माध्यम से ही किसानों को हर तरह की सलाह दी जा सकेगी। फिलहाल किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर मौसम की ताजा जानकारी पहुंचाई जा रही है।

### किसान सारथी एप के फायदे



- खाद्यान्न के साथ-साथ बागवानी उपज की भी खरीद-बिक्री होगी
- केवीके विज्ञानियों से इस प्लेटफार्म पर सवाल पूछे जा सकते हैं
- बोआई के उपयुक्त समय खाद और बीज के बारे में मिलेगी सलाह
- मंडियों में खाद्यान्न व फल और सब्जियों के भाव की जानकारी मिलेगी

## एडीबी ने विकास दर अनुमान घटाया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास दर अनुमान घटाकर 10 फीसद कर दिया है। इससे पहले बैंक ने यह अनुमान 11 फीसद रखा था। बैंक का मानना है कि रिकवरी की राह पर तेजी से लौट रही इकोनामी को कोरोना की दूसरी लहर से बड़ा नुकसान हुआ है।

एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट (एडीओ) में बैंक का कहना था कि बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2021) में विकास दर 1.6 फीसद रही, जिसके दम पर पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर में गिरावट का आठ फीसद का पूर्वानुमान घटकर 7.3 फीसद रह गया। लेकिन उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई और कई राज्यों को लाकडाउन जैसी सख्ती अपनानी पड़ी। हालांकि बैंक के अनुसार शुरुआती संकेत बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।

इस बीच, एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि देश की वृहत अर्थव्यवस्था मजबूत है और विकास दर सुधार के रास्ते पर है।

# कारपोरेट टैक्स में कटौती से कंपनियों ने की खूब कमाई

**मुंबई, प्रेट्र :** वर्ष 2019 में सरकार द्वारा कारपोरेट टैक्स में कटौती और कोरोना संकट के दौरान निजी स्तर पर खर्च में कमी लाने के उपायों से भारतीय कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में भरपूर कमाई की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते वित्त वर्ष (अप्रैल, 2020-मार्च, 2021) के दौरान भारतीय कंपनियों के मुनाफे में 105 फीसद की जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है। एसबीआइ रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हालत तब है जब समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनियों की आय में पांच फीसद की गिरावट देखी गई है।

एसबीआइ रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीते वित्त वर्ष के दौरान 4,000 सूचीबद्ध कंपनियों ने 1.90 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड कारपोरेट टैक्स अदा किया। उससे पिछले वित्त वर्ष में इन कंपनियों ने 1.40 लाख करोड़ रुपये कारपोरेट टैक्स दिया था। सरकार ने सितंबर, 2019 में कारपोरेट टैक्स की प्रभावी दर को 35 से घटाकर 26 फीसद कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने महामारी के दौरान अपने खर्च में भी काफी कमी की है। इससे उनका मुनाफा बीते वित्त वर्ष में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट का कहना है कि टैक्स कटौती ने महामारी के दौरान इन कंपनियों की आय में 19 फीसद का योगदान दिया। वहीं सीमेंट, टायर और टिकाऊ उपभोक्ता सामान कंपनियों की आय में यह योगदान 50 फीसद से अधिक रहा।

### रिपोर्ट का सच

**2.09** लाख करोड़ रुपये का कर्ज घटाया 15 सेक्टर की कंपनियों ने

**43,454** करोड़ रुपये कारपोरेट टैक्स दिया कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में, दो दशकों का रिकार्ड

**1.2** लाख करोड़ रुपये रह गया राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के दौरान मई के आखिर में

## राष्ट्रीय फलक

### न्यूज गैलरी

**केरल में बकरीद से पहले मीट की 958 दुकानों का निरीक्षण**

**तिरुअनंतपुरम :** नागरिक आपूर्ति और कानूनी माप विभाग के अधिकारियों ने केरल में मीट की 958 दुकानों का निरीक्षण किया। केरल के खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति मंत्री जीआर अनिल ने बताया कि राज्य में मीट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। (प्रेट्र)

**जर्किहोली मामले में एसआइटी ने हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट**

**बेंगलुरु :** भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री रमेश जर्किहोली से संबंधित सेक्स टेप मामले में एसआइटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट को सौंप दी। मामला दो मार्च को सामने आया था, जब सामाजिक कार्यकर्ता कल्लाहल्ली ने जर्किहोली से संबंधित सेक्स रैकेट में जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। (एएनआइ)

**वसूली के आरोप में दाऊद का गुर्गा यूसुफ बचकाना गिरफ्तार**

**मुंबई :** अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम के गुर्गे यूसुफ बचकाना को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसे 27 जुलाई तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। उस पर हत्या का भी आरोप है। (एएनआइ)

**एटीएस ने पकड़ा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज**

**पटना :** आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने मंगलवार को राजधानी पटना के अनीसाबाद इलाके में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) के इनपुट पर एटीएस ने यह कार्रवाई की। मौके से अनिल और सुशील चौरसिया को गिरफ्तार किया है। (राब्यू)

**मुजफ्फरनगर में बंधक बने 16 में से तीन लड़के घर पहुंचे**

**श्री बंशीधर नगर :** उप्र के मुजफ्फरनगर में बंधक बने झारखंड के गढ़वा जिले गरबांध गांव के 11 नाबालिग सहित 16 लड़कों में से तीन लड़के शिवधारी उरांव, जितेंद्र उरांव व गोपाल उरांव सोमवार की देर रात भागकर घर पहुंचे। सभी को चीनी मिल में काम दिलाने के बहाने धोखे से ले जाया गया था। (जासं)

# पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

**जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद**

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ 2009-10 में दिव्यांगों के उपकरण वितरण का कैंप दिखाकर लाखों रुपये हड़पने के आरोप में सीबीसीआइडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी की अदालत ने वारंट जारी करने के साथ ही सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की है।

सीबीसीआइडी के इंस्पेक्टर रामशंकर यादव ने कायमगंज कोतवाली में 29 मई, 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि फर्रुखाबाद मऊदरवाजा थाने के निकट स्थित डा.जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 71.50 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। फर्रुखाबाद व कायमगंज में फर्जी कैंप दर्शाकर इसमें से चार लाख रुपये हड़प लिए गए। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4-गुलमोहर एवेन्यू, जामिया नगर नई दिल्ली निवासी लुईस खुर्शीद व गुरुदेव विहार, नई दिल्ली निवासी ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुकी उर्फ अजहर को न्यायालय में तलब किया था। दोनों ही आरोपित अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर तामील कराने के आदेश जारी किए हैं।



घेरे में लुईस खुर्शीद। फाइल फोटो

## सहायिका का काम कर रही छात्रा ने किया बच्ची का अपहरण

**जागरण संवाददाता, भिवाड़ी (रेवाड़ी) :** पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए घरेलू सहायिका का काम कर रही एमएससी अंतिम वर्ष की एक छात्रा ने वेतन नहीं मिलने पर तीन साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। दिल्ली के प्रसाद नगर से भागी युवती को बच्ची के साथ भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ लिया गया। पुलिस ने बच्ची को भी बरामद कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपित युवती अलवर के 80 फीट मार्ग की रहने वाली है। वह वर्तमान में दिल्ली के प्रसाद नगर में घरेलू सहायिका का काम कर रही थी। सोमवार को वह परिवार की तीन साल की बच्ची को लेकर घर से निकल गई। बच्ची और घरेलू सहायिका नहीं दिखे तो परेशान परिवार ने पटेल नगर थाना पुलिस में शिकायत की। मोबाइल लोकेशन के आधार राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई। खुशखेड़ा पुलिस ने बस स्टाप से उसे दबोच कर बच्ची को बरामद कर लिया।

# जींस पहनने पर किशोरी की हत्या, फेंका शव पुल पर लटका

**जागरण संवाददाता, देवरिया**

जींस पहनने से नाराज स्वजन ने सोमवार की रात 17 वर्षीय किशोरी नेहा की पीटकर हत्या कर दी और शव छोटी गंडक नदी में फेंक दिया। मंगलवार सुबह शव पुल की रेलिंग में लटकता मिला, तो मामले का पर्दाफाश हुआ। महुआडीह के सवरेजी खर्ग गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात में नेहा की मां शकुंतला ने बाबा-दादी, दो चाचा-चाची व आटो चालक समेत तीन ग्रामीणों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपित फरार हैं। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट लगने की पुष्टि हुई है।

पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करने वाले अमरनाथ पासवान का परिवार गांव में ही रहता है। सोमवार रात जींस पहनने पर टोकने से नेहा की बाबा परमहंस से बहस हो गई। आरोप है कि बाबा, चाचा अरविंद और व्यास समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने नेहा को बेरहमी से पीटा। बीचबचाव करने आई नेहा की मां और बड़ी बहन निशा को धक्का देकर गिरा दिया। अरविंद और उसकी पत्नी पूजा के गला दबाने से नेहा बेहोश हो गई। बात बढ़ी तो अरविंद इलाज के लिए दो पड़ोसियों और गांव निवासी आटो चालक के साथ नेहा को लेकर निकला। बकौल पुलिस पांडेयचक के पास नेहा की मौत हो गई तो आरोपित छोटी गंडक नदी पर बने पटनवा पुल पहुंचे और शव नीचे फेंक दिया। शव पुल की रेलिंग में फंस गया और सभी आरोपित भाग गए। पुल पर शव लटकता देखकर मंगलवार सुबह सनसनी फैल गई।

जींस पहनने से नाराज स्वजन की पिटाई से किशोरी की मौत होने की बात सामने आई है। आटो चालक ने पूछताछ में पूरी घटना बताई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। -डा. श्रीपति मिश्र, एसपी

## सुंदरवन में सात दिन में लगातार सात लोग बने बाघों के शिकार

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** सुंदरवन में लगातार सात दिन में सात लोग बाघों का शिकार बने हैं। मरने वाले सभी मछुआरे हैं, जो कि केकड़ा पकड़ने जंगलों में गए थे। यह सभी वारदात 10 से 16 जुलाई तक हुई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि पिछले एक साल के दौरान सुंदरवन में बाघों के हमले में 50-60 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिक रुपये कमाने की चाह में प्रतिबंधित वनांचलों में जाकर केकड़ा पकड़ने के कारण लोग बाघों का भोजन बन रहे हैं। बाघों के हमले में जो लोग मारे गए हैं, उनके स्वजन को वन विभाग की तरफ से दो बकरियां दी गई हैं ताकि वे उससे रोजगार कर सकें। मृतकों के स्वजन का कहना है कि दो बकरियां देने से कुछ नहीं होने वाला। गौरतलब है कि रोजगार नहीं होने के कारण स्थानीय मछुआरे केकड़ा पकड़ने उन जगहों पर जाते हैं, जहां पर बाघ पानी पीने आते हैं।

# बस जलाने के मामले में छह साल की जेल

**एर्नाकुलम, प्रेट्र :** केरल के एर्नाकुलम स्थित एनआइए की विशेष अदालत ने कलामसेरी बस जलाने के मामले में एक व्यक्ति को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1,60,000 रुपये जुर्माना किया है। जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि 2005 में अपराध अंजाम देने के बाद देश से भाग निकले एर्नाकुलम निवासी केए अनूप को अप्रैल 2016 में गिरफ्तार किया गया था।

यह मामला सितंबर 2005 में कलामसेरी थाने में दर्ज किया गया था। टी. नजीर एवं अन्य ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष अब्दुल नासेर की रिहाई की मांग के समर्थन में एर्नाकुलम एवं सलेम के बीच चलने वाली तमिलनाडु की सरकारी बस का अपहरण कर लिया था और उसमें आग लगा दी थी। उस समय नासेर कोयंबटूर जेल में बंद था। एनआइए ने 2010 में मामला दर्ज किया और अनूप समेत 13 आरोपितों के खिलाफ भादवि की धाराओं और पीडीपीपी अधिनियम एवं यूए (पी) अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को अनूप को विभिन्न आरोपों में सजा सुनाई गई।

## ईरान में फंसे पांच भारतीयों की वापसी पर मांगा जवाब

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :** आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों की वतन वापसी को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने 27 जुलाई तक सुनवाई टाल दी। अधिवक्ता गुरिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर याचिका में स्वजन ने कहा कि नाविकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, वित्तीय सहायता, भोजन और आवास के साथ ही काउंसलर सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। याचिका के अनुसार नाविकों को दुबई में नौकरी के बहाने ईरान ले जाया गया और वहां से एक मालवाहक पोत पर भेज दिया गया। फरवरी, 2020 में ईरानी अधिकारियों ने पोत के कप्तान के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, ईरान की कोर्ट ने नौ मार्च को सभी नाविकों को बरी कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने पासपोर्ट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सौंपने से इन्कार कर दिया। स्वजन ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास को ज्ञापन दिया था, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिली। 10 जुलाई को वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

## जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरण में बहस पूरी

**जासं, रामपुर :** जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में आखिरकार बहस पूरी हो गई। अदालत अब दो अगस्त को फैसला सुना सकती है। उप जिलाधिकारी सदर ने 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट सरकारी जमीन पर बना होने पर तोड़ने का आदेश दिया था। इस मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी।

## अभिनेत्री खुशबू सुंदर का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक

**चेन्नई, प्रेट्र :** अभिनेत्री और भाजपा सदस्य खुशबू सुंदर ने मंगलवार को कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि उनके अकाउंट पर हाल के कुछ दिनों की गतिविधियों में वे शामिल नहीं हैं।

खुशबू ने कहा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि तीन दिन पहले मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हम ट्विटर के प्रशासनिक कार्यालय से इस मामले में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से इस अकाउंट से किए गए ट्वीट मेरे नहीं हैं। खुशबू ने बाद में राज्य के पुलिस प्रमुख सी शैलेंद्र बाबू के सामने शिकायत दर्ज कराई। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके ट्विटर हैंडल को बदल दिया गया है और वह उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं।



हैकिंग की शिकार अभिनेत्री खुशबू। फाइल फोटो

# बोनट पर लटका रहा युवक और चालक दौड़ाता रहा कार

- डीसीएम की टक्कर लगने पर शुरू हुआ विवाद, बात बढ़ी तो कुचलने का प्रयास
- नहीं पता चला कि कार सवार कितनी दूर ले गए युवक को, शिकायत का इंतजार



जाजमऊ फ्लाई ओवर पर कार की बोनट पर लटका युवक। स्रोत वीडियो ग्रैब

**जागरण संवाददाता, कानपुर**

हाईवे पर फर्राटा भरती कार के बोनट पर लटका युवक जान की भीख मांगता रहा, लेकिन कार चला रहा जल्लादा पसीजा नहीं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखी यह सनसनीखेज घटना कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित जाजमऊ फ्लाईओवर की बताई जा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह दृश्य देखकर लोग सहम जा रहे हैं। बोनट पर लटकी जिंदगी स्टीयरिंग पर 'जल्लाद' से हारी या जीती, फिलहाल इसका पता नहीं है।

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में तेज रफ्तार कार सवार युवक को बोनट पर लटकाए कार दौड़ाते नजर आ रहा है। हालांकि, यह नहीं पता चल पा रहा है कि कार चालक युवक को कितनी दूर ले गया और घटना कब की है, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है।

दैनिक जागरण
शांति ही समृद्धि सुनिश्चित करती है

# फटकार में देरी

केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लाकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उसे जो फटकार लगाई, वह जरूरी थी, क्योंकि केरल उन राज्यों में से है, जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यह हैरत की बात रही कि जब केरल सरकार को यह देखना चाहिए था कि बकरीद के अवसर पर बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में भीड़-भाड़ न होने पाए, तब उसने तीन दिन के लिए खास रियायत दे दी। इससे भी आपत्तिजनक बात यह रही कि उसने राज्य के उन इलाकों में भी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, जहां कोरोना संक्रमण की दर 15 प्रतिशत से भी अधिक थी। निश्चित रूप से ऐसा करके महामारी के जोखिम को और बढ़ाने का काम किया गया। यह सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसा केवल व्यापारी संगठनों के दबाव में ही नहीं किया गया होगा, बल्कि वोट बैंक बनाने या उसे मजबूत करने की कोशिश के तहत भी किया गया होगा। यह लज्जा की बात है कि कोई राज्य सरकार लोगों की जान जोखिम में डालकर तुष्टीकरण की ऐसी खुली राजनीति करे। केरल सरकार ने यह काम इस तथ्य से अवगत होने के बाद भी किया कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रतीकात्मक रूप से भी कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी।

यह संभव नहीं कि केरल सरकार इस सबसे परिचित न हो कि संक्रमण की दूसरी लहर के जारी रहने और तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए देश भर में किस तरह सार्वजनिक स्तर पर होने वाले आयोजनों को रद करने की जरूरत जताई जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री भी राज्यों को आगाह कर रहे थे। यह अजीब है कि केरल सरकार के फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को छोड़कर अन्य किसी संगठन ने आवाज उठाने का साहस नहीं किया। क्या इसलिए नहीं किया, ताकि समुदाय विशेष को बुरा न लगे? जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुंभ के आयोजन पर किस तरह तमाम राजनीतिक दल मुखर हो उठे थे। क्या नैतिकता का तकाजा यह नहीं कहता था कि ये दल केरल सरकार के बेजा फैसले पर भी मुखरता दिखाते? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि ऐसा करने में देर कर दी गई। यह फटकार तब आई, जब लाकडाउन में छूट का आखिरी दिन था। क्या यह उचित नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट उसी दिन सक्रिय होता, जिस दिन केरल सरकार ने तीन दिन के लिए छूट की घोषणा की थी? यह जो देरी हुई, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

# अब सभी की जिम्मेदारी

आखिर पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से दसवीं से लेकर बारहवीं तक के स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है। सरकार ने यह ठीक किया है कि इसे अभी अभिभावकों की इच्छा पर छोड़ दिया कि वे बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। इस फैसले ने शिक्षा महकमे ही नहीं, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। डेढ़ साल से ज्यादा समय से बच्चे आनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तमाम विशेषज्ञ, शिक्षाविद, मनोविज्ञानियों की यही राय रही है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए फिजिकल कक्षाएं जरूरी हैं। वहां बच्चे एक-दूसरे से समन्वय स्थापित करना सीखते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, शिक्षकों के समक्ष अपनी समस्याएं अच्छी तरह से रख पाते हैं, शिक्षक भी उन्हें बेहतर समझते हैं। घरों में ही रहने से बच्चों की सेहत व दिलोदिमाग पर असर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि स्कूलों में कक्षाएं लगें। कई राज्य तो पहले ही ऐसा कर चुके हैं। यह सुकून की बात है कि पंजाब में भी अब कोविड के मामले काफी कम हो चुके हैं। इसलिए सरकार ने निश्चित तौर पर बहुत सोच विचार करके ही यह फैसला लिया होगा। अगर यह फैसला सही रहता है तो दो अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की बात भी कही है। इसी के साथ ही कुछ और पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं या उनमें कुछ छूट दी जा रही है। जैसे कि इनडोर कार्यक्रमों में अब डेढ़ सौ और आउटडोर में तीन सौ तक लोग इकट्ठा हो सकेंगे। यह जनजीवन को सामान्य बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम तो हैं, लेकिन सरकार व आमजन को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आने की आशंका स्वास्थ्य विशेषज्ञ जता रहे हैं। सरकार अगर इतनी छूट दे रही है तो यह माना जा सकता है कि उसने तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी कर ली होगी। आक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पहले जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यहां बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी अब लोगों की भी है। दसवीं से बारहवीं तक के बच्चे समझदार होते हैं। उन्हें अभिभावक सही ढंग से समझाएंगे कि कोविड नियमों का पालन करें तो स्कूल भेजने में कोई खतरा नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन व शिक्षा विभाग को भी स्कूलों की निगरानी की व्यवस्था करनी होगी ताकि कोविड नियमों का पालन करवाया जा सके। सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी पाबंदियों में छूट और स्कूल खोलने का सरकार का फैसला उचित साबित होगा।

# मध्य एशिया में भारत की बढ़ती पैठ



हर्ष वी पंत

कट्टरपंथ और अतिवाद का बढ़ता जोखिम भी मध्य एशिया और भारत को एक मंच पर लाता है, क्योंकि ये दोनों के समक्ष एक साझा चुनौती है

कोरोना के कहर से कुछ मुक्ति मिलने के बाद भारतीय विदेश नीति ने भी यकायक रफ्तार पकड़ी है। इसी सिलसिले में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की। बीते दिनों वह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे भी गए। दरअसल अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच एससीओ बैठक की महत्ता और बढ़ गई। एससीओ बैठक के एजेंडे से यह सिद्ध भी हो गया, जहां अफगानिस्तान का मसला ही चर्चा के केंद्र में रहा। यह बहुत स्वाभाविक भी था, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की विदाई के बाद अब यह उसके पड़ोसी देशों का दायित्व बन जाता है कि वे आतंक और अस्थिरता से पीड़ित इस देश पर विशेष रूप से ध्यान दें। अन्यथा अफगान धरती से निकली आतंक की चिंगारी रूस और चीन से लेकर मध्य एवं दक्षिण एशिया में अशांति की भीषण आग लगा सकती है। स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को लेकर आस-पड़ोस के देशों पर दबाव बन रहा है। यह दबाव दुशांबे में भी महसूस किया गया। वहां बनी यह सहमति महत्वपूर्ण रही कि अफगानिस्तान में तालिबान को तब तक वैधानिकता और मान्यता मिलने से रही, जब तक कि वह सभी अफगान पक्षों और अंशभागियों के साथ एक मंच पर नहीं आता। इससे तालिबान पर एक प्रकार का दबाव तो बनेगा। इसकी पुष्टि अफगान सरकार के साथ उसकी वार्ता से भी हुई है।

अपने मध्य एशिया के दौरे पर जयशंकर कनेक्टिविटी से जुड़ी चर्चा के मंच पर भी सक्रिय रहे। न केवल अफगानिस्तान, बल्कि मध्य एशिया के अधिकांश देश लैंड लॉक्ड यानी भू-आबद्ध हैं। ऐसे में उनके समक्ष कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर उनकी निर्भरता और बढ़ जाती है। इसके अपने दुष्परिणाम हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जयशंकर ने उचित ही कहा कि कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ ही देशों की संप्रभुता का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के संदर्भ में ऐसी परियोजनाओं के जोखिमों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। भारत की संवेदनाओं को दरकिनार कर ही चीन इस परियोजना पर आगे बढ़ा। भारत के प्रति चीन का बिगड़ैल रवैया केवल इसी परियोजना तक ही सीमित नहीं रहा है। इसके बावजूद वह अपने हितों को देखते हुए भारत को साधने में भी लगा है। दुशांबे में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जयशंकर से संवाद का प्रयास भी किया, लेकिन भारतीय रुख चीन को लेकर एकदम स्पष्ट रहा कि तकरार और प्यार साथ नहीं चल सकते। चीन के ऐसे प्रयासों पर भारत ने उचित ही दोहराया कि जब तक सीमा पर पूर्व की यथास्थिति कायम नहीं हो जाती तब तक बीजिंग को वार्ता के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन नीतिगत मोर्चे पर उसे उसकी महत्ता के अनुरूप स्थान नहीं मिल सका। जयशंकर इस विसंगति को दूर करने में लगे हैं। उनके नेतृत्व में भारत मध्य एशिया के साथ अपनी ऐतिहासिक कड़ियों को फिर से जोड़कर संबंधों को पुनर्जीवित करने में जुटा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एससीओ बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का दौरा भी किया। मध्य एशियाई देशों के मामले में जहां भारत के लिए व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं वहीं भू-राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए इन संभावनाओं को भुना पाना उतनी ही कठिन चुनौती भी है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। गैस जैसे संसाधन के विपुल भंडार पर बैठे मध्य एशियाई देश भारत की ऊर्जा जरूरतों की दीर्घकालिक पूर्ति करने में सक्षम है। इस दिशा में अभी तक अपेक्षित प्रयास नहीं हुए हैं और जो हुए, वे भी अपेक्षा के अनुरूप सिरे नहीं चढ़ पाए। तापी गैस परियोजना को ही लें। तुर्कमेनिस्तान से भारत तक गैस आपूर्ति से जुड़ी यह परियोजना अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे साझेदारों के कारण अटकी हुई है। मध्य एशिया के साथ अपनी साझेदारी की राह में आने वाली ऐसी धरातलीय बाधाओं के बावजूद भारत ने अपनी कोशिशों की रफ्तार कम नहीं की है। जयशंकर का हालिया मध्य एशियाई दौरा इसी दिशा में एक अहम पड़ाव था। मध्य एशिया में कट्टरपंथ और अतिवाद का बढ़ता जोखिम भी मध्य एशिया और भारत को एक मंच पर लाता है, क्योंकि ये दोनों के समक्ष एक साझा चुनौती हैं, जिससे उन्हें मिलकर निपटना होगा।



अवधेश राजपूत

बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे अस्थिर देशों से जुड़ी बाधाओं की ही नहीं है। इस क्षेत्र में चीन और रूस अत्यंत अहम खिलाड़ी हैं। दोनों ने यहां पश्चिमी देशों को अपने पैर नहीं जमाने दिए हैं। वहीं भारत के लिए एससीओ में मिले प्रवेश ने यहां एक राह जरूर बना दी है, लेकिन आगे की मंजिल उतनी आसान नहीं है। इसका कारण चीन का भारत के प्रति जगजाहिर रवैया है। रूस भारत का सदाबहार मित्र तो है, लेकिन मौजूदा हालात में यह देखने वाली बात होगी कि वह भारत का कितना और किस हद तक समर्थन जारी रखता है? इसकी वजह यही है कि पिछले कुछ समय से मास्को का पलड़ा एक हद तक बीजिंग की ओर झुका है। चीन भी दुनिया भर में आक्रामक तेवर दिखाने के बावजूद इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, जिससे रूस को कोई नाराजगी हो। हालांकि रूस के साथ लगी चीनी सीमा से लेकर अन्य मध्य एशियाई देशों के मामले में चीन की दबी-छिपी मूल मंशा दिखती तो है, पर उसके कारण अभी तक किसी तनाव के संकेत नहीं दिखे हैं।

ऐसे जटिल समीकरणों में भारत के लिए यही सही होगा कि वह मौके के हिसाब से अगला कदम उठाए। कुल मिलाकर मध्य एशिया दौरे पर जयशंकर अफगानिस्तान पर आमसहमति बनाने, मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर स्पष्ट रुख अपनाने और इन देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के साथ ही उन संभावनाओं के द्वार भी खोलने में सफल रहे, जो अभी तक बंद थे। चूंकि चीन इस क्षेत्र का एक अहम खिलाड़ी है इसलिए इसे उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जाएगा कि यह सब बीजिंग के साथ तनातनी के दौर में भी संभव हो सका।

(लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं)

response@jagran.com

# न्यायपालिका पर भरोसे का सच



राजीव सचान

आखिर यह कैसे मान लिया जाए कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा होता है?

बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि देश के लोगों को भरोसा है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। उनके अनुसार लोग यह भी जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में उनके साथ खड़ा होगा। उन्होंने ये बातें भारत-सिंगापुर मीडिएशन समिट को संबोधित करते हुए कहीं। उनके इस कथन ने अन्य अनेक बातों के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के उस कुख्यात धरने की भी याद दिला दी, जो 2019 में सौ दिनों से अधिक समय तक चला था और जिसके चलते लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। लोग और खासकर इस धरने से सीधे तौर पर प्रभावित लोग यह नहीं भूल सकते कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्त कर दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि धरने को एक तरह की वैधानिकता मिल गई और शायद इसी कारण धरना दे रहे लोग टस से मस नहीं हुए। मध्यस्थों ने बीच सड़क पर धरना दे रहे लोगों को अन्यत्र धरना देने के लिए समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। धरना जारी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। बाद में जब कोरोना की दहशत बढ़ी और धरना स्थल पर चंद लोग ही रह गए, तब दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को मुक्त कराया। कई महीने बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता। यह फैसला आने के पहले ही पंजाब में किसान संगठनों के लोग कृषि कानूनों के विरोध में रेल पटरियों पर बैठ गए थे। चूंकि इन किसान संगठनों को पंजाब सरकार का भी समर्थन हासिल था इसलिए किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, हाई कोर्ट अवश्य पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान संगठनों के लोग रेल पटरियों पर बैठे ही रहे।

चूंकि पंजाब में यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों का भी परिचालन ठप हो गया था इसलिए कोयले की किल्लत के चलते बिजली संयंत्र बंद होने की नौबत आ गई और उद्योगों को कच्चा माल मिलना भी बंद हो गया। रेल पटरियां बाधित होने के कारण सैकडों ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। यह सिलसिला पांच महीने से अधिक चला। न्यायपालिका का पता नही,



कई मामलों में शीर्ष अदालत ने लोगों को किया निराश। फाइल

आम लोग यह अनुमान सहज ही लगा सकते हैं कि पांच महीनों तक सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन ठप रहने से कितने लाख लोग प्रभावित हुए होंगे? लोगों को न्यायपालिका से कोई राहत नहीं मिली। 169 दिन बाद किसान संगठनों ने पंजाब की रेल पटरियों को अपने कब्जे से मुक्त करने के बाद दिल्ली की ओर कूच किया और वे राजधानी के प्रवेश मार्गों पर आकर बैठ गए। सात महीने हो गए हैं, वे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके सड़कों पर बैठे होने के कारण दिल्ली और आसपास के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें या तो रास्ता बदलकर जाना पड़ता है या भारी ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। इस पर गौर करें कि सात महीने हो गए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है-सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। यह तब है जब रास्ता खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।

कोई नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों की धरनेबाजी से आजिज लोगों को राहत और न्याय देने की जरूरत क्यों नहीं समझ रहा है? आखिर क्यों और कैसे यह मान लिया जाए कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में लोगों के साथ खड़ा होता है? क्या इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कह रहे हैं? सवाल यह भी है कि आखिर शाहीन बाग मामले में देर से दिए गए उस निर्णय का क्या मूल्य-महत्व, जो यह कहता है कि धरना-प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता? क्या सात महीने की लंबी अवधि अनिश्चितकाल के दायरे में नहीं आती? अगर नहीं आती तो यह अंधेर के अलावा और कुछ नहीं। देर और अंधेर के साथ-साथ आम लोगों की अनदेखी का यह इकलौता उदाहरण नहीं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, जब न्यायपालिका लोगों के दुख और तकलीफों पर या तो मौन रही या फिर उससे परिचित होने के बावजूद तत्परता नहीं दिखाई। कई बार तो वैसे मामलों में भी नहीं, जो स्वतः संज्ञान लिए जाने लायक थे। ऐसा ही एक मामला है बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा का।

तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित हिंसा में उसे वोट न देने वालों को चुन-चुनकर प्रताड़ित किया गया। कुछ की हत्या की गई। कुछ के घर-दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई। तमाम लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जो अभी तक जारी है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का आतंक इतना जबरदस्त था कि सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इस भयावह हिंसा का स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने नहीं लिया। बाद में जब इस हिंसा की जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया। दूसरी तारीख में एक और जज ने भी ऐसा ही किया। ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। करीब दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा। क्या आप यह कह सकते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा होता है?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## त्याग का महत्व

मानव जीवन में त्याग की महती भूमिका मानी गई है। यहां तक कि हमें दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस का त्याग करना पड़ता है। त्याग मात्र एक कर्म ही नहीं, अपितु यह एक भाव है। यह हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक बनता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि 'त्याग के समान कोई सुख नहीं है।' स्वामी रामतीर्थ भी कहते हैं कि 'त्याग के सिवा इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है।' मनुष्य ही नहीं साक्षात ईश्वर को भी बिना त्याग के यश एवं वैभव की प्राप्ति नहीं हुई। त्याग की ऐसी प्रतिमूर्ति के रूप में भगवान श्रीराम का नाम सर्वोपरि माना जाता है। पिता की आज्ञा का मान रखकर राजपाट त्यागकर भगवान राम ने वन गमन को वरीयता दी। वनवास की ओर कदम बढ़ाने से पहले वह सिर्फ राम थे, लेकिन वनवास पूरा होने के बाद वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

इसी प्रकार अर्जुन और दुर्योधन महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्रीकृष्ण से मदद मांगने पहुंचे। तब अर्जुन ने श्रीकृष्ण की नारायणी सेना का त्यागकर श्रीकृष्ण को चुना, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि भगवान का साथ होना ही बहुत है। यदि अर्जुन सेना का मोह करते तो कदाचित महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता। राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक मोह का त्याग मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए किया। इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वह सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी ने त्याग का एक अनुपम उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने देश के हित और स्वाधीनता के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया। सुखों के त्याग से उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बना कि वह राष्ट्रपिता बन गए। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरों के हित में अपने सुखों का त्याग कर सकता है, वही साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक महामानव बनता है। ऐसे महामानव ही समाज, देश और सृष्टि के कल्याण का निमित्त बनते हैं।

पुष्पेंद्र दीक्षित

# महामारी के बीच बाल श्रम का संकट

उमेश कुमार गुप्ता

लाकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ लोग सस्ते श्रम के विकल्प के रूप में बाल मजदूरी को बढ़ावा दे सकते हैं

लाकडाउन खुलने के साथ ही बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से जबरिया मजदूरी कराने के लिए बच्चों की तस्करी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पिछले एक महीने के दौरान ऐसे ही 500 से अधिक बच्चों को उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से छापामार कार्रवाइयों के दौरान रेलवे पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मुक्त कराया। बहरहाल जो बच्चे मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी का शिकार होने से बच गए, वास्तव में भाग्यशाली हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि उनके पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। अन्यथा मजबूरन अपना गांव छोड़कर वे हजारों किमी दूर जाने को ही विवश होंगे।

गत माह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने 'बाल मजदूरी के वैश्विक अनुमान, चलन और आगे की राह' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके मुताबिक फिलहाल दुनिया में करीब 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। उनमें से सात करोड़ 90 लाख बच्चे खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। रपट के अनुसार कोविड महामारी के कारण बढ़ी गरीबी के चलते करीब छह करोड़ 80 लाख और बच्चे वर्ष 2022 के अंत तक बाल मजदूर बनने को विवश हो सकते हैं। बाल मजदूरी के मुद्दे पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की मानें तो लाकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई करने के क्रम में कुछ लोग सस्ते श्रम के रूप में बाल मजदूरों को रखने पर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं।

यहां एक बड़ा मुद्दा महामारी के दौरान स्कूलों का बंद रहना भी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। इससे वे अपने बच्चों को आनलाइन क्लास नहीं करा पा रहे। माता-पिता का मानना है कि यदि ये लोग पढ़ नहीं रहे तो अच्छा है कहीं बाहर जाकर काम सीखें और कुछ पैसे ही कमाएं। ऐसे सोच से बाल मजदूरी के खात्मे और शिक्षा के अधिकार के लिए पिछले एक दशक में चलाए गए अभियान को आघात पहुंचा है।

इस समस्या के निदान के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गति प्रदान की जाए। साथ ही जिला स्तर पर बने बाल श्रमिक कल्याण एवं पुनर्वास कोष का उपयोग मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास में किया जाए। वहीं जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाइयों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर ऐसे परिवारों का पता लगाएं जो बड़ी मुश्किल स्थिति में हैं और बच्चों को असमय आजीविका से जोड़ने पर बाध्य हैं। ऐसे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ने की पहल की जानी चाहिए। इसमें श्रम अधिकारियों की जवाबदेही भी अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी जगह बाल श्रमिकों से काम न लिया जा रहा हो।

(लेखक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं)

## अपनी छवि की चिंता करें दक्षिण अफ्रीकी

आरके सिन्हा ने अपने आलेख 'दक्षिण अफ्रीका में प्रताड़ित भारतवंशी' में इस अफ्रीकी देश में जारी संगठित एवं सुनियोजित हिंसा का सजीव चित्रण किया। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता कि जिस देश ने मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की आधारशिला रखी उसकी अपनी जड़ें इतनी खोखली हैं कि राजनीतिक विरोध से अंधे हुए कुछ लोग एक तबके को इस कदर निशाना बनाए हुए हैं कि उन्हें जान-माल का नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। एक राजनीतिक-औद्योगिक साठगांठ का खामियाजा आखिर उन आम भारतीयों को क्यों भुगतना पड़े, जिन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई और उसकी तरक्की के हमकदम रहे। साथ ही इस घटनाक्रम में उद्योगपतियों के लिए भी एक संदेश निहित है कि वे येन-केन-प्रकारेण संपत्ति सृजन करने में न लगे रहें। इससे वे स्वयं को असहज करने के साथ ही तमाम जोखिमों के लिहाज से संवेदनशील बना लेते हैं। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक समर्थकों का यह बिल्कुल हक नहीं बनता कि वे अपने संकीर्ण हितों और कुंठा की पूर्ति के लिए उन लोगों को निशाना बनाएं जिन्होंने अपने परिश्रम के दम पर अपनी मिट्टी से कहीं दूर जाकर अपनी जड़ें जमाई हैं। दक्षिण अफ्रीकियों को तो यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से भी वह एक संगम भूमि है, जहां हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। 'केप ऑफ गुड होप' की भूमि से हिंसा और कलह का ऐसा संदेश दुनिया में उसकी छवि को ही तार-तार करेगा। इस

## मेलबाक्स

मामले में भी वहां का कानून अपनी भूमिका निभाएगा ही तो बेहतर है कि लोग कानून अपने हाथ में लेकर एक गलत मिसाल न पेश करें।

केशव तिवारी, इंदिरापुरम (गाजियाबाद)

## कथनी और करनी में अंतर

विश्व के 100 बेहतरीन शहरों में नई दिल्ली का भी नाम आता है। दिल्ली का इतिहास भी रोमांचकारी और संघर्ष से भरा है। यहां की दिग्गज हस्तियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम कर इसके नाम को गौरवान्वित किया है, लेकिन आज प्रशासनिक कामों के मामलों में यह दिन-प्रतिदिन कमजोर पड़ती दिख रही है। 26 जनवरी को लाल किले के पास जो कुछ भी हुआ वह जगजाहिर है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी प्रशासन के कुप्रबंधन का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा और अब काफी इंतजार के बाद मानसून की फुहार जब दिल्ली की धरा पर पड़ी तो एक दिन की बारिश में ही कई स्थान तालाब में तब्दील हो गए। जल जमाव के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई, परिवहन तंत्र फेल हो गया। मानसून पूर्व नालों की सफाई के सारे दावे फेल हो गए। इन सब स्थितियों को देखने के बाद सरकार और प्रशासन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। सरकार व्यवस्था दुरुस्त होने के चाहे कितने भी दवे कर ले हकीकत कुछ और ही है। अब दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लगी है। जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार का प्रबंधन कमोबेश पहले से बेहतर होगा। ऐसे में सरकार को समय रहते विश्वसनीय और पुख्ता मापदंडों पर काम करने की जरूरत है ताकि कथनी और करनी में समरूपता दिखे।

मृदुल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

## अति उत्साह का खामियाजा

यह पत्र प्रकाशित सामग्री खतरनाक सेल्फी वाले समाचार के संदर्भ में है। इसमें सेल्फी लेने के चक्कर में चित्रकूटधाम जिले के शबरी जल प्रपात के तेज बहाव में बहकर चार दोस्त के 15 फीट गहरे कुंड में गिरने की चर्चा है। दरअसल सेल्फी के चक्कर में होने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगहों पर बड़े-बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि इससे आगे खतरा है। लेकिन अति उत्साह और सेल्फी के चक्कर में लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

... विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 ...

**50** हजार लोगों पर कराई जा रही थी दुनिया के 40 विभिन्न देशों में रहने वालों की मुखबिरी पेगासस साफ्टवेयर के माध्यम से। इस साफ्टवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ का दावा है कि वह इसे अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल सरकारों को ही बेचती है।

आजकल

# व्यर्थ का हंगामा है पेगासस मामला

**भारत की स्थिर सरकार को अस्थिर करने के हथकंडे पश्चिमी मीडिया लगातार अपनाता रहा है। इसलिए उसने कथित पेगासस प्रोजेक्ट बम ऐसे समय पटका जब संसद का मानसून सत्र आरंभ होना था। लिहाजा पिछले सात वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से मुंह की खा रहे विपक्ष को हंगामे का हथियार मिल गया। हालांकि संसद में विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों को पूर्व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है, फिर भी इसके विविध आयामों को समझना आवश्यक है**



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

डिजिटल साफ्टवेयर पेगासस के जरिये अनेक देशों की सरकारें अपने नागरिकों, विरोधियों व अन्य संदिग्धों की जासूसी करवाती रही हैं। दुनिया की 16 मीडिया संस्थानों ने मिलकर इस कथित तथ्य का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इसके नतीजे पश्चिम के कई प्रमुख अखबारों समेत मीडिया पोर्टल पर जारी किए गए हैं। इनमें 40 भारतीयों के नाम भी बताए जा रहे हैं, जिनमें सभी नामीगिरामी हस्तियां हैं। यदि वास्तव में इन हस्तियों के मोबाइल फोन टेप किए जा रहे थे, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए इन लोगों को अपने फोन फारेंसिक जांच के लिए देने होंगे। इस तथ्य का पर्दाफाश होने से संसद से सड़क तक बेचैनी जरूर है, लेकिन इसके परिणाम किसी अंजाम तक पहुंच पाएंगे इसमें संदेह है।

दरअसल यह मुखबिरी पेगासस के माध्यम से भारत के लोगों पर ही नहीं, बल्कि 40 देशों के 50 हजार लोगों पर कराई जा रही थी। इस साफ्टवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ ने दावा किया है कि इसे वह अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल सरकारों को ही बेचती है। पूर्व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में एनएसओ का पत्र लहराते हुए इस पूरे मामले को नकार दिया। तय है कि सरकार ने ऐसा कोई अनाधिकृत काम नहीं किया है, जो निंदनीय हो अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता हो। इसीलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली फ्रांस की कंपनी फारबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे कोई तथ्य नहीं दिए हैं, जो फोन पर की गई बातचीत को प्रमाणित करते हों? गोया बिना साक्ष्यों के कथित पर्दाफाश व्यर्थ है।

आज लगभग पूरी दुनिया में नीतियां कुछ इस तरह बनाई जा रही हैं कि नागरिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करें। दूसरी तरफ इंटरनेट मीडिया ऐसा ठिकाना है, जिसे व्यक्ति निजी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उपयोग करता है। इस दौरान की गई बातचीत पेगासस साफ्टवेयर ही नहीं, कई ऐसे अन्य साफ्टवेयर भी हैं जो व्यक्ति की सभी गतिविधियों का क्लोन तैयार कर लेने में सक्षम हैं। इसकी खासियत है कि इसके प्रोग्राम को किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो यह हैकर का काम करने लगता है। नतीजतन फोन में संग्रहित सामग्री आडियो, वीडियो, चित्र, लिखित सामग्री, ईमेल और व्यक्ति के लोकेशन तक की जानकारी पेगासस हासिल कर लेता है। इसकी विलक्षणता यह भी है कि यह एनक्रिप्टेड संदेशों को भी पढ़ने लायक स्थिति में ला देता है। पेगासस स्पाईवेयर इजराइल की सर्विलांस फर्म एनएसओ ने तैयार किया है। पेगासस नाम का यह एक प्रकार का वायरस इतना खतरनाक व शक्तिशाली है कि लक्षित व्यक्ति के मोबाइल में मिस्ड काल के जरिये प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह मोबाइल में मौजूद सभी डिवाइसों को एक तो सीज कर सकता है, दूसरे जिन हाथों के नियंत्रण में यह वायरस है, उनके मोबाइल स्क्रीन पर लक्षित व्यक्ति की सभी जानकरियां क्रमवार हस्तांरित होने लगती हैं। लक्षित व्यक्ति की कोई भी जानकारी सुरक्षित व गोपनीय नहीं रह जाती।

वैसे पेगासस या इस जैसे साफ्टवेयर पहली बार चर्चा में नहीं हैं। इजरायली प्रौद्योगिकी से वाट्सएप में सेंध लगाकर करीब 1,400 भारतीय सामाजिक कार्यकताओं व पत्रकारों की बातचीत के डाटा हैक कर जासूसी का मामला भी 2019 में आम चुनाव के ठीक पहले सामने आया था। शायद यह आम चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार की छवि खराब करने की दृष्टि से सामने लाया गया था। उस समय वाट्सएप ने कहा था कि 1,400 मोबाइल फोन में स्पाइवेयर पेगासस डालकर उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी चुराई गई हैं। यह जानकारी तब चुराई गई थी, जब भारत में 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में विपक्ष ने यह आशंका जताई थी कि इस स्पाइवेयर के जरिये विपक्षी नेताओं और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्षरत लोगों की अपराधियों की तरह जासूसी कराई गई। हालांकि इस मामले में भी अब तक कोई तथ्यपूर्ण सच्चाई सामने नहीं आई है।

वैसे आइटी कानून के तहत भारत में कार्यरत कोई भी वेबसाइट या साइबर कंपनी यदि व्यक्ति विशेष या संस्था की कोई गोपनीय जानकारी जुटाना चाहती है तो केंद्र व राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। निजता गोपनीय बनी रहे, लिहाजा ऐसे मामले सामने आने पर सरकार भी इस सुरक्षा के प्रति, प्रतिबद्धता जताती रही है। वैसे सरकारों द्वारा अपने विरोधियों के मोबाइल फोन टेप करने के मामले यदा-कदा सामने आते ही रहते हैं। जो कांग्रेस पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा बरपाए हुए है, उसी कांग्रेस की वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह सरकार में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और राजनीतिक लाबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत का टेप लीक हुआ था। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर यह बड़ा संकट था। बाद में यह भी पर्दाफाश हुआ कि यूपीए सरकार और कई मोबाइल फोन टेप करा रही थी।

हालांकि भारत में 10 ऐसी सरकारी गुप्तचर जांच एजेंसियां हैं, जो आधिकारिक रूप से संदिग्ध व्यक्ति अथवा संस्था की जांच कर सकती हैं। भारत में संचार उपकरण से जुड़ा पहला बड़ा मामला पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जासूसी से जुड़ा है। उस फोन टैपिंग के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति के पत्रों की जांच करने का आरोप राजीव गांधी सरकार पर लगा था। इसी तरह पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के दफ्तर में भी जासूसी यंत्र 'बग' मिलने की घटना सामने आई थी। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस तरह के रहस्यों का पर्दाफाश होने से इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लेकर लोगों के मन में संदेह स्वाभाविक है। लिहाजा सरकार को अपनी जवाबदेही स्पष्ट करने की जरूरत है। लेकिन हंगामे के बीच सफाई कैसे दी जाए? शोर थमे तब तो सरकार का स्पष्टीकरण सामने आए? लिहाजा संसद में शोर थमना चाहिए।



पेगासस साफ्टवेयर के जरिये मोबाइल फोन में घुसपैठ करते हुए जासूसी करने से जुड़ा सच सामने आना चाहिए। प्रतीकात्मक

## धुआं उठ रहा है तो आग भी लगी होगी

अभय कुमार 'अभय'

अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो आग भी कहीं अवश्य लगी होगी। इसलिए इस खबर को सिरे से खारिज करना उचित नहीं होगा कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिये प्रमुख हस्तियों की जासूसी की गई थी। खबरों में बताया जा रहा है कि एक मिस काल देकर स्पाईवेयर को टार्गेटेड स्मार्टफोन में इनस्टाल कर दिया जाता है, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति का पूरा डाटा, उसकी बातचीत, वह कहां आता जाता है आदि की जासूसी करना आसान हो जाता है। हद तो यह है कि स्मार्टफोन बंद होने पर भी इस स्पाईवेयर से उसका कैमरा आन किया जा सकता है, जिससे यह मालूम हो जाता है कि वह व्यक्ति किससे कहां मुलाकात कर रहा है।

इसलिए इस संदर्भ में इलेक्ट्रानिक्स व इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, 'यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास है, क्योंकि इस प्रकार के दावे अतीत में मुंह के बल गिरे हैं।' जबकि उन्हें केवल इतना बताना था कि भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं। संक्षेप में बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार 2019 की तरह इस बार भी कोई सीधा व स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजराइली कंपनी एनएसओ ग्रुप अपना यह साफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचती है और वह भी सिर्फ आतंकी गतिविधियों को रोकने व जांच हेतु जासूसी करने के लिए। इसका इस्तेमाल करने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है, क्योंकि पेगासस एक साइबर हथियार है, जिसके लिए आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकारें इसका दुरुपयोग राजनीतिक व अन्य जासूसी करने के लिए करती हैं। इसलिए पेगासस स्पाईवेयर को लेकर बार बार गंभीर सवाल उठते हैं। संतोषजनक उत्तर की गैर-मौजूदगी में यह प्रश्न निरंतर उठता रहेगा। अक्टूबर 2019 में यह तथ्य सामने आया था कि भीमा कोरेगांव जांच से जुड़े अनेक संबंधित कार्यकर्ताओं को पेगासस से टारगेट किया गया था। कहा गया था कि उनके वाट्सएप पर मिस काल दी गई और उनके स्मार्टफोन पर स्पाईवेयर इनस्टाल कर दिया गया। तब इस पर जब काफी शोर मचा था तो सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था। उस जांच का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम।

बहरहाल, दुनिया की वे सरकारें भी दूध की धुली हुई नहीं हैं, जो पेगासस की सूची में नहीं हैं। टेक्नोलाजी में विकसित देशों के पास जासूसी के अन्य साफ्टवेयर टूल्स हैं। पिछले साल अमेरिका के 'कोर्ट आफ अपील्स' ने कहा कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने जो बड़ी संख्या में घरेलू फोनों को सर्विलांस पर रखा वह असंवैधानिक था।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि नागरिकों की निजता को इस प्रकार की जासूसी से लोकतंत्र में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों को मिलकर प्राइवेट स्पाईवेयर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा करने से वैध सुरक्षा जरूरतों से समझौता नहीं होगा, केवल सत्ता के आशंकित दुरुपयोग से सुरक्षित रहने की राहें निकलेंगी। भारत में व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा कानून की जरूरत है, ताकि अवैध घुसपैठ से कानूनी सुरक्षा मिल सके। दिसंबर 2019 में संसद में डाटा सुरक्षा विधेयक पेश किया गया था, जो अभी तक विचाराधीन है। प्रासंगिक संशोधन के साथ इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता है। दरअसल यह विधेयक पीड़ित को कोई राहत उपलब्ध नहीं कराता है, जबकि आज स्पाईवेयर एक आम आदमी भी आसानी से हासिल कर सकता है। इस विधेयक में कहा गया है कि डाटा उल्लंघन की स्थिति में सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेटर को सूचित करना होगा। आशंकित हानि की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए रेगुलेटर तय करेगा कि पीड़ित को जानकारी दी जाए या नहीं। कुल मिलाकर यह विधेयक कमजोर है, इसकी जगह नया विधेयक लाना चाहिए। इसलिए भी, क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट व इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी एक्ट के तहत सर्विलांस ताकतों को नियंत्रित करने के कोई प्रविधान नहीं हैं।

(लेखक सामाजिक अध्येता हैं)

खरी-खरी

## किंतु, परंतु, मगर, बट, लेकिन...

आशीष दशोत्तर

कमाल हो गया। शब्दों में इतनी शक्ति होती है, उन्हें इसका एहसास पहली बार हुआ। पांच तत्वों से बनी उनकी काया निष्प्राण होने के करीब थी। उनका महान व्यक्तित्व अवसान के निकट था। ऐसे नाजुक मोड़ पर उन्हें पांच शब्दों ने जीवनदान दे दिया। लगभग व्यर्थ और निष्प्रभावी करार दिए जा चुके उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने यह नया जीवन पाने के पहले कितने कष्ट सहे, पूछिए मत। अक्सर व्यक्ति इस बात से दुःखी रहता है कि उसकी कही छोटी सी बात पर लोग क्या-क्या कह डालते हैं। मगर इनके साथ मामला अलग था। इनकी किसी भी बात पर कोई कुछ कहता ही नहीं था। यही इनके लिए चिंता का कारण था।

वे हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देते मगर उनकी प्रतिक्रिया पर किसी की क्रिया नहीं होती। अब तक वे क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम को नहीं समझ पाए थे। इस चक्कर में कई बार न्यूटन को कोसते, जिसने हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया की बात तो कही मगर 'प्रतिक्रिया पर क्रिया' का पर्दाफाश नहीं किया।

जब से उनके जीवन में किंतु, परंतु, मगर, बट, लेकिन 'पंच तत्वों' का समावेश हुआ है, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ गया है। उनकी प्रतिक्रिया को बराबर सम्मान मिलने लगा। उन्हें अब समझ आया कि गरिष्ठ जिस प्रकार पचता नहीं, उसी प्रकार वरिष्ठ किसी को पचाता नहीं। लिहाजा उन्होंने भी अपने जीवन में इन पांच शब्दों का समावेश कर स्वयं को वरिष्ठ बना लिया।

पहले वह किसी भी बात पर सीधी प्रतिक्रिया दे दिया करते थे, जो अक्सर प्रशंसा का भाव लिए होती थी। उस पर कोई गौर नहीं करता था। सबको लगता था कि यह बहुत सामान्य सी प्रतिक्रिया है। जब से 'पंच शब्दीय पंच' शामिल किया, उनकी गाड़ी कहीं पंचर नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी लिखी प्रतिक्रियाओं को निकाला, उनमें किंतु-परंतु का तड़का लगाया और फिर से छपने के लिए भेज दिया। पिछली बार अस्वीकृत हुई रचनाएं इस बार तत्काल स्वीकृत हो गईं। शब्द शक्ति के चमत्कार से वे अभिभूत हैं। इन पांच शब्दों से प्राप्त सफलता के बाद वे किसी भी नए शब्द को सीखने के मूड में नहीं है।

## ट्वीट-ट्वीट

भारत में भी तालिबान की घुसपैठ हो चुकी है। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या के बाद भी जिस तरह कुछ पत्रकार-बुद्धिजीवी तालिबानी आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, उससे साफ है कि कई लोगों के दिलोदिमाग में तालिबान घुसपैठ कर चुका है।
अशोक श्रीवास्तव@AshokShrivasta6

अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा दिया। इस लिहाज से काबुल में तालिबानी सरकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, लेकिन यह असल में उसके लिए बुरी खबर है। एक तो पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों पर नियंत्रण गंवा दिया है, जो अफगानिस्तान को गृहयुद्ध में झोंक देंगे। वहीं डूरंड रेखा पर पश्तून शरणार्थियों का संकट अलग से खड़ा हो जाएगा।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant



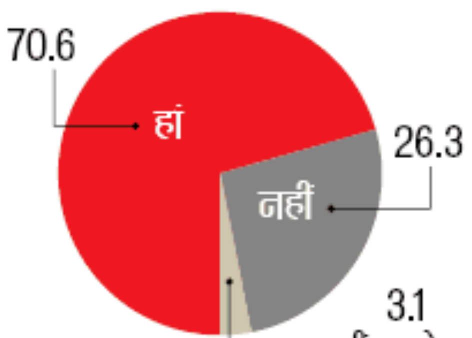
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को बदलकर दिखा दिया कि वहां लोकतंत्र अभी जीवित है। पूर्व प्रधानमंत्री के दौर में चीन ने नेपाल में अपनी गहरी पैठ बनाई। अब भारत को भी अपनी विदेश नीति में सुधार करना चाहिए। इस कड़ी में नेपाल को तुरंत कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

यह कितने शर्म की बात है कि हाई प्रोफाइल अमीर सेलेब्रिटी पोर्न के जरिये कमाई करते हैं।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या विपक्ष को प्रधानमंत्री को संसद में अपने मंत्रियों का परिचय कराने का अवसर देना चाहिए था?**




सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**
क्या पेगासस मामला संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए उछाला गया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

इज्जत, शोहरत, धन उन्हें शायद हजम न होय,
उल्टे-सीधे काम कर रहे प्रतिष्ठा खोय।
रहे प्रतिष्ठा खोय कभी वो खेलें सट्टा,
कभी फिल्म अश्लील बना लगवाएं बट्टा।
खुद अपना सम्मान बेच करवाएं हुज्जत,
गलत करें पतिदेव गंवाए पत्नी इज्जत!
– ओमप्रकाश तिवारी

उत्तराखंड डायरी

# राज्य में कांग्रेस का असमंजस



कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मसला सुलझ गया है। तमाम दुश्वारियों के बाद पार्टी हाईकमान ने हल निकाल ही लिया। पंजाब की इस समस्या के समाधान के बाद उत्तराखंड के कांग्रेसी भी खासे उत्साहित हैं। चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्य में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का मसला करीब एक माह से लटका हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का पद तो डा. इंदिरा हृदयेश के देहावसान के कारण रिक्त हुआ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलने का सुझाव हाईकमान तक पहुंच रखने वाले बड़े नेताओं का है। इनमें प्रदेश की राजनीति पर खासी पकड़ रखने वाले हरीश रावत प्रमुख हैं।

पिछले लगभग चार वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को इंदिरा हृदयेश से खासी ताकत मिलती थी। अब उनकी स्थिति कमजोर देखते हुए पार्टी का एक बड़ा धड़ा उन्हें बदलने की पुरजोर वकालत करने लगा है। प्रांत में अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन यूं तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह की खींचतान चल रही है, उससे यह जाहिर होता है कि कांग्रेस के लिए यह सात माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंजाब में तो सरकार भी कांग्रेस की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में तो पार्टी को संगठन के बूते ही लड़ना होगा। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष की अहमियत बढ़ गई है।

पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हरीश रावत स्वयं उत्तराखंड कांग्रेस के कैप्टन हैं। यहां प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा उठाने, उलझाने, गरमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हरीश रावत इसके समाधान में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस दौरान वह स्वयं पंजाब कांग्रेस को लेकर मसरूफ रहे, अब उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए उपलब्ध होंगे।



पंजाब के बाद उत्तराखंड में पार्टी की समस्याओं को सुलझाने पर जोर : हरीश रावत। फाइल



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कायम रहने में मुश्किलों का सामना : प्रीतम सिंह। फाइल

पार्टी हाईकमान के लिए भी पंजाब संकट उत्तराखंड के मुकाबले ज्यादा गहरा था। यही वजह है कि छोटे राज्य का मसला वरीयता नहीं प्राप्त कर सका। प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। कभी उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में एकाधिकार सा रखने वाली पार्टी वर्तमान में सियासी मुफलिसी से गुजर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो कई पार्टी दिग्गज भाजपा में शामिल हो गए। विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज, डा. हरक सिंह, यशपाल आर्य जैसे दिग्गजों का कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका था कि अभी तक पार्टी पटरी पर नहीं आ पाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश का गुजर जाना भी पहले से ही बड़े चेहरों की कमी से जूझ कांग्रेस के लिए बड़ी हानि रही। चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा घोषित करने का अघोषित अभियान चला रहे हरीश रावत अब अपने स्तर का अकेला चेहरा रह गए हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रांतीय नेता अब भी कह रहे हैं कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही होगा। पार्टी हाईकमान का रुख भी सामूहिक नेतृत्व की तरफ रहा है। यही देखते हुए रावत को भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाले धड़े ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग को हवा दी। अगर रावत अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनपसंद को बिठा पाए, तो बिना कुछ किए ही वह चुनाव में कांग्रेस का स्वाभाविक चेहरा हो जाएंगे। इसके अलावा, टिकट वितरण में भी वह निर्णायक हो जाएंगे। इस अंदेशे को देखते हुए पार्टी में उनके विरोधी सतर्क और सक्रिय हो गए हैं।

हरियाणा डायरी

# संयुक्त किसान मोर्चा के लिए सिरदर्द बने तीन नेता



जगदीश त्रिपाठी
प्रभारी, हरियाणा स्टेट डेस्क

तीनों नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में चल रहे आंदोलन को एक तरफ हरियाणा के ही किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (मान) के प्रदेश अध्यक्ष गुणीप्रकाश ने चुनौती दे दी है, तो वहीं आंदोलन के नेता खुद भी कई गुटों में बंट गए हैं। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला आजकल तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जारी धरनास्थलों पर पहुंचने लगे हैं। उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है। राकेश टिकैत स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राजनीतिक दलों के नेताओं से दूरी बनाए रखने की बात कहते रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत निरंतर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, गुरनाम चढूनी जो हरियाणा के किसान संगठनों की तरफ से संयुक्त मोर्चे में एकमात्र प्रतिनिधि थे (यदि आप योगेंद्र यादव को किसानों का प्रतिनिधि मानते हों तो बात अलग है), उन्हें संयुक्त मोर्चे ने चार दिन पहले एक सप्ताह के लिए इस आधार पर निलंबित कर दिया कि उन्होंने पंजाब के किसान संगठनों को सुझाव दिया था कि वे एकजुट होकर पंजाब विधानसभा के चुनाव लड़ें और वहां अपनी सरकार बनाएं। वे अपनी सरकार को देश भर में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके लिए हरियाणा का उदाहरण देते हुए चढूनी ने कारण भी गिनाए थे। चढूनी का कहना था कि किसानों के सहयोग से चौधरी भजनलाल की सरकार आई, उस सरकार में भी किसान पीड़ित हुए। भजनलाल का विरोध कर चौधरी बंसीलाल की सरकार बनाई गई। बंसीलाल की सरकार में भी किसानों का उत्पीड़न हुआ। बंसीलाल के बाद चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार बनवाई गई तो उस सरकार में भी किसानों पर गोलियां चलीं।



हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से संयुक्त मोर्चे में थे प्रतिनिधि : गुरनाम चढूनी।



पूर्व में अपनी ही कही गई बातों पर नहीं कर रहे अमल : राकेश टिकैत। फाइल



किसानों पर अपनी पकड़ कायम रखने का दावा : ओमप्रकाश चौटाला। फाइल

हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे के किसी नेता ने चढूनी के तर्कों पर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें निलंबित जरूर कर दिया। इससे हरियाणा के किसान संगठन क्षुब्ध हो गए हैं। उनका कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हरियाणा के किसान नेताओं के सुझाव सिरे से खारिज कर देते हैं। यह नहीं चलेगा। उनका आरोप है कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी साथियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसान मोर्चा की बैठक में हरियाणा की तरफ से दिए जाने वाले सभी सुझावों को निरस्त किया जाता है। इस बीच हरियाणा के संगठनों का आरोप है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक ही तरह की गलती करने वाले तीन नेताओं को दंडित करने के लिए अलग-अलग मापदंड अपना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने की घोषणा की तो उस बयान को वापस लेने की बात कहकर माफ कर दिया गया।

दो अन्य किसान नेताओं युद्धवीर सिंह सहरावत और योगेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे निर्दलीय विधायक विधायक सोमवीर सांगवान को योजनाबद्ध रूप से संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल करने के लिए बुलाया। इसका विरोध हुआ। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने दोनों को निलंबित करने के लिए कमेटी बनाने की बात कह दी।

विचारणीय है कि हरियाणा से जुड़े आंदोलनकारी अब कुंडली बार्डर पर जाने से भी परहेज करने लगे हैं। वे अब मध्य हरियाणा में धरने पर जोर दे रहे हैं। टीकरी बार्डर पर जरूर हरियाणा के संगठनों से जुड़े लोग भागीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चढूनी और टिकैत मुखर होकर भले ही संयुक्त किसान मोर्चे पर काबिज पंजाब के नेताओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के संगठनों के नेताओं को महत्वहीन करने में जरूर जुट गए हैं। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प यह भी है कि राकेश टिकैत और चढूनी में आपस में भी टकराव है।

आंदोलनकारियों को भी अब लगने लगा है कि उनका टेंट उखड़ सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो गुणीप्रकाश के साथ बड़ी संख्या में किसान भी आंदोलनकारियों के विरोध में रहे हैं तो कुंडली बार्डर पर आंदोलनकारियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने के विरोध में हेमंत नांदल के नेतृत्व में वहां के आसपास के किसान, ग्रामीण और उद्यमी लामबंद हैं। टीकरी बार्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए वहां के उद्यमी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना बना रहे हैं।

दूसरा कारण यह है कि भले ही संयुक्त किसान मोर्चे के नेता कहें कि वह किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को मंच नहीं साझा करने देंगे, लेकिन ओमप्रकाश चौटाला धरनस्थलों पर गए तो वह जहां खड़े होकर बोलने लगेंगे वही मंच हो जाएगा और आंदोलनकारियों के पंडाल की सारी भीड़ चौटाला लूट लेंगे। यदि ऐसी स्थिति में पंजाब के संगठनों के नेता ओमप्रकाश चौटाला का विरोध करने का साहस करते हैं तो वहां जुटी भीड़ उनकी दुर्गति भी कर सकती है। इसलिए चौटाला को सम्मान देने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं होगा। चौटाला, चढूनी और टिकैत को कैसे हाशिए पर करें, यह पंजाब के नेताओं और योगेंद्र यादव जैसे उनके साथियों को नहीं सूझ रहा है।

**42.72** फीसद थी 2016 में भारत में स्टेम स्नातकों में महिलाओं की भागीदारी। अमेरिका में 33.99, जर्मनी में 27.14, ब्रिटेन में 38.10, फ्रांस में 31.81 व कनाडा में 31.43 फीसद थी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 21 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

# प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती

उत्तराखंड में मानसून के रफ्तार पकड़ते ही प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में तीन ग्रामीण जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में मलबा आने से 150 से ज्यादा संपर्क मार्ग बंद हैं और सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। हालात को देखते हुए कुमाऊं के प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के साथ प्राकृतिक आपदाओं का चोली-दामन जैसा रिश्ता है। विशेषकर चौमासे में कुदरत कब कुपित हो जाए कहा नहीं जा सकता। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं में जान माल की हानि होती है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आपदा से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रविवार रात उत्तरकाशी जिले में आई आपदा के बाद तंत्र की सक्रियता सराहनीय रही। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात से ही मामले पर नजर बनाए रहे। प्रशासनिक अमला भी सूचना मिलते ही घटनास्थल की ओर रवाना हो गया था। यह अलग बात है कि रास्ते बंद होने के कारण टीम को मौके पर पहुंचने में वक्त लग गया। दूसरा अंधेरा होने के कारण राहत कार्यों में दिक्कत भी हुई। उत्तराखंड का विषम भूगोल हमेशा ही एक चुनौती रहा है। अक्सर देखने में आता है कि बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं रात को अथवा तड़के होती हैं। ये ऐसा समय है जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं। ऐसे में जान बचाने के लिए समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा, सुदूर पहाड़ों तक राहत पहुंचाना भी आसान नहीं है।

> प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती नई बात नहीं है। आवश्यकता यह है कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए सही सिस्टम विकसित किया जाए

दरअसल, इस हिमालयी राज्य में आपदाओं पर भले ही नियंत्रण करना संभव नहीं, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। विडंबना ही है कि सिस्टम इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया। प्रदेश में तीन स्थानों पर डाप्लर रडार लगाए जाने थे। यह कवायद वर्ष 2008 से चल रही है। बावजूद इसके अब तक मुक्तेश्वर में ही डाप्लर रडार स्थापित हो पाया है। वहीं टिहरी जिले के सुरकंडा और पौड़ी जिले के लैंसडौन में अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है।

इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए जाने थे। चमोली के रैणी गांव में फरवरी में आई आपदा के बाद इस मामले में तेजी भी आई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। आपदा के प्रभाव को कम करने का एकमात्र तरीका सतर्कता ही है। इसे सरकार के साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा और उसी अनुरूप व्यवहार करना होगा।

बिहार

# बालू की कीमतों पर नियंत्रण

भवन निर्माण चाहे निजी हो या सरकारी, बालू के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। अभी इसके खनन से लेकर वितरण तक की दोषपूर्ण व्यवस्था से बालू की किल्लत है। दाम भी अनाप-शनाप हैं। दोषपूर्ण व्यवस्था सबके सामने आ चुकी है। बालू माफिया से साठ-गांठ पर दो एसपी समेत दर्जनों पुलिस अफसरों का स्थानांतरण, निलंबन और जेल भेजने की कार्रवाई हो चुकी है। सैकड़ों माफिया भी जेल जा चुके हैं। बालू से अफसरों की काली कमाई पर आर्थिक अपराध इकाई की नजरें हैं। अब सरकार ने सिरदर्द बने बालू के दाम और वितरण को व्यवस्थित करना शुरू किया है।

फिलवक्त सरकार की कोशिश बालू की मनमानी कीमत पर अंकुश लगाने की है। उसने राजधानी पटना में बालू की अधिकतम कीमत चार हजार रुपये प्रति सौ सीएफटी और अन्य जिलों में 3,900 रुपये सीएफटी तय की है। भंडार स्थल अथवा घाट से बालू परिवहन का प्रति किमी शुल्क तय करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और परिवहन विभाग को दी है। अभी स्थिति यह है कि घाट से चार हजार रुपये सीएफटी वाला बालू 40-50 किमी दूर शहर पहुंचने


राज्य में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध कारोबार। फाइल

> बिहार में बालू का खेल सुर्खियों में है। इसके अवैध खनन और मनमानी कीमत ने राज्य सरकार को भी परेशान कर रखा है। वह इसे व्यवस्थित करने में लग गई है

पर 13 से 14 हजार रुपये का हो जाता है। इससे मकान बनवाने वाले आम लोगों के साथ बिल्डर और सरकारी कार्य कराने वाले ठेकेदारों के रोने की नौबत आ जाती है। बड़ी वजह यह है कि बारिश में खनन बंद होने की स्थिति में स्टाक बालू का उठाव नहीं हो रहा था। यह बालू घाट पर खनन का ठीका लेने वाली कंपनियों का है जो भाग खड़ी हुई हैं। ऐसे में माफिया अवैध खनन कर रहे हैं और उनका बालू घाट से शहर आते-आते पुलिस की वसूली का शिकार होने के बाद तीन गुना तक महंगा हो जाता है। चिंतित सरकार ने अब बालू की कीमतों पर अंकुश की कवायद शुरू की है। खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव ने कई जिलों के डीएम के साथ बालू की उपलब्धता, कीमत और परिवहन शुल्क को लेकर वीडियो कांफ्रेंस कर निर्देश दिए हैं कि वे कीमतें तय करने के साथ प्रति किमी बालू ढुलाई का परिवहन शुल्क भी निर्धारित करें। इससे कुछ हद तक हालात सुधरने की उम्मीद की जा सकती है।

झारखंड

# खदानों की ई-नीलामी

झारखंड सरकार लौह अयस्क के बंद खदानों को खोलने के लिए विभागीय स्तर पर ई-नीलामी कर रही है। कुछ अपरिहार्य कारणों से अंतिम समय में यह नीलामी प्रक्रिया सोमवार को रोक दी गई। इससे इतर सरकार के स्तर से बंद खदानों को खोलने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है। जिन खदानों की लीज समाप्त हो चुकी है, नए सिरे से उनकी बोली अब ई-नीलामी के माध्यम से ही लगेगी। पड़ोसी राज्य ओडिशा में मार्च 2020 से पहले ही अधिकतर खदानों की नीलामी हो चुकी है। झारखंड में खदानों के बंद हुए तकरीबन डेढ़ साल से अधिक समय हो गए हैं। नीलामी की प्रक्रिया देर से ही सही, लेकिन अब शुरू हो जाने के बाद इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खदानें बंद होने से सरकार को हजारों करोड़ रुपये का अलग से नुकसान हो रहा है। सोमवार को जिस अजिताबुरू लौह एवं मैंगनीज अयस्क ब्लाक की ई-नीलामी होने वाली थी, सरकार को उससे तकरीबन साढ़े चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने की उम्मीद है।


रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने में खदानों की है अहम भूमिका। फाइल

> खदानों के चालू हो जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार को राजस्व मद में हजारों करोड़ का मुनाफा भी होगा

झारखंड में लौह अयस्क खनिज का सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। यहां पर करीब 41 लौह अयस्क खदानें पूर्व में लीज पर दी गई थी। 31 मार्च 2020 को अधिकतर निजी खदानों की लीज समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में केवल टाटा स्टील और सेल की खदानें ही चालू हालत में हैं। इस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था खदानों पर ही निर्भर है। खदानों के चालू होने से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। खदानों के चालू होने से एक साथ हजारों लोगों को खदान के अंदर काम तो मिलता ही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। यहां के लोगों को अपने घर के आसपास ही काम मिल जाता है और आजीविका की तलाश में उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। खदानों के चालू हो जाने से कंपनियां भी सीएसआर फंड से क्षेत्र के विकास के लिए काम करतीं। ई नीलामी की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर खदानों के लीज आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

बंगाल

# बिना मास्क घूमने वालों पर शिकंजा

कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें बार-बार लोगों को सजग-सतर्क और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील करती रही हैं। परंतु देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर सरकार की अपीलों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर सिर पर है। बावजूद इसके वे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घूमने-फिरने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इससे दार्जिलिंग जैसे जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ममता सरकार भी प्रशासन से कोरोना के नियम पालन कराने को सख्त कदम उठाने का निर्देश दे रखा है। बावजूद इसके बसों से लेकर बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर लोग बिना मास्क लगाए टहलते नजर आ रहे हैं।

अभी दो दिन पहले ही बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोरोना नियमों की अवहेलना करने पर किसी को भी रियायत न दें। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। परंतु देखा जा रहा है कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से दार्जिलिंग, तारापीठ, दीघा जैसे पर्यटन स्थलों पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके लोग पहुंच जा रहे हैं। बंगाल में अभी हर दिन कोरोना के नए मामले 700 से लेकर एक हजार के बीच आ रहा है। मौतें भी हो रही हैं। राज्य प्रशासन की ओर से बार-बार लोगों को हिदायत व चेतावनी दी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। कोरोना की वजह से कुछ रियायतों के साथ बंगाल में लाकडाउन 30 जुलाई तक जारी है। फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है।

> ममता सरकार ने प्रशासन से कोरोना के नियम पालन कराने को सख्त कदम उठाने का निर्देश दे रखा है। बावजूद इसके सार्वजनिक स्थानों पर लोग बिना मास्क लगाए टहलते नजर आ रहे हैं

यही वजह है कि प्रशासन को पर्यटन केंद्रों के अलावा विभिन्न बाजारों में कोरोना नियमों को सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इसकी रूपरेखा नए सिरे से तैयार करना पड़ रहा है। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब राज्य पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सख्ती और बढ़ाए। नहीं तो कुछ के चलते सभी लोग परेशान हो रहे हैं। बस से लेकर अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी लोग अब भी बिना मास्क लगाए सफर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इंसानियत के दुश्मन न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? बार-बार कहने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लिहाजा सरकार को सख्ती अपनाने के साथ ही जुर्माना की रकम बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए।

# नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को गति देने के लिए बनी नई रणनीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

**कवायद**

- उच्च शिक्षण संस्थानों व एजेंसियों को हर अपडेट की देनी होगी जानकारी
- शिक्षा मंत्रालय स्तर पर इसे लेकर तैयार किया गया एक नया पोर्टल

कोरोना संकट काल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल की सुस्त पड़ी रफ्तार को फिर से गति देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से नीति के अमल में अब तक हुई प्रगति की रिपोर्ट मांगें जाने के बाद इसे लेकर हलचल और बढ़ी हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने अब नीति के अमल पर नजर रखने के लिए एक पोर्टल भी तैयार करने की योजना बनाई है। जिसमें शिक्षा नीति के अमल से जुड़ी सभी एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी अपडेट करनी होगी।

इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर नीति के सुझावों को संपूर्णता के साथ लागू करने को कहा है, ताकि देश की 21वीं सदी की जरूरतें पूरी हो सकें। यूजीसी ने मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत बताई है, उनमें कला, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रोफेशनल, तकनीक और व्यवसायिक क्षेत्र शामिल है। इसके साथ ही स्किल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाओं पर भी फोकस करने को कहा है।

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली हर नई पहल को अपने संस्थान की वेबसाइट पर भी साझा करने को कहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर यह हलचल इसलिए भी बढ़ी हुई है, क्योंकि कोरोना के चलते शिक्षा नीति के अमल के लिए तय किए गए कई टास्क पर तय समयसीमा से काम


नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से प्रगति की रिपोर्ट मांगें जाने के बाद हलचल और बढ़ी। फाइल

नहीं शुरू हो पाया है। वैसे भी शिक्षा नीति के अमल को लेकर जो टास्क बनाया है, उनमें ज्यादा टास्कों पर वर्ष 2024 तक काम होना है। इनमें भी अगले दो सालों में करीब 70 फीसद टास्क पर काम होना है। ऐसे में इसके अमल में देरी हुई तो नीति के अमल में आगे भी देरी दिखेगी। केंद्र सरकार नीति के अलम को लेकर इसलिए भी सतर्क है, क्योंकि इससे पहले जो नीति आयी थी, वह समय पर लागू होने के चलते अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इससे बचने की जरूरत पर बल दिया गया है।

# 'बाइक के साइलेंसर की तेज आवाज एकांतता के अधिकार का हनन'

जासं, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तमाम देशी विदेशी दुपहिया वाहनों के साइलेंसर में मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रविधानों को दरकिनार कर मनमर्जी से परिवर्तन कराकर कानफोड़ू आवाज पैदा करने को लोगों की आजादी में खलल माना है। कोर्ट ने इसे एकांतता के अधिकार का हनन करार देते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसी मोटरसाइकिलें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से हलफनामा मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तय की है। यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने 'मोडिफाइड साइलेंसरों से ध्वनि प्रदूषण' टाइटिल से जनहित याचिका दर्ज करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि बुलेट व दूसरी बाइकों में आजकल साइलेंसर में परिवर्तित करा कर तेज आवाज में चलाने का फैशन हो गया है। इससे बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर भारी दिक्कतें होती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 को उधृत करते हुए कहा कि इसके तहत वाहनों में परिवर्तन प्रतिबंधित है।

कोर्ट ने इसी एक्ट की धारा 190(2) का भी जिक्र किया जिसके तहत ध्वनि व वायु प्रदुषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का प्रविधान है। कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, विदेशी बाइकों जैसे हर्ले डेविडसन, ह्योसंग, यूएन कमांडो आदि पर भी लागू होता है।

# कड़ी सुरक्षा में निकली बाहुड़ा रथयात्रा

जाटी, भुवनेश्वर

- सिंहद्वार पहुंचे चतुर्धा विग्रह, महाप्रभु की बाहुड़ा यात्रा संपन्न
- बुधवार शाम की चतुर्धा विग्रहों को रथों के ऊपर सोने के वेश में सजाया जाएगा

कड़ी सुरक्षा के बीच जगन्नाथ धाम पुरी में मंगलवार को चतुर्धा विग्रहों की बाहुड़ा (घर वापसी) यात्रा निकाली गई। बाहुड़ा यात्रा के लिए गुंडिचा मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगल आरती संपन्न किए जाने के बाद तड़प लागी, अवकाश नीति, द्वारपाल पूजा, सूर्यपाल पूजा, रसोई होम, खिचड़ी भोग लगाया गया। सुबह 7:40 बजे चतुर्धा विग्रहों की बाहुड़ा पहंडी बिजे शुरू हुई। सर्वप्रथम सुदर्शन की पहंडी बिजे कर रथ पर लाया गया। इसके बाद प्रभु बलभद्र फिर देवी सुभद्रा एवं अंत में महाप्रभु जगन्नाथ की पहंडी बिजे कर रथ पर विराजमान किया गया। पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर चतुर्धा विग्रहों की पहंडी बिजे संपन्न करा ली गई। वहीं, रथ पर रीति-नीति संपन्न हो जाने के बाद गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव को पालकी में लाया गया। तमाम रीति-नीति संपन्न होने के बाद सेवकों द्वारा रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई।

सर्वप्रथम 12 बजकर 20 मिनट पर प्रभु बलभद्र के रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर एक बजे देवी सुभद्रा का रथ एवं अंत में एक बजकर 22 मिनट पर महाप्रभु के रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। कोविड संक्रमण के कारण भक्तों के आगमन पर प्रतिबंध लगाए जाने से तीनों रथों को जगन्नाथ मंदिर के सेवकों द्वारा गुंडिचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार तक खींचकर लाया गया। सबसे पहले तीन बजकर 50 मिनट पर भगवान बलभद्र का रथ पहुंचा। इसके बाद देवी सुभद्रा का रथ चार बजकर 20 मिनट पर तथा अंत में जगन्नाथ प्रभु का रथ पांच बजकर 40 मिनट पर लाया गया।


ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में निकाली गई चतुर्धा विग्रहों की बाहुड़ा यात्रा में भाग लेते श्रद्धालु। प्रेट्र

**मौसी मां द्वारा बना पोड़ पीठा समर्पित किया गया :** गुंडिचा मंदिर रत्न सिंहासन को बिजे कर रहे चतुर्धा विग्रहों को पूजा पंडा सेवकों द्वारा रास्ते में मौसी मां मंदिर बलगंडी चौक पर मौसी मां द्वारा बनाए गए पोड़ पीठा समर्पित किया गया। वहीं, महाप्रभु का रथ सिंहद्वार पहुंचने से पहले लक्ष्मी-नारायण भेंट नीति संपन्न की गई। उसके बाद पुनः भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। पांच बजकर 40 मिनट पर प्रभु का रथ सिंहद्वार के सामने पहुंच गया। महाप्रभु पुरी रात रथ पर ही विराजमान रहेंगे।

**बाहुड़ा यात्रा में भी रही त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था :** इधर, महाप्रभु की बाहुड़ा यात्रा में किसी प्रकार की अड़चन न आने पाए, इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था रही। पुरी की नाकेबंदी करते हुए पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। बाहरी लोगों के प्रवेश पर तो रोक लगा ही, पुरी शहर के अंदर रहने वाले खासकर बड़दांड में रहने वाले लोगों को भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। दोनों ओर स्थित भवनों पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है।

**आज रथ पर होगा चतुर्धा विग्रहों का सोना वेश :** बुधवार को शाम की धूप नीति संपन्न होने के बाद चतुर्धा विग्रहों को रथों के ऊपर सोने के वेश में सजाया जाएगा। गुरुवार को देवी-देवताओं को अधरपणा भोग लगाया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को महाप्रभु भाई-बहन के साथ नीलाद्री बिजे में निकलकर रत्न सिंहासन पर विराजमान होंगे।

# 'कर्मचारियों का वेतन रोकना अधिकारों का उल्लंघन'


नैनीताल हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। फाइल/इंटरनेट मीडिया

जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को पिछले छह माह से वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जो 34 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए हैं वह आज या कल तक परिवहन निगम को दें। भविष्य में कर्मचारियों के वेतन के मामले में विस्तृत प्रस्ताव आगामी कैबिनेट मीटिंग में रखने को भी कहा, ताकि यह समस्या बार-बार न आने पाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों का वेतन रोकने या कटौती करने का अधिकार नहीं है। वेतन रोकना संविधान और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रोडवेज कर्मचारी यूनियन व रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाकर निर्णय लेने के निर्देश केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को दिए गए थे, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ।

कोर्ट ने तीन माह के भीतर दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों से बैठक कर परिसंपत्तियों के बंटवारे पर निर्णय लेने के सख्त निर्देश दिए। कहा कि उत्तराखंड बने 21 साल होने को हैं, मगर अब तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सका है, जबकि केंद्र तथा दोनों राज्यों में एक ही दल की सरकार भी है। मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।

**सरकार को कटौती पर फटकार :** परिवहन निगम की तरफ से कहा गया कि जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों को 50 फीसद वेतन दिया जाए। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाए। कटौती करना संवैधानिक व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने आइएएस अफसरों के वेतन में कटौती की भी चेतावनी दी। कहा कि कर्मचारियों की हालत बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई है।

जागरण विशेष

# अब घर पर भी सुन सकेंगे गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन

## एकेटीयू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग की मदद से तैयार किया उपकरण, क्लिनिकल ट्रायल के बाद जल्द बाजार में आने की उम्मीद

पुलक त्रिपाठी • लखनऊ

आने वाले समय में सामान्य स्थिति में गर्भस्थ शिशु का हाल जानने के लिए बार-बार अल्ट्रासाउंड व अन्य जांचों से निजात मिलेगी। शिशु के दिल की धड़कन और उसकी गतिविधियों (हाइपोक्सिया) आदि को छोटे से उपकरण की मदद से घर पर भी जाना जा सकेगा। इस दिशा में चल रहे शोध में डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एकेटीयू के सेंटर आफ एडवांस स्टडीज (सीएएस) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) व मशीन लर्निंग (एमएल) एल्गारिद्म की मदद से यह उपकरण तैयार किया है।

**ग्रामीण इलाकों के लिए होगा वरदान:** ग्रामीण इलाकों में जहां डाक्टरों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, वहां गर्भस्थ की जान का जोखिम बना रहता है। प्रसूता को जांचों व चिकित्सीय प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। नए उपकरण के बाजार में आने से इन क्षेत्रों में गर्भस्थ के स्वास्थ्य की जांच आसान हो जाएगी। सीएएस के विज्ञानियों द्वारा फीटल हार्ट रेट (एफएचआर) के उपयोग पर आधारित उपकरण में डाप्लर व सेंसर की मदद से गर्भस्थ शिशु से सिग्नल के रूप में डाटा कलेक्शन किया जाता है। जिसके बाद उपकरण एआइ व एमएल तकनीक से गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन के बारे में सटीक जानकारी मुहैया कराता है।



सौजन्यः एकेटीयू

**उपकरण की खासियत**

- इस उपकरण के दुरुपयोग की संभावना नहीं होगी, क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग का पता नहीं लगाया जा सकता।
- डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया दस सेकेंड की होगी।
- उपकरण प्रसूता के दिल की धड़कन, कमरे में चल रहे पंखे, एसी व अन्य आवाज को प्रक्रिया के दौरान फिल्टर कर हटा देता है और सिर्फ बच्चे से लिए गए सिग्नल पर ही काम करता है।
- क्लीनिकल ट्रायल के बाद इस उपकरण की बाजार में कीमत अधिकतम पांच हजार से दस हजार रुपये होने की उम्मीद है।

**अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित हुआ शोध:** सीएएस के निदेशक डा. एमके दत्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय जनरल एलसीवियर में यह शोध प्रकाशित हुआ। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण चेक गणराज्य के एक अस्पताल की 500 से अधिक प्रसूताओं पर शोध के तहत उपकरण का उपयोग किया गया, जिसमें बेहद सार्थक परिणाम सामने आए हैं। चूंकि इसकी कीमत काफी कम होगी, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे सरकारी प्रयासों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) तक पहुंचाने का प्रयास होगा। निजी केंद्र पर गर्भवती का अल्ट्रासाउंड कराने में करीब एक हजार रुपये का खर्च आता है। यह उपकरण कम कीमत में ही गर्भस्थ के स्वास्थ्य का हाल बता देगा।



"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग ने हमारी राह आसान की है। इसी एल्गारिद्म पर यह उपकरण तैयार किया गया है। ट्रायल के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत काफी कम होगी। यह भारत जैसे देश के लिए उपयोगी तकनीक व उपकरण हो सकता है।
**प्रो. एम के दत्ता,** निदेशक, सेंटर फार एडवांस स्टडीज, एकेटीयू

एआइ व एमएल तकनीक के जरिए सीएएस इस दिशा में काफी गहन अध्ययन कर रहा है। सामने आया यह परिणाम न सिर्फ बड़ी उपलब्धि है बल्कि स्वस्थ भारत की शुरुआत का संकेत भी है।
**प्रो विनय कुमार पाठक,** कुलपति, एकेटीयू



यदि कोई डिवाइस गर्भ में बच्चे के बारे में जानकारी दे सकती है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के बाद काफी मदद मिलेगी।
**डा. उमा सिंह,** डीन व एचओडी, क्वीन मेरी, केजीएमयू



इंट्रा यूट्राइन डेथ (आइयूडी) यानी गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु के मामले अक्सर आते हैं। ऐसे मामलों में प्रसूता को इस बात का भ्रम रहता है कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह उपकरण काफी कारगर साबित हो सकता है। प्रसूताओं के लिए यह काफी उपयोगी कहा जा सकता है।"
**डा. मालविका मिश्रा,** एसोसिएट प्रोफेसर, डा. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

**15** महीनों के दौरान 157 अरब डालर (करीब 11 लाख 70 हजार करोड़ रुपये) मुहैया कराए हैं विश्व बैंक ने स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए। किसी संकट से निपटने में इस वैश्विक बैंक की यह अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय मदद है।

# काबुल में राष्ट्रपति पैलेस पर आतंकियों ने दागे राकेट

## अफगानिस्तान में संघर्ष ▶ ईद की नमाज पर गनी के यहां इकट्ठा थे अफगान नेता और अधिकारी

### रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर तैनात किए टैंक, युद्धाभ्यास भी करेगा



अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच राजधानी काबुल में राष्ट्रपति भवन के समीप राकेट हमले में क्षतिग्रस्त कार का निरीक्षण करते सुरक्षा बल के अधिकारी व जवान। एपी

**काबुल, रायटर:** हिंसाग्रस्त देश अफगानिस्तान में ईद पर आतंकियों ने अशरफ गनी के राष्ट्रपति पैलेस को निशाना बनाकर लगातार तीन राकेट दागे। ये राकेट उस समय दागे गए, जब राष्ट्रपति व तमाम बड़े नेता और अधिकारी पैलेस में ईद की नमाज पढ़ रहे थे। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने नहीं ली है। अफगान गृह मंत्री के प्रवक्ता मीरवाइज स्टेनेकजई ने बताया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। राकेट एक किले के मैदान में आकर गिरे। इसमें एक कार नष्ट हो गई है।

काबुल में राष्ट्रपति पैलेस किलेबंद सुरक्षा में है। यहां ग्रीन जोन के चारों तरफ मजबूत सीमेंट की दीवार बनी हुई है। हमले के दौरान राष्ट्रपति पैलेस में पढ़ी जा रही नमाज का वीडियो वायरल हो रहा है। राकेट धमाके के बाद हालांकि अशरफ गनी सहित सभी लोग नमाज पढ़ते रहे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की सक्रियता दिखाई दे रही थी।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रायटर को वायस मैसेज में कहा कि ईद पर तालिबान सुरक्षा की मुद्रा में हैं। हालांकि पिछले सालों की तरह तालिबान ने इस बार युद्धविराम की कोई घोषणा नहीं की है। एएनआइ के अनुसार राकेट परवान ए से क्षेत्र से दागे गए थे, जो राष्ट्रपति पैलेस के पास बाग-ए-अली मर्दन, चमन-ए-होजोरी और बशारी क्षेत्र में गिरे।

**गनी ने कहा, तालिबान का शांति का कोई इरादा नहीं :** एपी के अनुसार राष्ट्रपति पैलेस के निकट राकेट हमले के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान का शांति का न तो कोई इरादा दिखाई देता है और न ही कोई इच्छा। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत पांच हजार तालिबानी आतंकियों को छोड़ना सरकार की बड़ी गलती थी। हमले के दौरान मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी राष्ट्रपति पैलेस में मौजूद थे, जो सोमवार को ही दोहा वार्ता में शामिल होकर वापस लौटे थे।

#### मानवाधिकारों का सम्मान न करने वाली सरकार वैध नहीं हो सकती

प्रेट्र के अनुसार, अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी है कि कोई भी सरकार बिना मानवाधिकारों का सम्मान किए वैध नहीं हो सकती है। अमेरिका ने कहा है कि बंदूक के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

#### तुर्की के राष्ट्रपति बोले, तालिबान से होगी वार्ता

एपी के अनुसार, अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तुर्की हर हाल में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा लेना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा है कि वह इस संबंध में तालिबान से भी वार्ता करेंगे। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के मामले में अमेरिका से भी मदद और सहयोग की अपील की है।

#### अमेरिका फिर अफगानिस्तान में नहीं घुस पाएगा

एएनआइ के अनुसार, अमेरिका के संसद सदस्य एडम किसिंगर ने कहा है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए यहां दोबारा जाना असंभव हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व जनरल डेविड पेट्रेउस ने कहा है कि जल्दबाजी में सेना वापसी के निर्णय पर अमेरिका को पछताना पड़ेगा।

#### अफगान राजनयिक की पुत्री का नहीं हुआ अपहरण : पाक

प्रेट्र के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा कि पुलिस जांच में अफगान राजनयिक की पुत्री का अपहरण होना नहीं पाया गया है। अफगानिस्तान जांच में शामिल होकर इसकी पुष्टि कर सकता है। साथ ही पाक ने अशरफ गनी के द्वारा राजदूत को वापस बुलाने की भी निंदा की है।

इधर तालिबान आतंकियों के तेजी से विस्तार करने के बाद अफगान सीमा से लगी ताजिकिस्तान सीमा पर रूस ने टी-72 टैंक तैनात कर दिए हैं। रूसी अधिकारियों ने कहा, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ हमारी सेना 30 जुलाई से 10 अगस्त के बीच नियमित युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही है।

# भारत को जल्द सौंपा जा सकता है तहव्वुर राणा

- बाइडन प्रशासन ने कोर्ट से शीघ्र प्रत्यर्पण आदेश देने का किया आग्रह
- 26/11 मुंबई हमले में वांछित राणा अमेरिका की जेल में है बंद



तहव्वुर राणा फाइल/ इंटरनेट मीडिया

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** मुंबई हमले में वांछित कुख्यात आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द भारत के हवाले किया जा सकता है। अमेरिका की बाइडन सरकार ने उसके जल्द भारत प्रत्यर्पण का आदेश जारी करने का लास एंजिलिस की अदालत से आग्रह किया है। इसी कोर्ट में राणा के प्रर्त्यपण का मामला चल रहा है।

59 वर्षीय तहव्वुर राणा को मुंबई के 26/11 हमले के बाद से ही भारत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। इस हमले को लेकर उस पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राणा को भारत के अनुरोध पर ही जून 2020 में लास एंजलिस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था।

अदालत में राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हुए बाइडन प्रशासन ने कहा है कि भारत ने प्रत्यर्पण के संबंध में दिए गए अनुरोध में राणा के ऊपर जो भी आपराधिक आरोप लगाए हैं, उनके संबंध में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। भारत के प्रस्ताव में सभी जरूरी दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। अमेरिकी अटार्नी ने भारत के मसौदे को पूरी तरह से प्रत्यर्पण के अनुरूप पाया है।

भारत ने अदालत में बताया कि मुंबई हमले को अंजाम देने का काम राणा के बचपन के दोस्त और लश्कर-ए- तैयबा के सदस्य डेविड कोलमेन हेडली ने किया है। उसने पाक में आतंकवादियों की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। इस काम में उसकी पूरी मदद राणा ने की। उसने हेडली को जाली दस्तावेज के जरिये बिजनेस वीजा आदि की सुविधा देकर भारत पहुंचाया। भारत ने इसके भी अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। साथ ही अन्य आतंकी घटना में हेडली कोलमेन के संबंध में भी मजबूत तथ्य पेश किए गए हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में 166 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

# चीन को भी हर पाकिस्तानी नजर आने लगा आतंकवादी

- बम विस्फोट में नौ चीनी इंजीनियरों की मौत से बीजिंग दहशत में
- सीपीइसी योजना के कार्यस्थल से निकाले ढाई हजार पाक कामगार

**इस्लामाबाद, आइएएनएस :** पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम विस्फोट में नौ चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोगों की मौत के बाद बीजिंग की नींद उड़ गई है। मारे गए इंजीनियर दासू बांध परियोजना में काम कर रहे थे। इस घटना के बाद परियोजना पर काम कर रही कंपनी ने सभी पाकिस्तानी कामगारों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें कार्यस्थल से बाहर निकाल दिया है।

पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीइसी) के तहत कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें हजारों चीनी नागरिक विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। पिछले बुधवार को परियोजना स्थल के पास एक बस में हुए बम विस्फोट में नौ चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। घटना को पाक ने दबाने की कोशिश में महज हादसा बताया। चीन ने आंख दिखाई तो गृह मंत्रालय ने बम विस्फोट को आतंकी घटना बताकर जांच शुरू की।

इस मामले के बाद चीनी परियोजनाओं को गहरा धक्का लगा है। यहां काम करने वाले चीनी नागरिक पाक छोड़ना चाहते हैं। चीन का एक पंद्रह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जांच के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है।

विस्फोट की घटना के बाद चीनी कंपनी (गेझुबा ग्रुप) ने परियोजना पर काम करने वाले ढाई हजार पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर हालात और खराब हो गए हैं। चीनी कंपनी की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। चीनी नागरिकों को अब फिर हमले का डर सता रहा है।

इस संबंध में चीन के स्टेट काउंसलर व नागरिक सुरक्षा मंत्री झाओ केझी ने पाक के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद से वार्ता की। प्रधानमंत्री इमरान खान को भी हर रोज बीजिंग को हमले की जांच की प्रगति रिपोर्ट देनी पड़ रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, पाकिस्तान सरकार की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पकड़ बेहद कमजोर है। यहां तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान पूरी तरह से सक्रिय है।

# अमेरिका बोला, आतंकियों को पकड़ कर सजा दे पाकिस्तान

- कहा, एफएटीएफ की कार्य योजना को पूरा करे इस्लामाबाद

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक नसीहत दी है। उसका कहना है कि एफएटीएफ की काली सूची में जाने से बचना है तो पाकिस्तान खूंखार आतंकियों को पकड़ कर सजा देना सुनिश्चित करे। दिखावटी कार्रवाई की जगह आतंकी फंडिंग पर निर्णायक कदम उठाए। पाकिस्तान जून, 2018 से आतंकी फंडिंग को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची में है।

आतंकवाद के खिलाफ एफएटीएफ की 27 सूत्रीय कार्य योजना के तहत जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ पाक को निर्णायक कदम उठाने हैं। साथ ही जैश सरगना मसूद अजहर और लश्कर सरगना हाफिज सईद की जांच करने और मुकदमे चलाने को भी कहा गया है। इस संबंध में अमेरिका का कहना है कि आतंकी सरगनाओं के खिलाफ किसी भी किस्म की लापरवाही पाक को गहरे संकट में डाल सकता है और इस चक्कर में वह ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। उसे इस कार्य योजना को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को कहा, 'एफएटीएफ के एजेंडे को लागू करने में फिलहाल पाकिस्तान का काम संतोषजनक है, लेकिन उसे अभी बहुत करना बाकी है।'

ज्ञात हो, वैश्विक स्तर पर आतंकी फंडिंग रोकने व इसकी निगरानी के लिए स्थापित एफएटीएफ की गत माह बैठक हुई थी। इसमें मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने में नाकाम पाए जाने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का निर्णय लिया गया था।

# मिशिगन की वैदेही बनीं मिस इंडिया यूएसए



मिशिगन की वैदेही डोंगरे। ट्विटर

**वाशिंगटन, प्रेट्र:** अमेरिका में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब मिशिगिन की रहने वाली 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने जीता है। जार्जिया की अर्शी लालानी फर्स्ट रनर अप रहीं। अर्शी ने ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से जूझने के बाद यह खिताब पाया है।

यूनिवर्सिटी आफ मिशिगन से इंटरनेशल स्टडी में स्नातक करने वाली वैदेही फिलहाल एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। कथक नृत्य में पारंगत वैदेही को मिस टेलेंटेड का पुरस्कार भी मिल चुका है। वैदेही ने खिताब जीतने के बाद कहा कि वे महिलाओं की साक्षरता और वित्तीय स्वतंत्रता पर काम करना चाहती हैं। फर्स्ट रनर अप 20 वर्षीय अर्शी लालानी ने अपने आत्मविश्वास से सभी का मन जीत लिया। वह फिलहाल ब्रेन ट्यूमर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने बीमार होने के बाद भी जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे सभी लोग हतप्रभ रह गए। इस कार्यक्रम में भारत की मिस वर्ल्ड-1997 डायना हेडन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

# ताइवान को लेकर चीन ने जापान को दी परमाणु हमले की धमकी

- ताइवानी दूतावास खोलने की इजाजत देने पर लिथुआनिया को भी चेताया
- चीन द्वीपीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है



**बीजिंग, एएनआइ :** चीन अपनी दादागीरी वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने ताइवान मामले को लेकर जापान को परमाणु हमले की धमकी दी है। बीजिंग ने लिथुआनिया को अपने यहां ताइवानी दूतावास खोलने की इजाजत देने पर चेतावनी दी है। चीन द्वीपीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है। वह इस क्षेत्र पर बल पूर्वक कब्जा करने की धमकी भी दे चुका है। वह ताइवान के साथ किसी देश के राजनयिक संबंध स्थापित करने का भी विरोध करता है।

फाक्स न्यूज के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का एक वीडियो सामने आया है। सीसीपी द्वारा स्वीकृत एक चैनल पर दिखाए गए इस वीडियो में कहा गया कि गैर परमाणु शक्तियों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की चीन की नीति है। जापान इसका अपवाद बन सकता है। इसमें यह चेतावनी दी गई है कि ताइवान मामले में जापान ने दखल दिया तो परमाणु हमला कर दिया जाएगा। हालांकि इस वीडियो को बाद में चीनी वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म शिगुआ से हटा दिया गया। इसे 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया। यह वीडियो हटाए जाने से पहले ही यूट्यूब और ट्विटर पर भी अपलोड कर दिया गया।

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, चीन ने लिथुआनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वह गलत संदेश नहीं दे। इससे पहले ताइवान ने कहा कि वह बाल्टिक क्षेत्र के इस देश में अपना दूतावास खोलेगा।

#### ब्रिटेन एशियाई जल क्षेत्र में तैनात करेगा युद्धपोत



बेन वालेस।

**टोक्यो, रायटर :** ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा कि वह अपने दो युद्धपोत एशियाई जल क्षेत्र में स्थायी तौर पर तैनात करेगा। यह तैनाती सितंबर में उस विवादित जल क्षेत्र से विमानवाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ के गुजरने के बाद की जाएगी, जिस पर चीन अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। यह पोत दक्षिण चीन सागर से होते हुए जापान जाएगा। चीन इस जल क्षेत्र पर अपना दावा करता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस ने अपने जापानी समकक्ष के साथ एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी।

# अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा प्रतिबंधों में दी राहत

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** अमेरिका ने भारत के साथ यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। यह निर्णय कोरोना के मरीजों में आई कमी को लेकर किया गया है। इसमें अमेरिकी नागरिक अब यात्रा पर विचार कर सकते हैं। अमेरिका ने यात्रा के खतरों का स्तर चार के स्थान पर तीन कर दिया है।

देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण अमेरिका ने यात्रा प्रतिबंध कड़े किए थे। उसने प्रतिबंधों को उच्च स्तर चार पर रखा था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जब तीन लाख से भी ज्यादा मरीज हर रोज आ रहे थे, उस समय ये प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी तरह से पाकिस्तान यात्रा में भी राहत दी गई है और उसे भी स्तर चार से तीन पर कर दिया गया है।

यात्रा के संबंध में राहत दिए जाने की गाइडलाइन सोमवार को दोनों देशों की कोरोना की स्थिति देखने के बाद जारी की गई है। यह गाइडलाइन सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर (सीडीसी) ने जारी की।

सीडीसी ने कहा है कि यदि आप अधिकृत वैक्सीन की दोनों खुराक लेकर यात्रा करते हैं, तो कोरोना संक्रमण के खतरे कम हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रा से पहले नागरिकों को सीडीसी द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान से देख लेना चाहिए।

## हाई स्पीड ट्रेन...

चीन ने शानडोंग प्रांत के क्वींगडाओ में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है। उसका दावा है कि यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। यह बीजिंग से शंघाई के बीच एक हजार किलोमीटर की दूरी महज 2.5 घंटे में तय करेगी।

**600** किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की रफ्तार

**कौन सी तकनीक**

- विद्युत चुंबकीय बल (इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स)।
- यह ट्रैक के ऊपर तैरती हुई नजर आती है।
- इसे फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जा रहा है।

**हवाई जहाज से तुलना**

हवाई जहाज की तीन घंटे की दूरी को यह लगभग साढ़े पांच घंटे में तय करेगी।



फोटो : रायटर

**विश्व में दौड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेनें**

- स्पेन : एवीई, हाई स्पीड : 574 किमी प्रति घंटा
- चीन : सीआर 400 बीएफ, टाप स्पीड : 420 किमी प्रतिघंटा
- जापान : शिंकानसेन, हाई स्पीड : 400 किलोमीटर प्रति घंटा
- फ्रांस : टीजीवी-पीओएस, हाई स्पीड :403 किमी प्रति घंटा
- जर्मनी : आइसीई, हाई स्पीड : 368 किलोमीटर प्रति घंटा

# आधा आस्ट्रेलिया लाकडाउन में, फ्रांस में कोरोना की चौथी लहर

- ईरान में एक सप्ताह के लिए बंद, पाक में मामले बढ़े
- ब्रिटेन और रूस में संक्रमण में नहीं आ रही कमी



लंदन में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू प्रतिबंधों में हटा लिए जाने के बाद 'फ्रीडम डे' पर टीवी का बाक्स लगाकर जाता एक व्यक्ति। रायटर

**सिडनी, रायटर :** कोरोना संक्रमण के चलते आधी आस्ट्रेलियाई आबादी लाकडाउन के दायरे में आ गई है। यहां कड़ी पाबंदी लगा दी गई हैं। इधर फ्रांस में चौथी लहर शुरू हो गई है।

आस्ट्रेलिया में सिडनी और विक्टोरिया में ही लाकडाउन लगा हुआ था। अब इसका दायरा बढ़ गया है। न्यू साउथ वेल्स सहित कई क्षेत्रों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आधे आस्ट्रेलिया में लाकडाउन लगा दिया है। इस निर्णय से लगभग ढाई करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में डेल्टा वैरिएंट कहर बरपा रहा है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर शुरू हो गई है। सरकार के प्रवक्ता गेबरील अट्टल ने बताया कि पिछली लहरों की तुलना में इस बार संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दस हजार से ज्यादा केस रोजाना मिल रहे हैं। इनमें से 80 फीसद मामले डेल्टा वैरिएंट के हैं। ईरान में भी कोरोना संक्रमण की गति तेज है। यहां एक सप्ताह के लिए लाकडाउन लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 27 हजार से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। रूस में भी हर रोज 24 हजार से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। तेजी से वैक्सीन लगाने के बाद भी मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। पाकिस्तान में संक्रमण तेज हो गया है। कराची के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं।

**चीन :** म्यांमार सीमा से लगे युन्नान प्रांत में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। म्यांमार में संक्रमण से स्थिति खराब होने का यहां असर है।

**म्यांमार :** जेल में बंद आंग सान सू की के वरिष्ठ सलाहकार यान विन की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है।

**दक्षिण कोरिया :** एक युद्धपोत पर ढाई सौ सैनिकों के संक्रमित होने पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने माफी मांगी है। इन सैनिकों को टीके नहीं लगे थे।

## फ्रांस में टीकाकरण नीति का विरोध बढ़ा

न्यूयार्क टाइम्स से

**पेरिस :** फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की टीकाकरण नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है। नई टीकाकरण नीति के विरोध में एक लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस टीकाकरण नीति के तहत जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें रेस्तरां, कैफे, सिनेमा हाल और लंबी दूरी की ट्रेनों में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।

राष्ट्रपति ने एलान किया था कि ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों और स्थानों पर जाने के लिए हेल्थ पास की जरूरत होगी। यह हेल्थ पास टीकाकरण, हालिया कोरोना निगेटिव टेस्ट या हाल में ही कोरोना से उबरने का आधिकारिक दस्तावेज होगा।

इस नीति को मैक्रों की तानाशाही बताते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने पेरिस और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया। हालांकि, इसके साथ ही इस नीति का असर भी दिखने लगा है। नई नीति के अगले माह अस्तित्व में आने से पहले रिकार्ड संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों का रुख कर रहे हैं। इससे देश में स्पष्ट विभाजन दिख रहा है। एक तरफ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी कतारें देखी जा रही हैं।

**आपदा**

# यूरोप में बाढ़ के बाद अब भी सैकड़ों लोग लापता

जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के कई प्रांत चपेट में, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 196

न्यूयार्क टाइम्स से



पिछले कई दशकों की सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहे जर्मनी में सबकुछ अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें, घर और प्रमुख मार्ग मलबे के ढेर से अटे पड़े हैं। चारों तरफ बर्बादी का भयानक मंजर है। यह तस्वीर जर्मनी के राइनलैंड-पैलेटिनेट प्रांत के न्यूएनहर-अहरवीलर शहर की है, जहां घरों के सामान बाढ़ की चपेट में आए वाहन दिखाई दे रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने पड़ोसी देशों बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग में भी बुरा हाल किया है। रायटर

**बर्लिन :** विनाशकारी बाढ़ से जूझने वाले यूरोप में अब भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। गत हफ्ते भारी बारिश के चलते जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के कई प्रांत बाढ़ की चपेट में आ गए थे। बाढ़ में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 196 हो गई है।

जर्मनी की पुलिस ने बताया कि भीषण बाढ़ के चलते सैकड़ों घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। कई कारें बह गईं। इससे 700 से ज्यादा लोगों के लापता होने का अंदेशा जताया गया था। कई दिनों की अनिश्चितता के बाद ज्यादातर को सुरक्षित बताया गया है। लेकिन बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाकों में अब भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ से पश्चिमी जर्मनी के राइनलैंड-पैलेटिनेट और नार्थ राइन-वेस्टफैलिया प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। इन प्रांतों में मरने वालों की संख्या 164 हो गई है। इनमें से 117 लोगों की मौत राइनलैंड-पैलेटिनेट राज्य के एहरवीलर काउंटी में हुई। इस काउंटी में 749 लोग घायल हुए। इधर, बेल्जियम में अब तक 31 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। यहां अभी भी 127 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड और स्विटजरलैंड में भी बाढ़ से जानमाल को नुकसान पहुंचने की खबर है।

# अमेरिका बोला, हमारी मदद से मजबूत हो रही भारतीय नौसेना

**वाशिंगटन, प्रेट्र:** अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि भारतीय नौसेना हमारी मदद से मजबूत हो रही है। इसके लिए उन्हें पी 8 जैसे निगरानी विमान दिए गए हैं। इस तरह के विमान दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं हैं। साथ ही अमेरिका से शक्तिशाली एमएच-60 आर सी हाक हेलीकाप्टर मिलने से भी भारत की नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी।

अमेरिकी कंपनी लाकहीड मार्टिन के एमएच-60 आर हेलीकाप्टर युद्ध संबंधी कई भूमिकाओं को निभाने में पूरी तरह सक्षम और बेहद शक्तिशाली हैं। यह मल्टीरोल आल वेदर हेलीकाप्टर हैं। ऐसे 26 हेलीकाप्टर भारत को मिलेंगे। इनमें से दो हेलीकाप्टर भारत को दिए जा चुके हैं। पिछले सप्ताह सैन डियागो में नौसेना के एयर स्टेशन पर औपचारिक रूप से हेलीकाप्टर हस्तांतरित करने का एक समारोह आयोजित किया गया था।




# चाहर ने दिलाई भारत को रोमांचक जीत

## भारत तीन विकेट से जीता, दीपक ने दो विकेट लेने के बाद जड़ा अर्धशतक


शाट खेलते दीपक चाहर ● एएफपी

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली :** भारतीय टीम ने मंगलवार को कोलंबो में 273 रन के लक्ष्य के सामने जब 27 ओवर में 160 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे तो लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम सीरीज में बराबरी हासिल कर लेगी। ऐसे में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे दीपक चाहर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और करियर का पहला अर्धशतक जड़ते हुए भारत को अंतिम ओवर में तीन विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। चाहर ने 82 गेंदों पर सात चौकों व एक छक्के के साथ रन नाबाद 69 रन बनाए। उन्होंने इससे पहले 53 रन देकर दो विकेट भी लिए। भुवनेश्वर 28 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। इससे पहले श्रीलंका ने चरित असलंका और सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने अर्धशतक की मदद से 50 ओवर में नौ विकेट पर 275 रन बनाए थे। असलंका ने 68 गेंद में छह चौकों की मदद से 65 रन बनाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, जबकि फर्नांडो ने 71 गेंद में चार चौकों व एक छक्के की मदद से 50 रन बनाए।

**69** नाबाद रन की पारी खेली दीपक चाहर ने, जो किसी भारतीय बल्लेबाज का आठवें या उससे नीचे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। शीर्ष पर 77 रन के साथ रवींद्र जडेजा हैं

> टीम की शानदार जीत। खराब हालात के बावजूद टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच देखना सुखद रहा। दीपक चहर और सूर्यकुमार यादव ने दबाव के बीच शानदार पारी खेली। -विराट कोहली

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पिछले मैच के तीन बड़े हीरो पृथ्वी शा (13), इशान किशन (1) व कप्तान शिखर धवन (29) के विकेट सिर्फ 65 रन तक गंवा दिए। यहां से मनीष पांडे (37) और सूर्यकुमार यादव (53) ने चौथे विकेट के लिए 32 गेंदों पर 50 रन जोड़कर भारत को मैच में लौटाया। पांडे के 18वें ओवर में रन आउट होने से यह साझेदारी टूटी तो इसी ओवर में दासुन शनाका ने हार्दिक पांड्या (0) को भी चलता मैच को फिर श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया। अब सूर्यकुमार को हार्दिक के भाई क्रुणाल पांड्या (35) का साथ मिला, लेकिन 27वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद सूर्यकुमार चलते बने। उन्हें लक्षण संदाकन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया।

यहां से दीपक चाहर बल्लेबाजी करने उतरे। इस मैच से पहले उनके पास अनुभव के नाम पर चार वनडे व 13 टी-20 मैचों में मिलाकर कुल 17 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सिर्फ 19 रन का अनुभव था और भारत को जीत के लिए 23 ओवर में 116 रन बनाने थे, जबकि उसके हाथ में सिर्फ चार विकेट बाकी थे। चाहर और क्रुणाल ने धीमी साझेदारी करते हुए 49 गेंदों पर 33 रन जोड़े। इस साझेदारी को वानिंदु हसरंगा ने क्रुणाल को बोल्ड कर तोड़ा। यहां से चाहर को भुवनेश्वर कुमार का साथ मिला। दोनों ने शुरुआत में धीमी गति से साझेदारी को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में चाहर ने तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए भारत को जीत दिला दी। इस दौरान उन्होंने 64 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उन्होंने भुवनेश्वर के साथ आठवें विकेट के लिए 84 गेंदों पर 84 रन जोड़े। इससे पहले श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अविष्का फर्नांडो और मिनोद भानुका (36) ने पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। मिनोद के आउट होने के बाद चरित असलंका और फर्नांडो ने अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। निचले क्रम में चमिका करुणारत्ने (नाबाद 44, 33 गेंद, 5 चौके) ने तेजतर्रार पारी खेली, जिससे टीम अंतिम 10 ओवर में 79 रन जोड़ने में सफल रही। भारत की ओर से लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल व भुवनेश्वर ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

### स्कोर बोर्ड

टास : श्रीलंका (बल्लेबाजी) — मैन आफ द मैच : दीपक चाहर

**श्रीलंका — 275/9 (50 ओवर)**

| | रन | गेंद | चौके | छक्के |
|---|---|---|---|---|
| अविष्का का. क्रुणाल बो. भुवनेश्वर | 50 | 71 | 04 | 01 |
| मिनोद भानुका का. पांडे बो. चहल | 36 | 42 | 06 | 00 |
| भानुका राजपक्षे का. इशान बो. चहल | 00 | 01 | 00 | 00 |
| धनंजय डिसिल्वा का. धवन बो. चाहर | 32 | 45 | 01 | 00 |
| चरित का. सब बो. भुवनेश्वर | 65 | 68 | 06 | 00 |
| दासुन शनाका बो. चहल | 16 | 24 | 01 | 00 |
| वानिंदु हसरंगा बो. चाहर | 08 | 11 | 01 | 00 |
| चमिका करुणारत्ने नाबाद | 44 | 33 | 05 | 00 |
| दुष्मंता चमीरा का. सब बो. भुवनेश्वर | 02 | 05 | 00 | 00 |
| लक्षण संदाकन रन आउट | 00 | 01 | 00 | 00 |
| कासुन रजिता नाबाद | 01 | 01 | 00 | 00 |

**अतिरिक्त :** (लेबा-6, नोबा-2, वा-13) 21, **कुल :** 50 ओवर में नौ विकेट पर 275 रन, **विकेट पतन :** 1-77 (मिनोद, 13.2), 2-77 (भानुका, 13.3), 3-124 (अविष्का, 24.6), 4-134 (डिसिल्वा, 27.2), 5-172 (दासुन, 35.2), 6-194 (हसरंगा, 39.1), 7-244 (चरित, 47.1), 8-264 (चमीरा, 49.1), 9-266 (संदाकन, 49.3)

**गेंदबाजी :** भुवनेश्वर 10-0-54-3 : चाहर 8-0-53-2, हार्दिक 4-0-20-0, युजवेंद्रा 10-1-50-3, कुलदीप 10-0-55-0, पांड्या 8-0-37-0

**भारत — 277/7 (49.1 ओवर)**

| | रन | गेंद | चौके | छक्के |
|---|---|---|---|---|
| पृथ्वी शा बो. डिसिल्वा | 13 | 11 | 03 | 00 |
| धवन एलबीडब्ल्यू बो. डिसिल्वा | 29 | 38 | 06 | 00 |
| इशान किशन बो. रजिता | 01 | 04 | 00 | 00 |
| मनीष पांडे रन आउट | 37 | 31 | 03 | 00 |
| सूर्यकुमार एलबीडब्ल्यू बो. संदाकन | 53 | 44 | 06 | 00 |
| हार्दिक का. डिसिल्वा बो. शनाका | 00 | 03 | 00 | 00 |
| क्रुणाल पांड्या बो. डिसिल्वा | 35 | 54 | 03 | 00 |
| दीपक चाहर नाबाद | 69 | 82 | 07 | 01 |
| भुवनेश्वर कुमार नाबाद | 19 | 28 | 02 | 00 |

**अतिरिक्त :** 21 (बा-1, लेबा-4, वा-16), **कुल :** 49.1 ओवर में सात विकेट पर 277 रन, **विकेट पतन :** 1-28 (शा, 2.6), 2-39 (किशन, 4.6), 3-65 (धवन, 11.6), 4-115 (पांडे, 17.2), 5-116 (हार्दिक, 17.6), 6-160 (सूर्यकुमार, 26.6), 7-193 (क्रुणाल, 35.1)

**गेंदबाजी :** कासुन रजिता 7.1-0-53-1, चमीरा 10-0-65-0, हसरंगा 10-0-37-3, लक्षण संदाकन 10-0-71-1, चमिका करुणारत्ने 6-1-26-0, दासुन शनाका 3-0-10-1, धनंजय डिसिल्वा 3-0-10-0

## मिताली नौवीं बार वनडे की नंबर एक बल्लेबाज बनीं

**दुबई, प्रेट्र :** भारतीय कप्तान मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की नवीनतम महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 762 अंक के साथ एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गईं जबकि बायें हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी नौवें स्थान के साथ शीर्ष-10 में शामिल हैं।

16 साल से भी अधिक समय पहले पहली बार बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाली मिताली नौवीं बार नंबर एक बल्लेबाज बनी हैं। पिछली रैंकिंग में शीर्ष पर चल रही वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर पांचवें स्थान पर खिसक गई हैं। गेंदबाजों की सूची में झूलन गोस्वामी पांचवें स्थान के साथ शीर्ष-10 में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं जबकि आलराउंडरों की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा 10वें स्थान पर हैं।

महिला टी-20 रैंकिंग में भारतीय सलामी बल्लेबाज मंधाना अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की बराबरी करते हुए तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी-20 में 70 रन की पारी खेली थी जो पिछले हफ्ते इस प्रारूप में उनका एकमात्र मुकाबला था। मंगलवार को हुए साप्ताहिक अपडेट में वेस्टइंडीज की कप्तान टेलर को 30 अंक का नुकसान हुआ।

# बोपन्ना ने रिकार्डिंग की सार्वजनिक, एआइटीए ने उठाया कदम

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) के महासचिव अनिल धूपर के साथ बातचीत को सार्वजनिक करने के रोहन बोपन्ना के मामले को एआइटीए की आचरण और प्रबंध समिति के पास भेजा जाएगा। एआइटीए ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एआइटीए ने साथ ही ओलिंपिक में भारतीय पुरुष डबल्स टीम के क्वालीफिकेशन को लेकर अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) के साथ अपना पूरा संवाद जारी किया। ई-मेल के माध्यम से जानकारी मिली कि दो जुलाई को एआइटीए ने आइटीएफ से स्पष्टीकरण मांगा कि वैश्विक संस्था ने कैसे अमेरिका (संयुक्त रैंकिंग 118), स्पेन (संयुक्त रैंकिंग 170) व पुर्तगाल (संयुक्त रैंकिंग 204) को पुरुष डबल्स में जगह दे दी जबकि उनकी संयुक्त रैंकिंग बोपन्ना और दिविज की 113 की संयुक्त रैंकिंग से कम थी।

एक अन्य ई-मेल में एआइटीए ने आइटीएफ से अपील की कि टोक्यो खेलों में प्रवेश के लिए बोपन्ना व दिविज की 2018 एशियाई खेलों की उपलब्धि पर गौर करे। एआइटीए ने ये ई-मेल बोपन्ना के उस ट्वीट के बाद सार्वजनिक किए हैं जिसमें उन्होंने वीडियो काल रिकार्डिंग पोस्ट की थी। इस वीडियो रिकार्डिंग में धूपर को यह कहते हुए सुना गया था कि आइटीएफ ने पुरुष डबल्स में बोपन्ना और सुमित नागल की प्रविष्टि स्वीकार कर ली। धूपर को कहते हुए सुना गया कि शायद कल हमें अच्छी खबर (क्वालीफिकेशन की) मिल जाए। बोपन्ना ने जब स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या उनकी और नागल की प्रविष्टि को स्वीकार कर लिया गया तो धूपर ने सकारात्मक जवाब दिया। बोपन्ना का कहना है कि आखिर एआइटीए ने उन्हें क्वालीफिकेशन की झूठी उम्मीद क्यों दी। धूपर ने कहा, 'फोन काल को रिकार्ड करने और सार्वजनिक करने के कदम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एआइटीए की प्रबंध समिति और आचरण समिति इस पर गौर करेगी। ये दो समितियां फैसला करेंगी कि बोपन्ना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत है या नहीं।'

**भूपति बोले, पहाड़ों पर चला जाता :** इस मामले पर महेश भूपति ने ट्वीट किया कि अगर यह मैं होता तो मैं पहाड़ों पर रास्ता तराशने के लिए निकल जाता। इसके अलावा, मुझे नहीं लगता कि यह अक्षमता है। उन्हें बस परवाह नहीं है। जिसका जवाब देते हुए बोपन्ना ने ट्वीट किया कि 50 साल से अभी तक यही चल रहा है।


रोहन बोपन्ना ● फाइल फोटो, ट्विटर

### बोपन्ना विवाद पर एआइटीए का स्पष्टीकरण

**नई दिल्ली, एएनआइ :** भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के विवाद पर अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने नाराजगी जाहिर की है। एआइटीए ने कहा, 'कुछ सम्मानित खिलाड़ियों के गैर-जिम्मेदार ट्वीट के कारण बेतुके विवाद पर एआइटीए गहरी निराशा जाहिर करता है। बोपन्ना व शरण की पुरुष डबल्स जोड़ी क्वालीफाई नहीं कर सकी। ऐसे में क्वालीफाई किए बिना, बोपन्ना का सानिया मिर्जा के साथ मिक्स्ड डबल्स में भाग लेने का सवाल ही नहीं उठता। 16 जुलाई को सुमित को सिंगल्स में मौका मिला, तो हमें लगा कि सुमित के साथ बोपन्ना की जोड़ी बनाए जाने की संभावना है, जिस पर आइटीएफ से पूछा कि क्या ऐसा संभव है। दुर्भाग्य से आइटीएफ ने नकार दिया। हमने सभी संयोजनों के साथ खिलाड़ियों की मदद करने की कोशिश की लेकिन वे रैंकिंग आधार पर कटौती करने में विफल रहे। क्या यह सब बोपन्ना जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए समझना इतना मुश्किल है? इस तरह के आरोप लगाना काफी निराशाजनक है।'

# केएल राहुल का शतक, जडेजा भी चमके

## काउंटी एकादश के खिलाफ भारत ने नौ विकेट 306 रन बनाए

**डरहम, आइएएनएस :** केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने मंगलवार को यहां काउंटी एकादश (काउंटी सिलेक्ट इलेवन) के खिलाफ तीन दिवसीय प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच के पहले दिन नौ विकेट पर 306 रन बनाए। राहुल 150 गेंदों पर 11 चौकों व एक छक्के की मदद से 101 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। रवींद्र जडेजा ने भी 146 गेंदों पर पांच चौकों व एक छक्के की मदद से 75 रन बनाए।

कप्तान रोहित शर्मा ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मयंक अग्रवाल (28), चेतेश्वर पुजारा (21) व हनुमा विहारी (24) ने 20 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका। इसके बाद राहुल व जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला।

**कोहली व रहाणे को विश्राम :** इस मैच के लिए नियमित कप्तान विराट कोहली, उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे व आफ स्पिनर आर अश्विन को आराम दिया गया। बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने कहा, 'कोहली को सोमवार देर शाम पीठ में कुछ जकड़न महसूस हुई। उन्हें मेडिकल टीम ने मैच से आराम करने की सलाह दी। रहाणे के बायें पैर की मांसपेशियों के आसपास हल्की सूजन है।'

### विपक्षी टीम से खेले आवेश और सुंदर

चोट व क्वारंटाइन के कारण अपने खिलाड़ियों को गंवाने के बाद भारत के युवा खिलाड़ी आवेश खान व वाशिंगटन सुंदर काउंटी एकादश टीम की ओर से अपने ही देश की टीम के खिलाफ खेलने उतरे। आवेश ने 9.5 ओवर गेंदबाजी भी की जिसके बाद उनके हाथ के अंगूठे में चोट लग गई और उनके मैच में आगे हिस्सा लेने की संभावना नहीं है। बीसीसीआइ की मेडिकल टीम उन पर निगरानी रख रही है। उन्हें यह चोट हनुमा विहारी के शाट को रोकते समय लगी। अभ्यास मैचों में खिलाड़ियों का अपनी ही टीम के खिलाफ उतरना नई बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर जब 14 साल के थे तो उन्होंने 1987 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच के दौरान इमरान खान की अगुआई वाली पाकिस्तान की टीम के लिए क्षेत्ररक्षण किया था। तेंदुलकर उस मैच में बाल ब्वाय थे और अब्दुल कादिर की जगह क्षेत्ररक्षण करने उतरे थे।

# पदक लेकर आएंगे पंघाल, मेरी कोम और कृष्णन : विजेंद्र सिंह

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

बीजिंग ओलिंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का मानना है कि अनुभवी मुक्केबाज एमसी मेरी कोम, अमित पंघाल, विकास कृष्णन टोक्यो ओलिंपिक में जरूर पदक जीतेंगे। रियो ओलिंपिक में भारतीय मुक्केबाज खाली हाथ रहे थे।

35 वर्षीय विजेंद्र ने मंगलवार को दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि पिछले ओलिंपिक में हमने अच्छा नहीं किया था और हम एक भी पदक नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार की टीम बहुत मजबूत है और नौ मुक्केबाजों ने क्वालीफाई किया है। पंघाल, मेरी कोम और विकास के पास पदक जीतने का अच्छा मौका है और उनके पास अनुभव भी है। मुझे उम्मीद है कि वे पदक के साथ लौटेंगे।


विजेंद्र सिंह ● फाइल फोटो, प्रेट्र

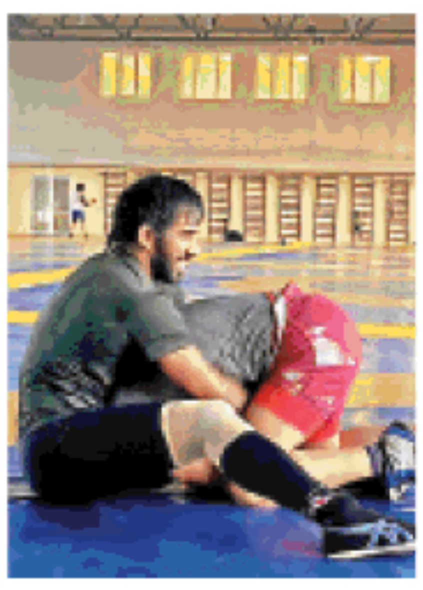
मैं चाहता हूं कि हमारे नौ मुक्केबाज पदक लेकर आएं, लेकिन उन तीनों से ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि 38 वर्षीय मेरी कोम का यह आखिरी ओलिंपिक हो सकता है। मेरी कोम को लेकर विजेंद्र ने कहा कि वह सभी के लिए प्रेरणा हैं। वह बहुत ही मजबूत महिला हैं। उनके तीन बच्चे हैं और वह इतनी जिम्मेदारी के बाद भी ओलिंपिक खेलने गई हैं। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वह पदक के साथ लौटेंगी।

# तेंदुलकर ने एथलीटों को दिया सफलता का मंत्र

**ओलिंपिक डायरी**

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टोक्यो ओलिंपिक जाने वाली भारत की 26 सदस्यीय एथलेटिक्स (ट्रैक एवं फील्ड) टीम को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि दबाव का लुत्फ उठाएं और इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। तेंदुलकर ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) के साथ आयोजित आनलाइन कार्यक्रम में खिलाड़ियों को विदाई दी।

तेंदुलकर ने कहा, 'काफी लोग कहते हैं कि खेल में हार और जीत होती है, लेकिन मेरा संदेश है कि हार विरोधी की हो और आप जीत दर्ज करें। आपको पदक जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए और आपका सपना गले में पदक पहनना, राष्ट्रगान का बजना और तिरंगे का लहराना होना चाहिए।'


अभ्यास करते बजरंग पूनिया ● साई

ट्रैक एवं फील्ड यानी एथलेटिक्स स्पर्धा में कुल 47 सदस्य शामिल हैं जिसमें 26 खिलाड़ियों के अलावा 11 कोच, आठ सहयोगी स्टाफ, एक टीम डाक्टर और एक टीम नेतृत्वकर्ता है। यह दल 23 जुलाई को टोक्यो के लिए रवाना होगा।

**ओलिंपिक के आदर्श वाक्य में जुड़ा नया शब्द :** ओलिंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में अब अधिक तेज (सिटिअस), उच्चतर (अल्टिअस) और अधिक मजबूत (फोर्टिअस) के साथ एकजुट (कोम्युनिस) भी जोड़ दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच 23 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों से पहले अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के सत्र में यह फैसला लिया गया। पहले ओलिंपिक का आदर्श वाक्य तीन लेटिन शब्दों सिटिअस, अल्टिअस और फोर्टिअस से बना था जिसके हिन्दी में मायने हैं अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। अब इसमें कोम्युनिस (एकजुट) भी जोड़ दिया गया है। इस बदलाव का प्रस्ताव आइओसी अध्यक्ष थामस बाक ने रखा था जिसे अप्रैल में कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दी थी। अब नया आदर्श वाक्य है, सिटिअस, अल्टिअस, फोर्टिअस, कोम्युनिस।


अभ्यास करते हुए मनु भाकर ● ट्विटर

**खेल गांव में नहीं रहेंगी एश्ले बार्टी :** एशले बार्टी के जापान आने के बाद आस्ट्रेलियाई दल के प्रमुख इयान चेस्टरमैन ने अधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी ओलिंपिक खेल गांव में नहीं रहेगी। पिछले सप्ताह विंबलडन जीतने वाली बार्टी को ओलिंपिक में लय कायम रखने की उम्मीद है।

# अमन और सागर बने विश्व कैडेट चैंपियन

विजय गाहल्याण ● पानीपत

युवा भारतीय पहलवान अमन गूलिया और सागर जागलान बुडापेस्ट में मंगलवार को अपने-अपने वर्ग में विश्व कैडेट चैंपियन बन गए। इस चैंपियनशिप में अमन ने 48 किग्रा के फाइनल में अमेरिका के ल्यूक जोसेफ लिलेडाहल को 5-2 से हराया जबकि सागर ने 80 किग्रा में जेम्स माकलर राउले को 4-0 से शिकस्त दी।

इससे पहले हुए चार मुकाबलों में सागर ने फितले दांव का इस्तेमाल कर प्रतिद्वंद्वियों को हराया। सागर पानीपत शहर के राजनगर में रहते हैं। वह बचपन में शारीरिक रूप से कमजोर थे। पिता मुकेश कुमार पहलवान रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि बेटे को भी पहलवान बनाऊंगा ताकि कोई कमजोर शरीर पर तंज न कसे। सागर खरखौदा स्थित अश्वनी कुश्ती अकादमी के कोच अश्वनी के पास अभ्यास करते हैं। सागर जागलान ने बताया कि वह स्टार पहलवान बजरंग पूनिया के फितले दांव के मुरीद हैं। पूनिया से कई बार मिल चुके हैं। दांव की बारीकी सीख चुके हैं। वह हर रोज 120 बार फितले दांव का अभ्यास करते हैं। एशियन चैंपियनशिप व विश्व चैंपियनशिप में फितले दांव की वजह से जीत दर्ज कर पाया।


अमन गूलिया ● ट्विटर

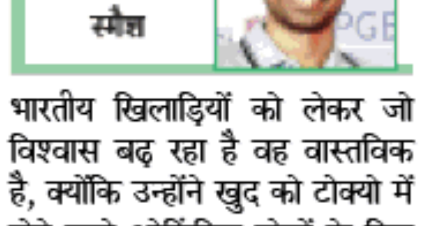

सागर जागलान ● जागरण आकाईव

## कोहनी मोड़ने की 15 डिग्री की सीमा को हटा दे आइसीसी : सकलेन

**कराची, प्रेट्र :** पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलेन मुश्ताक चाहते हैं कि आइसीसी गेंदबाजों के लिए कोहनी मोड़ने की मौजूदा 15 डिग्री की सीमा को हटा दे। सकलेन लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उच्च प्रदर्शन केंद्र में मुख्य कोच हैं। उन्होंने कहा कि यह नियम युवाओं को आफ स्पिन गेंदबाजी कला को अपनाने से हतोत्साहित कर रहा है।

उन्होंने कहा, 'मैं जानना चाहता हूं कि आइसीसी के विशेषज्ञ गेंदबाजों को केवल 15 डिग्री तक कोहनी मोड़ने की अनुमति देने के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। क्या उन्होंने एशियाई खिलाड़ियों, कैरेबियाई खिलाड़ियों या किसी अन्य पर शोध किया क्योंकि हर कोई अलग है। एशियाई खिलाड़ियों का शरीर कैरेबियाई या इंग्लैंड के खिलाड़ियों से थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि आइसीसी को इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि 15 डिग्री की सीमा बहुत कम है। यह आफ स्पिन गेंदबाजी की कला से खिलाड़ियों को हतोत्साहित कर रहा है। जब से यह नियम आया, मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे जो आफ स्पिन गेंदबाजी करते थे, लेकिन अब लेग स्पिनर या कलाई के स्पिनर बन गए।'

# भारतीय खिलाड़ियों ने खुद को बेहतर तरीके से तैयार किया है


पुलेला गोपीचंद

भारतीय खिलाड़ियों को लेकर जो विश्वास बढ़ रहा है वह वास्तविक है, क्योंकि उन्होंने खुद को टोक्यो में होने वाले ओलिंपिक खेलों के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया है। भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में इस समय आत्मविश्वास और उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। महामारी और चुनौतियों के बावजूद यह चीज उनकी तैयारियों को दिखाती है।

यह आत्मविश्वास कहां से आया है, इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। एक साल की देरी से शुरू हो रहे टोक्यो 2020 के लिए चुने गए सभी 125 खिलाड़ियों ने खुद को मानसिक, शारीरिक तरीके से तैयार रखने के लिए हरसंभव कोशिश की है। यह कहना सही होगा कि ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को हर जरूरी समर्थन मिला है। आज प्रत्येक क्वालीफायर को विदेशी कोच, फिजियो और स्ट्रेंथ व कंडिशनिंग कोच से मदद मिल रही है। एक समय था जब किसी एक खिलाड़ी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई हैं। अब जो स्थिति है वो सिर्फ शीर्ष देशों में ही देखने को मिलती है।




रियो में 2016 गेम्स की मुझे याद है, जब भारतीय खिलाड़ी उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं ला पाए थे, बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने टीम का 100 फीसद समर्थन किया था। रियो के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त ओलिंपिक टास्क फोर्स का मैं हिस्सा था। मैं भारतीय खेल में हो रहे बदलावों को साफतौर पर देख पा रहा था। उच्च स्तर से लेकर ग्रासरूट तक रुचि दिखाई जा रही थी, ताकि देश में खेल को लेकर ज्यादा पाजिटिव और पेशेवर माहौल बनाया जा सके।

यह एक शानदार बदलाव है, भारत ने एथलीटों को प्राथमिकता दी और भारतीय खेल प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सभी जरूरतें पूरी हों। समय एकदम से बदल गया और हर किसी का सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखने लगा कि एथलीटों को खेलों के महाकुंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे तैयार किया जाए। राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय ओलिंपिक संघ के साथ मिलकर खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि कोच के अनुबंध आगे बढ़ाए जाएं। देशभर में सेंटर आफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय कैंप सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए आयोजित किए जाएं। मुझे उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि टोक्यो 2020 में हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यह हमारे लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट हो सकता है, क्योंकि हमने हमारे एथलीटों में काफी ज्यादा निवेश किया है।



# 2016

## बेटियों ने बढ़ाया मान

टोक्यो ओलंपिक
02 दिन शेष

ब्राजील के शहर रियो डि जेनेरियो में हुए इन ओलिंपिक में भारत ने सिर्फ दो पदक जीते। इन दोनों पदकों को दो बेटियों ने जीतकर भारत का मान बढ़ाया। ओलिंपिक इतिहास में पीवी सिंधू महिला सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं, तो कुश्ती में साक्षी मलिक ने 58 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।

### वाह बोल्ट

जमैका के फर्राटा धावक उसेन बोल्ट अपना तीसरा ओलिंपिक खेले व लगातार तीसरी बार तीन स्पर्धाओं में स्वर्ण जीतकर अनोखी हैट्रिक पूरी की। उन्होंने लगातार तीसरे ओलिंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर व चार गुना 100 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण जीते। हालांकि, बाद में उनके एक साथी को अयोग्य पाए जाने के बाद 2008 का उनका चार गुना 100 मीटर रिले का स्वर्ण छीन लिया गया था।

पांच से 21 अगस्त

11238 एथलीट | 207 देश | 28 खेल 306 मुकाबले

### तालिका में शीर्ष पांच देश

| देश | स्वर्ण | कुल पदक |
|---|---|---|
| अमेरिका | 46 | 121 |
| ग्रेट ब्रिटेन | 27 | 67 |
| चीन | 26 | 70 |
| रूस | 19 | 56 |
| जर्मनी | 17 | 42 |

### दीपा ने रचा इतिहास



दीपा कर्माकर ने रियो ओलिंपिक में क्वालीफाई करते ही इतिहास रच दिया था। वह ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। उन्होंने अपने प्रदर्शन से भी सबका दिल जीता और जिम्नास्टिक की वाल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर मामूली अंतर से पदक से चूक गई थीं।

### पदक से चूके अभिनव

2008 बीजिंग ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के पास रियो में भी पदक जीतने का मौका था, लेकिन 10 मीटर एयर राइफल में वह चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूक गए थे।

### पेस का कमाल

1996 अटलांटा ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस का यह लगातार सातवां ओलिंपिक था। वह सात ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय हैं। रियो में ही भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी चौथे पायदान पर रहकर पदक से एक कदम दूर रह गई।

दैनिक जागरण
सप्तरंग

# सेहत भरे जीवन का

बुधवार, 21 जुलाई, 2021

## चातुर्मास में क्यों आवश्यक है आहार में अनुशासन

जीवनशैली

डा. उदय नारायण पांडे
उप चिकित्सा अधीक्षक
गुरुकुल राजकीय
आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार

20 जुलाई से लगे चातुर्मास को ऋतुओं का संधिकाल कहा गया है। इस मौसम में उमस और नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं और रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए खानपान व दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इसकी अहमियत बढ़ जाती है ताकि कोई भी बीमारी आपको स्पर्श न कर सके...

आयुर्वेद की मान्यता है कि कोई भी बीमारी शरीर में वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होती है। चातुर्मास में इन तीनों की तीव्रता बढ़ जाती है, फलस्वरूप पाचन क्रिया कमजोर पड़ना, गैस व एसिडिटी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। इनका एक ही समाधान है कि वात, पित्त और कफ में संतुलन बनाएं। इसके लिए आहार और शारीरिक व्यवहार में संयम व अनुशासन जरूरी हो जाता है।



**सुपाच्य भोजन करें :** कम तेल, मिर्च, मसाले वाला हल्का सुपाच्य भोजन पाचन तंत्र ठीक रखने में सहायक है। पित्त पाचन क्रिया में सहायक है और उसकी तीव्रता दिन में अधिक व रात्रि में क्षीण पड़ जाती है। इसलिए विशेषकर इस मौसम में देर रात्रि भोजन करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आहार संध्या समय ही कर लें ताकि पाचन दुरुस्त रहे।

**हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचें :** बारिश के दिनों में मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया पनपते हैं। इस मौसम में साग व हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से दूर रहना लाभकारी है। दरअसल इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों में बेहद सूक्ष्म कृमि की मौजूदगी की वजह से ऐसा करने की सलाह दी जाती है। कई बार सब्जियों को ठीक से न धोए जाने के कारण वे आहार के साथ शरीर में पहुंचकर आपको बीमार बना सकती हैं।

**दूध से बने उत्पादों का सेवन करें :** बारिश के दिनों में दूध के बजाय इससे बने उत्पादों का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में दूध में बैक्टीरिया शीघ्र पनपते हैं, किंतु जब भली प्रकार पकाकर उसका सेवन किया जाता है तो वह शरीर के लिए गुणकारी होता है। रात में दही के सेवन से बचना चाहिए अन्यथा जुकाम हो सकता है।

**पानी उबालकर पिएं :** वर्षाकाल में नदियों व जल के अन्य स्रोतों में धूल कण व मिट्टी घुल जाती है। यह दूषित जल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस मौसम में पानी सदैव उबालकर पीना चाहिए।

प्रस्तुतिः कीर्ति सिंह

### सूर्योदय से पहले उठें

सुबह के समय ताजी हवा फेफड़ों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठने व प्राणायाम करने का नियम बना लें। योग व प्राणायाम करने से हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है और रक्त संचार बेहतर होता है। जब शरीर में भरपूर आक्सीजन पहुंचती है तो विभिन्न अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हम रोग मुक्त बने रहते हैं।

इन दिनों

डा. संजीव कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर तथा कोरोना
नोडल आफिसर, एम्स, पटना

कोरोना को हराना है

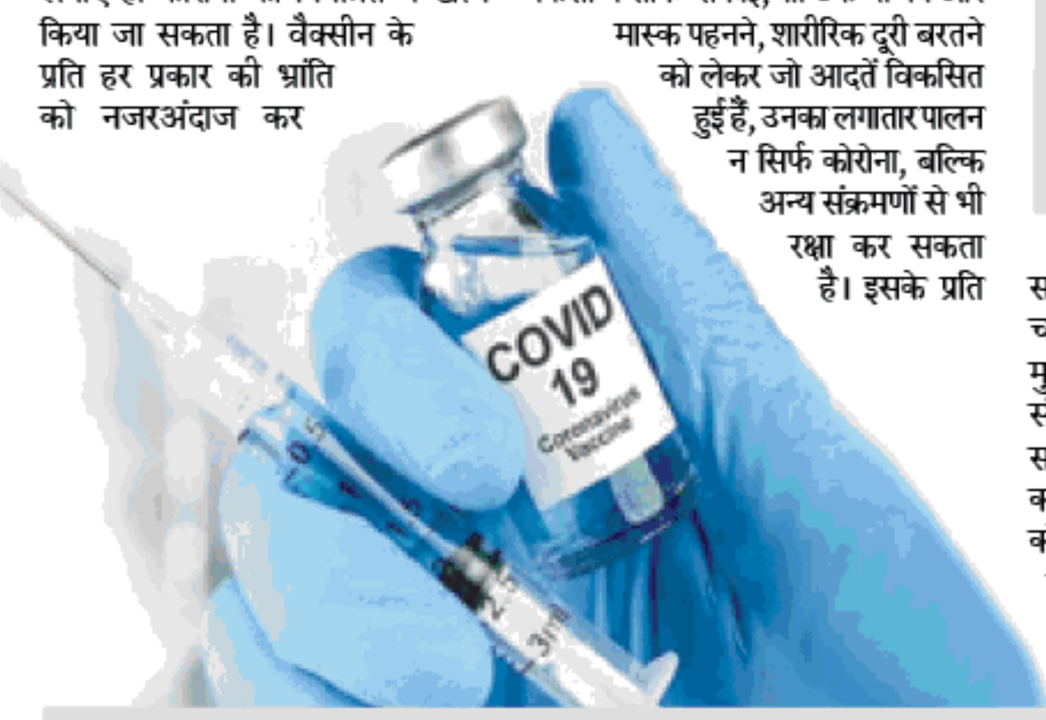


कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद पर्यटन स्थलों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर नजर आ रही लापरवाह भीड़ भावी आफत की तस्वीर खींच रही है। भारतीय चिकित्सक संघ (आइएमए) ने भी चेताया है कि अगर ऐसे हाल रहे तो कोरोना की तीसरी लहर आने की काफी आशंका है। बेहतर होगा कि जिस स्थिति से बीते दौर में हम गुजरे वह वक्त हमारी अपनी लापरवाही से दोहराया न जाए...

# भीड़ न पड़ जाए भारी

सभी जानते हैं कि कोरोना या अन्य वायरस को जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नई-नई जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। यदि उसे नई जीवित कोशिकाएं ही न मिलें तो यह स्वतः खत्म हो सकता है। वायरस की दो कमजोरियों का लाभ उठाकर ही इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। पहली, यह सिर्फ मनुष्य में ही खुद को जीवित रख सकता है, जो अपनी समझदारी से इसकी चेन को तोड़ सकते हैं। दूसरी, इनका आकार मध्यम है और यह सिर्फ ड्रापलेट्स के जरिए ही संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में एक-दूसरे से छह फीट की दूरी, सही तरीके से मास्क पहनकर और समय-समय पर साबुन-पानी से हाथ धोकर या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके कोरोना महामारी से निजात पाई जा सकती है।

**तो नहीं होगा लाकडाउन :** लाकडाउन यानी जीवन के लिए जरूरी तमाम गतिविधियों को कुछ वक्त के लिए रोक देना। हालांकि यह कोरोना का उपचार नहीं है। फिर भी जब आमजन कोरोना महामारी के खतरे को जानते-समझते हुए भी उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करते तो सरकार-प्रशासन को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। यदि आमजन कोरोना के खतरे को समझकर उससे बचाव के अनुरूप व्यवहार को अपनी आदत बना लें तो बिना लाकडाउन लगाए ही कोरोना को नियंत्रित व खत्म किया जा सकता है। वैक्सीन के प्रति हर प्रकार की भ्रांति को नजरअंदाज कर समय पर इसकी डोज लें तो कोई कारण नहीं है कि पार्क, बस, ट्रेन, मंदिर, स्कूल आदि बंद हों।




**बने कोरोना संस्कृति :** कोरोना संस्कृति से अर्थ है कि बीते करीब डेढ़ साल में हर किसी में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन और मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बरतने को लेकर जो आदतें विकसित हुई हैं, उनका लगातार पालन न सिर्फ कोरोना, बल्कि अन्य संक्रमणों से भी रक्षा कर सकता है। इसके प्रति सरकार को न केवल सख्त रुख अपनाना चाहिए, बल्कि उस तरह से सुविधाएं भी मुहैया करानी चाहिए। एक बार कोरोना संस्कृति पूरी तरह विकसित हो गई तो सरकार को न तो लाकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही कोरोना संक्रमण का इतना खतरा रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के खतरनाक परिणामों के बाद भी जो लोग सबक नहीं सीख रहे, उन्हें सख्त संदेश देकर इसका अनुपालन कराया जाना चाहिए।

**सिंगल डोज यानी सीमित सुरक्षा :** कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन कोई भी हो, सही समय पर दोनों डोज लेने से ही कोरोना के विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में एंटीबाडी विकसित होती हैं। तय समयावधि के बाद पहली डोज से बनी एंटीबाडी भी खत्म हो जाती है और संक्रमण का खतरा एक भी डोज नहीं लेने के बराबर हो जाता है। यही नहीं पहली डोज के बाद निर्धारित समय पर दूसरी डोज न लेने पर अपेक्षाकृत कुछ कम एंटीबाडी विकसित होती हैं। इससे पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली डोज लें और पूरी सावधानी बरतते हुए जैसे ही दूसरी डोज लेने का वक्त पूरा हो, तुरंत ही वैक्सीनेशन करवाएं।

**टीकाकरण के बाद भी रहें सतर्क :** कोरोना वैक्सीन की दो डोज लेने वाले संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित हो गए, ऐसा मानना सही नहीं है। अध्ययनों के अनुसार, दो डोज लेने के बावजूद 10 फीसद लोग न केवल खुद संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। यह बात अलग है कि कोरोना संक्रमित हुए इन लोगों में से तीन फीसद में ही गंभीर लक्षण होते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित होने वालों में से महज 0.4 फीसद की ही मृत्यु होने की आशंका होती है। ऐसे में यदि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कोरोना संस्कृति नहीं अपनाएंगे तो भी कोरोना की चेन नहीं टूटेगी और संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के जिन लोगों को अभी वैक्सीन की सुरक्षा नहीं मिल पाई है, वे भी आपकी लापरवाही के गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं।

**न टूटे नाजुक कड़ी :** तमाम सुरक्षा के बावजूद हमारे समाज की सबसे नाजुक कड़ी हैं बच्चे, बीमार और बुजुर्ग। इनके प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें। बच्चे, बीमार और बुजुर्ग घर से बाहर कम ही निकलते हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा बाहर जाने वाले स्वजन से ही होता है। बेहतर होगा बाहर से आने वाले सदस्य स्नान करने व कपड़े बदलने के बाद ही इनके पास जाएं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार दें। बच्चों को भी बचाव उपायों के प्रति जागरूक करें। शेष वयस्क, बीमार व बुजुर्गों को चिकित्सक की सलाह के पश्चात वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं।

प्रस्तुतिः पवन कुमार मिश्र

### पांच नियमों का पालन जरूरी

- संक्रमित की जल्द पहचान के लिए अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच जारी रखी जाए।
- संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच कराई जाए।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के सभी प्रयास किए जाएं। खान-पान की सेहतमंद आदतों का पालन हो।
- गंभीर परिणामों से बचाव के लिए जल्द से जल्द पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दे दी जाएं।
- कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। बेवजह बाहर न जाएं और बाहर जाना ही हो तो मास्क व शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें।

### प्रशासन रखे ये तैयारियां

- संक्रमितों को इलाज के लिए दूरदराज न जाना पड़े, घर के पास नजदीकी अस्पताल में हो व्यवस्था। गंभीर रोगियों को ही बड़े अस्पतालों में भेजा जाए।
- हर जिले में आवश्यक क्षमता के अनुसार आक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाए, क्योंकि इससे मचा हाहाकार पूरी व्यवस्था को हिला देता है।
- वयस्क व बच्चों के लिए आइसीयू व वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही पर्याप्त दवाएं, डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।
- शहर हों या गांव, हर कोरोना संक्रमित को एक जैसा उपचार मिल सके, इसके लिए शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज किया जाए।
- आपदा प्रबंधन की तैयारी कर ली जाए ताकि अचानक संक्रमण बढ़ने पर अफरा तफरी का माहौल न बनने पाए।
- टीकाकरण व बचाव उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ हर हालात से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखा जाए।

नेक सलाह

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.)
डा. विमल अरोड़ा
वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ,
क्लोव डेंटल, नई दिल्ली

## कोरोना से बचाएं मसूढ़े और दांत

ओरल हाइजीन (मुंह की स्वच्छता) पर ध्यान न देने से कोविड के मरीजों का वायरल लोड बढ़ सकता है व कोविड की समस्या भी गंभीर हो सकती है...

ओरल कैविटी मुंह में बहुत से वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का बसेरा बना देती है। इसलिए ओरल हेल्थ पर ध्यान देना अनिवार्य है ताकि आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो। कई परीक्षणों से यह प्रमाणित हुआ है कि ओरल हेल्थ खराब हो तो कोरोना संक्रमण अधिक गंभीर हो सकता है और यहां तक कि ठीक होने में भी अधिक समय लग सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि फेफड़ों का संक्रमण और मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाला वायरस एक ही है। मसूड़ों में सूजन होने पर सीआरपी वैल्यू (सी-रिएक्टिव प्रोटीन, शरीर में अति सूजन के लिए एक मार्कर) की रीडिंग अधिक हो जाती है जिसके चलते कोविड के इलाज के दौरान डाक्टर गलत अर्थ लगा सकते हैं।



**ये लक्षण आ रहे नजर :** दूसरी लहर में आए डेल्टा वैरिएंट के चलते कोविड रिकवरी के दौरान मुंह में कई विचित्र लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसे में चेतावनी के कुछ संकेतों को लेकर अधिक सतर्क रहें, जैसे दांतों का हिलना/ढीला होना। दुर्गंध, दांत दर्द, मुंह में छाले, ओरल म्यूकोसा का लाल होना, नाक से काला तरल निकलना, खून बहना, आंखों में सूजन। इन संकेतों के दिखने पर तुरंत डेंटिस्ट से मिलें।

**जरूरी है संपूर्ण देखभाल :** कोविड से रिकवर हो चुके सभी मरीजों को यह सलाह दी जाती है कि खुद घर पर अच्छी रोशनी में आइने में देखें कि दांतों में चेतावनी का कोई संकेत तो नहीं साथ ही डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार चलाए जा रहे 'पोस्ट कोविड रिकवरी ओरल स्क्रीनिंग प्लान' का हिस्सा बनें। यह ओरल केयर प्लान व्यापक है जिसका मकसद कोविड से रिकवरी के दौरान ओरल हेल्थ की संपूर्ण देखभाल करनी है। इसके तहत कुछ चरणों में जांच और देखभाल की जाती है।

1. पूरे मुंह का एक्सरे। संक्रमण और दांतों में सड़न का पता लगाने के लिए।
2. अल्सर, फंगस और दांतों की अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए मुंह, लार ग्रंथियों और जबड़े की पूरी जांच।
3. मसूड़ों के नीचे गहरी और पूरी सफाई।

**मुंह स्वच्छ तो आप सुरक्षित**

मुंह की संपूर्ण स्वच्छता के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन आपः

- फ्लास करें, टंग क्लीनर का उपयोग करें, दो बार ब्रश जरूर करें।
- चिकित्सक से परामर्श करके दिन में दो बार अच्छे माउथवाश का उपयोग करें।
- अपने टूथब्रश और टंग क्लीनर को अन्य सदस्यों के टूथब्रश और टंग क्लीनर से दूर रखें। इन्हें वक्त-वक्त पर बदलते भी रहें।

काम की बात

डा. मनीष वैश्य, निदेशक,
न्यूरोसर्जरी विभाग, मैक्स
हास्पिटल, गाजियाबाद

## रीढ़ की हड्डी की समझें तकलीफ

स्पाइनल डिसआर्डर्स के कारण होने वाली बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें से स्कोलियोसिस एक है। स्कोलियोसिस एक डिसआर्डर है जिसमें स्पाइन या रीढ़ की हड्डी असामान्य तरीके से मुड़ जाती है। यह परिवर्तन कर्व साइड से भी दिखाई देने लगता है, अमेरिकन एसोसिएशन आफ न्यूरोलाजिकल सर्जंस के अनुसार, स्कोलियोसिस के 80 फीसद मामलों में इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। अधिकतर बच्चों में सात साल की उम्र तक इसका डायग्नोसिस हो जाता है।

**क्या है स्कोलियोसिस :** रीढ़ की हड्डी जब आसामान्य रूप से मुड़ती है तो उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। इसके सामान्य आकार में दो कर्व होते हैं, पहला, ऊपर कंधे की ओर और दूसरा, कमर के निचले भाग में। अगर रीढ़ की हड्डी में कर्व साइड की ओर हो या स्पाइन एस या सी के आकार की हो। यह स्थिति बच्चों में किशोरावस्था तक पहुंचने से पहले विकसित होती है। स्कोलियोसिस के अधिकतर मामले मामूली होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ स्थिति गंभीर होती जाती है।

**जिम्मेदार कारक :** इसके अधिकतर कारक आनुवांशिक होते हैं। इसके अलावा, यह तकलीफ निम्न कारणों से भी हो सकती हैः

- न्यूरोमस्क्युलर कंडीशंस, जैसे सेरिब्रल पाल्सी या मस्क्युलर डिसट्राफी, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या संक्रमण होना। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के विकास को प्रभावित करने वाली जन्मजात विकृतियां, जैसे स्पाइनल बायफिडा भी अहम कारक है।
- स्कोलियोसिस के गंभीर मामलों में, पसलियों के कारण फेफड़ों और हृदय पर दबाव बढ़ता है। इससे सांस लेने और हृदय को रक्त पंप करने में कठिनाई होती है। स्कोलियोसिस के कारण शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे नितंब, कंधे, पसलियां और रीढ़ की हड्डी के आकार में परिवर्तन आ जाता है।



**जांच व उपचार जो रहेंगे मददगार :** इसका पता लगाने के लिए चिकित्सक शारीरिक परीक्षण करते हैं। इसकी संरचना को समझने के लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट कराने की सलाह भी दी जा सकती है, जैसे एक्स-रे, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, बोन स्कैन इमेजिंग टेस्ट आदि। उपचार के सबसे प्रमुख विकल्प ब्रेसिंग और सर्जरी है।

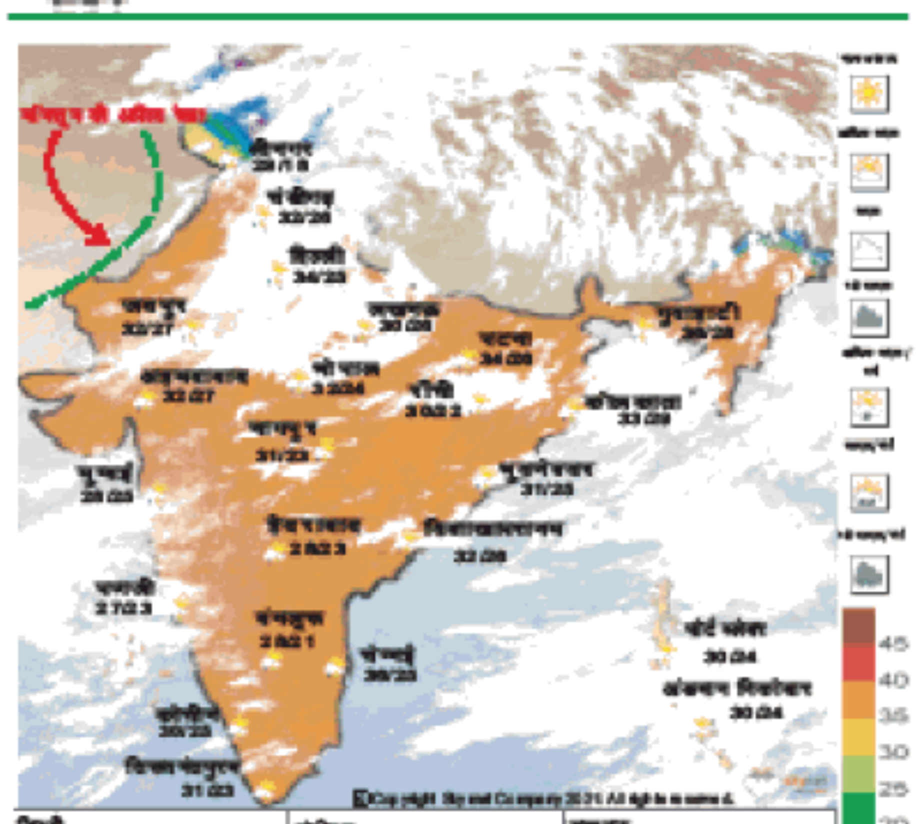
अगर कर्व लगातार बढ़ रहा है और यह 25-40 डिग्री है तो ब्रेसिंग की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेसिंग से रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, लेकिन यह कर्व को बढ़ने से रोक सकती है। जब स्कोलियोसिस की पहचान जल्दी हो जाती है, तब ब्रेसिंग अधिक प्रभावी होता है। जिन लोगों को ब्रेस लगाए जाते हैं, उन्हें इसे प्रतिदिन 15-20 घंटे तक पहनना पड़ता है। जितने अधिक समय तक मरीज इसे लगाए रखेगा, परिणाम उतने बेहतर आएंगे।

सर्जरी उन लोगों के लिए जरूरी हो जाती है जिनका कर्व 40 डिग्री से अधिक हो। सर्जन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि स्पाइन के विकास को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किए बिना कर्व को बढ़ने से कैसे रोका जाए। सर्जरी में स्पाइनल फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा स्पाइन के असामान्य विकास को रोकने का प्रयास किया जाता है।

**सर्जरी के बाद की सावधानियां :** ऐसे मरीज सर्जरी के बाद तुरंत ठीक नहीं हो जाते, उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगता है। घाव 12-14 दिनों में भर जाते हैं और फ्यूजन को पूरी तरह ठीक होने में आठ-नौ महीने का समय लगता है। हालांकि मरीज की स्थिति में सुधार छह महीने बाद दिखने लगता है। सर्जरी के बाद कोई भी भारी सामान उठाने, मुड़ने या तेजी से घूमने से बचना चाहिए। इस दौरान केवल उतनी एक्सरसाइज करें जिससे स्पाइन पर दबाव न पड़े या यह मुड़े न। जब तक फ्यूजन ठीक नहीं हो जाता तब तक फुटबाल, हाकी और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों से दूर रहें।

### इन लक्षणों पर रखें नजर

- ऊंचे-नीचे कंधे। रीढ़ की हड्डी घूम या मुड़ जाना।
- चूंकि फेफड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होना।
- लगातार कमर में दर्द रहना।





## लाड्‌र्स के मैदान में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया

क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लाड्‌र्स मैदान में 1884 में आज ही पहला टेस्ट मैच खेला गया था। एशेज सीरीज के तहत तीन दिनों तक खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया को एक पारी और पांच रन से हराया था।





## दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं सिरिमाओ भंडारनायके

वर्ष 1960 में आज ही सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थीं। वह किसी देश में प्रधानमंत्री बनने वाली दुनिया की पहली महिला थीं। 1959 में अपने पति सोलोमान भंडारनायके की हत्या के बाद सिरिमाओ ने राजनीति में कदम रखा था।

## सेना में भी रहे थे रूमानी गीतकार आनंद बक्शी

चार दशक तक बालीवुड पर राज करने वाले गीतकार आनंद बक्शी का जन्म आज ही 1930 में रावलपिंडी में (अब पाकिस्तान में) हुआ था। 1947 में इनका परिवार भारत आया था। इन्होंने रायल इंडियन नेवी में दो साल नौकरी की, इसके बाद सेना में रहने के दौरान गीत लिखते थे। नौकरी छोड़ मुंबई गए और 1958 में फिल्म भला आदमी से गीतकार के रूप में जुड़े। तेरे मेरे बीच में, तुझे देखा तो ये जाना सनम गानों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुने गए। 30 मार्च, 2002 को इनका निधन हो गया।



# दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति ने भी की अंतरिक्ष की सैर

### मिशन अंतरिक्ष

- 10 दिन के अंदर वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रेनसन के बाद अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष में दस्तक
- ब्रेनसन ने 90 किलोमीटर और बेजोस की टीम ने 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक किया सफर
- जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस, 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन और 82 वर्षीय महिला वैली फंक ने अंतरिक्ष की सैर की



धरती पर वापसी के बाद अपनी सहयोगी से गले मिलते जेफ बेजोस • रायटर

टीम ब्लू के मौजूदा और पुराने साथियों को स्पेस फ्लाइट के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बधाई। यह नए लोगों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा का अवसर खोलेगा।
– सफल अभियान के बाद ब्लू ओरिजन का ट्वीट

### 11 जुलाई को गए थे रिचर्ड ब्रेनसन

ब्रिटेन के रिचर्ड ब्रेनसन ने 11 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर की थी। उन्होंने 90 किलोमीटर का सफर तय किया था और उनकी पूरी यात्रा 55 मिनट में पूरी हुई थी।

दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ई-कामर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने तीन अन्य के साथ अंतरिक्ष की सैर कर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया है। 204 अरब डालर की संपत्ति के मालिक बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजन के बनाए राकेट न्यू शेपर्ड ने चार यात्रियों के साथ कैप्सूल को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इन सवारों में जेफ बेजोस के भाई मार्क बेजोस, 82 वर्षीय पायलट व एविएशन सिक्योरिटी इनवेस्टिगेटर वैली फंक और 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन शामिल थे। सफर में यह टीम 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। पूरे अभियान में 10 मिनट से कुछ ज्यादा का समय लगा। ब्लू ओरिजन ने इस यात्रा का पूरा वीडियो भी वेबसाइट पर साझा किया है। इसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा था। वापसी के बाद बेजोस ने इस दिन को सबसे अच्छा बताया।

### अहम बातें

- पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड के नाम पर ही ब्लू ओरिजन ने अपने राकेट का नाम न्यू शेपर्ड रखा है
- यह वीटीवीएल (वर्टिकल टेकआफ वर्टिकल लैंडिंग) तकनीक पर काम करने वाला राकेट है, जिसे पूरी तरह दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है

### ऐसे बढ़े कदम

- **6:43 बजे शाम:** राकेट न्यू शेपर्ड ने चारों यात्रियों के साथ उड़ान भरी
- **6:46 बजे:** यात्रियों ने कारमन लाइन (100 किमी) को पार किया
- **6:48 बजे:** राकेट और कैप्सूल अलग हुए। राकेट ने नीचे का सफर शुरू किया
- **6:50 बजे:** राकेट लांच पैड पर वापस आया
- **6:54 बजे:** कैप्सूल भी धरती पर वापस लौट आया



जागरण रिसर्च



## जर्मनी में समुद्र तट पर ही गुजारिए रात

दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो नई-नई तरकीबें आजमा कर पर्यटन के जरिये अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। कोरोना के बाद दुनिया में जीने के तौर-तरीकों में बदलाव आया है। जर्मनी के होटल मालिक ने पहली बार समुद्र तट पर रात बिताने के लिए विशेष रूप से आरामदायक कुर्सियां डिजाइन की हैं। मामूली खर्च पर इनमें रात बिताने के लिए गद्दे और रजाइयां भी उपलब्ध हैं। एपी

### इधर-उधर की

## पांच दिन तक दो दीवारों के बीच फंसा रहा कुत्ता



अग्निशमन विभाग ने हथौड़े से दीवार तोड़कर बचाया। इंटरनेट मीडिया

**वाशिंगटन, एजेंसी:** जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अमेरिका के ओहायो से आई खबर इस पंक्ति को सच साबित कर रही है। यहां पांच दिन तक दो दीवारों के बीच फंसे गेर्टी नाम के कुत्ते को अग्निशमन विभाग ने सुरक्षित निकाला है। सिनसिनाटी अग्निशमन विभाग ने कहा, पांच दिन से लापता गेर्टी की तलाश के लिए कई जगह पोस्टर लगाए गए थे। इसी बीच, एक शख्स ने दीवार के पीछे से कुछ आवाज सुनने के बाद हमसे संपर्क किया। इसके बाद बचाव अभियान चलाकर कुत्ते को बचाया गया। कुत्ता दोनों दीवारों के बीच की जगह में गिरकर फंस गया था। विभाग ने रेस्क्यू का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया है।

# विज्ञानियों ने विकसित किया खास कार्बनिक पदार्थ, टूटे उपकरण खुद करेंगे अपनी मरम्मत

**सफलता** ▶ आइआइएसईआर और आइआइटी, खड़गपुर के विज्ञानियों को मिली कामयाबी

### अमेरिका के प्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया गया शोध

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता**

साइंस फिक्शन फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि कोई मशीन या रोबोट खराब होने या टूटने के बाद खुद-ब-खुद अपनी मरम्मत कर खुद को दुरुस्त कर पहले की तरह बन जाता है। यह देखने में बेहद ही अचरज भरा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि फिलहाल यह संभव नहीं है। यदि हम कहें कि फिल्मी पर्दे और किताबों का ये अफसाना हकीकत बनने जा रहा है तो शायद एकबारगी आपको यकीन न हो, लेकिन भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसा करने में सफलता हासिल कर ली है।

जरा सोचिए आपके हाथ से मोबाइल फोन गिरे और उसकी स्क्रीन टूटे और फिर खुद ब खुद ठीक भी हो जाए। ये और ऐसी कई कल्पनाएं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर), कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), खड़गपुर के बनाए गए एक पदार्थ से भविष्य में सच हो सकती हैं। यहां के विशेषज्ञों ने ऐसे पदार्थ का आविष्कार करने में सफलता हासिल कर ली है, जो पलक झपकते ही अपने अंदर हुई टूट आदि की मरम्मत कर सकता है।

**आप्टिकल उद्योग में किया जा सकता है प्रयोग :** अमेरिका के प्रतिष्ठित विज्ञान (एएएस) जर्नल में यह शोध प्रकाशित हुआ है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों के स्वतः मरम्मत से लेकर आप्टिकल उद्योग में इस नए पदार्थ का कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पहले जो स्व-उपचारात्मक सामग्री विकसित की गई थीं, उनका इस्तेमाल एयरोस्पेस, अभियांत्रिकी और स्वचालन में किया जाता है। नए पदार्थ और पहले से इस्तेमाल किए जा रहे पदार्थ में अंतर यह है कि उन्होंने अब ठोस पदार्थ के एक नए वर्ग को संश्लेषित किया है, जो उनके दावे के मुताबिक अन्य प्रतिस्पर्धी सामग्री की तुलना में 10 गुना ज्यादा सख्त है। पूर्व में विकसित सामग्री इसके विपरीत नरम और अनाकार (बिना किसी स्पष्ट परिभाषित आकार के) थी और उसे स्वतः मरम्मत करने में मदद के लिए प्रकाश, उष्मा या एक रसायन की आवश्यकता होती है। हालांकि, नया पदार्थ सख्त है और अपने विद्युत आवेशों का इस्तेमाल स्वतः उपचार के लिए करता है।

**खंडित टुकड़े त्वरण के साथ मधुमक्खी के पंख जैसी गति के साथ बढ़ते हैं :** आइआइटी खड़गपुर के प्रोफेसर भानू भूषण खातुआ ने बताया कि मरम्मत के दौरान खंडित टुकड़े त्वरण के साथ मधुमक्खी के पंख जैसी गति के साथ बढ़ते हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2015 में प्रतिष्ठित स्वर्ण जयंती फैलोशिप प्राप्त कर चुके प्रोफेसर सी मल्ला रेड्डी और उनके दल ने आइआइएसईआर, कोलकाता में ठोस पदार्थ की नई श्रेणी का संश्लेषण किया।



नए पदार्थ से टूटे हुए उपकरणों की मरम्मत कराने की नहीं पड़ेगी जरूरत। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

### यह है प्रक्रिया

विज्ञानियों ने कहा कि अत्याधिक क्रिस्टलीय सामग्री जब खंडित हो जाती है तो पलक झपकते ही स्वयं को आगे बढ़ा सकती है और फिर से जुड़ सकती है। साथ ही खुद की इतनी सटीकता के साथ मरम्मत कर सकती है कि अखंडित सामग्री और उसमें भेद करना मुमकिन नहीं होता।

# हरियाली के बीच रहने से तेज हो सकता है बच्चों का दिमाग

**अनुसंधान**



ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अध्ययन में सामने आए लाभ। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

हरियाली के बीच रहने का सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे तन और मन दोनों को लाभ होता है। ऐसे माहौल का बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि पेड़-पौधों के समीप रहने से बच्चों का मस्तिष्क विकास बेहतर हो सकता है। इससे न सिर्फ उनका दिमाग तेज हो सकता है, बल्कि भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कालेज लंदन और इंपीरियल कालेज लंदन के शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन से शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। यह निष्कर्ष लंदन के 31 स्कूलों में पढ़ने वाले नौ से 15 साल की उम्र के 3,568 बच्चों के डाटा के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। बच्चों की उम्र का यह एक ऐसा दौर होता है, जब उनमें सोचने, समझने और विचार करने की क्षमताओं का विकास होता है। नेचर सस्टेनबिलिटी पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में शहरों में प्राकृतिक माहौल का बच्चों के मस्तिष्क विकास, मानसिक सेहत व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुल प्रभाव पर गौर किया गया।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, रोजाना हरियाली में अधिक समय रहने वाले बच्चों में मस्तिष्क विकास बेहतर पाया गया। ऐसे बच्चों में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं का खतरा भी 16 फीसद कम पाया गया। यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के शोधकर्ता मिकेल मेस ने कहा, 'पूर्व के अध्ययनों से भी जाहिर हो चुका है कि शहरी माहौल में हरियाली का मस्तिष्क विकास और मानसिक सेहत से सकारात्मक संबंध होता है।' -आइएएनएस

## स्क्रीन शॉट

# शुरुआत में बिना मेकअप के ही आडिशन देने जाती थी : मिथिला

रिजेक्शन और संघर्ष कलाकारों के जीवन का हिस्सा होता है। त्रिभंगा, कारवां जैसी फिल्में कर चुकीं मिथिला पालकर भी इन सबसे गुजर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में मिथिला ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दौर के बारे में बताया कि मैंने जब आडिशन देना शुरू किया तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं बिना मेकअप ही आडिशन देने चली जाती थी। मस्तमौला थी। मैं जानती ही थी कि मुझे एक्टर बनना है तो दूसरी बातें दिमाग में आती ही नहीं थीं, लेकिन साल-डेढ़ साल बाद भी काम नहीं मिला तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी कि इतने रिजेक्शंस क्यों मिल रहे हैं। मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि, रिजेक्शन कलाकारों के करियर का हिस्सा होता है। मैं जब कुछ बन गई थी तब दो-तीन साल बाद लोगों ने कहा कि मैं बहुत साधारण सी लगती थी। इसलिए सिलेक्ट नहीं हुई। मेकअप करना मुझे आज भी बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन उस वक्त मेरे मेंटर ने कहा था कि थोड़ा मेकअप करके जाना जरूरी होता है, क्योंकि आडिशन में भी कैमरा और लाइट्स होती हैं। फिर मैंने मेकअप करना शुरू किया था। दरअसल, मैं 12 साल की उम्र से ही जानती थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। 12 साल की उम्र में जब स्टेज पर कदम रखा था तभी महसूस हो गया था कि इतना खुश मैंने कभी महसूस नहीं किया है।



काजोल के साथ त्रिभंगा फिल्म में नजर आई थीं मिथिला। इंस्टाग्राम

# नेहा और अंगद ने फैंस से बच्चे का नाम सुझाने को कहा

सितारों के जीवन में फैंस की अहम जगह होती है। इंटरनेट मीडिया के जरिये वे उनसे जुड़े हुए भी होते हैं। अपनी लाइफ की कई छोटी-बड़ी बातें उनसे साझा भी करते हैं। हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने इंस्टाग्राम के जरिये बताया कि वह दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं। अब प्रशंसकों के साथ लाइव चैट में दोनों में अपने दूसरे बच्चे का नाम सुझाने के लिए भी कहा है। मंगलवार को लाइव चैट के दौरान एक फैन ने अंगद से कहा कि उनकी बेटी का नाम मेहर है तो उन्हें आने वाले बच्चे का नाम गुरमेहर रखना चाहिए। यह नाम नेहा और अंगद दोनों को ही पसंद आया। दोनों ने कहा कि और नाम सुझाते रहें। इस बीच दोनों ही मस्ती के मूड में भी नजर आए। अंगद ने कहा कि इस लाइव के लिए नेहा ने जल्दी से मेकअप कर लिया है। वहीं, नेहा ने कहा कि मैंने मेकअप इसलिए किया, ताकि सबको लगे कि यह प्रेग्नेंसी वाला ग्लो है। इस पर अंगद ने कहा कि नेहा से ज्यादा तो वह ग्लो कर रहे हैं। इस लाइव के दौरान अंगद ने नेहा को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया। एक प्रशंसक ने जब अंगद से पूछा कि वह अपनी बेटी मेहर का चेहरा इंटरनेट मीडिया पर क्यों नहीं दिखाते हैं? इसका जवाब देते हुए अंगद ने कहा कि वह अभी बहुत छोटी हैं। जब वह बड़ी हो जाएंगी और समझदार हो जाएंगी तो वह अपने लिए खुद च्वाइस कर लेंगी।



दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं अंगद और नेहा। इंस्टाग्राम

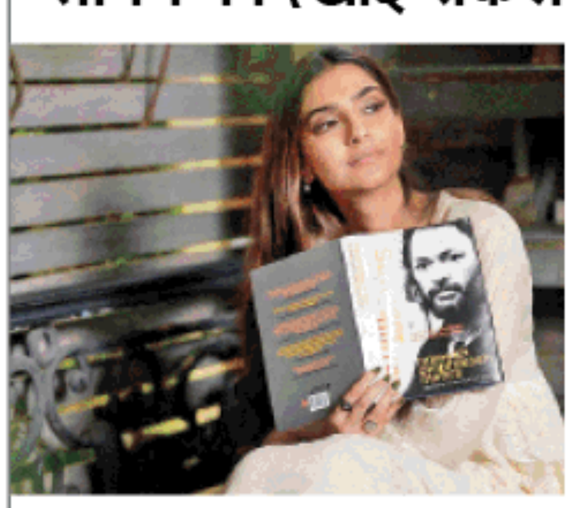
# बेमन से दिया था फील्स लाइक इश्क का आडिशन : स्कंद ठाकुर

कई बार काम की सफलता या असफलता में किस्मत भी बहुत अहम भूमिका निभा जाती है। इसे किस्मत ही कहेंगे कि आगामी एंथोलाजी (कई लघु कहानियों से बनी) वेब सीरीज फील्स लाइक इश्क के अभिनेता स्कंद ठाकुर ने बेमन से इसके लिए आडिशन दिया और वह इस शो के लिए चुन भी लिए गए। स्कंद इस शो में जयदीप सरकार द्वारा निर्देशित इश्क मस्ताना कहानी का हिस्सा हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में स्कंद बताते हैं, 'पिछले साल मैंने पूरा लाकडाउन पहाड़ों पर गुजारा था। उसके बाद मुंबई अपने घर आया तो महामारी की परिस्थितियों में घर एकदम बंद-बंद सा लग रहा था। पूरे लाकडाउन के बाद यह पहला आडिशन था जो मैं स्टूडियो में जाकर दे सकता था। यही मेरे लिए एकमात्र प्रेरणा रही। वह दिन मेरे लिए अच्छा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि घर से बाहर जाकर आडिशन दूंगा तो शायद मूड अच्छा हो जाए। मैंने बेमन और लापरवाही से इस शो का आडिशन दिया। खास बात यह है कि इस शो के निर्माताओं को अपने किरदार में वही बेपरवाही चाहिए थी तो उन्हें मेरा आडिशन पसंद आ गया। हालांकि, तब तक मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद प्रोडक्शन के कहने पर मैंने जयदीप से वीडियो काल पर कुछ सामान्य बातें कीं और कोई सकारात्मक परिणाम न मिलता देख दूसरे आडिशन देखने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जयदीप को मेरा आडिशन पसंद आया और मैं इस शो के लिए चुन लिया गया हूं।' छह अलग-अलग कहानियों से मिलकर बना यह शो 23 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगा।



फील्स लाइक इश्क में रोमांटिक किरदार में दिखेंगे स्कंद। टीम नेटफ्लिक्स

# सोनम ने दिखाई राकेश ओमप्रकाश मेहरा की आत्मकथा की पहली झलक



सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। सौ. टीम सोनम

मौजूदा दौर में सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियां किताबों के माध्यम से अपने सफर और संघर्षों की अनकही कहानियां साझा कर रही हैं। इन किताबों की कड़ी में रंग दे बसंती, डेल्ही 6 और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों के निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की आटोबायोग्राफी (आत्मकथा) द स्ट्रेंजर इन द मिरर का नाम भी जुड़ गया है। मंगलवार को अभिनेत्री सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम के माध्यम से इस किताब की पहली झलक दुनिया के सामने प्रस्तुत की। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'पहली झलक। मेहरा (राकेश ओमप्रकाश मेहरा) इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर के लिए एक महान मेंटर (परामर्शदाता) हैं। स्क्रीन पर उनका उत्साह और कल्पना देखना वास्तव में एक जादुई अनुभव है। अब वह अपने नजरिये और सफर को द स्ट्रेंजर इन द मिरर के माध्यम से सभी के साथ साझा कर रहे हैं। प्रस्तुत है राकेश ओमप्रकाश मेहरा की आत्मकथा की पहली झलक।' बता दें कि इस किताब को राकेश ने लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ मिलकर लिखा है, जबकि इसकी प्रस्तावना संगीतकार ए आर रहमान ने लिखी है। यह किताब 27 जुलाई से बाजार में उपलब्ध होगी। सोनम राकेश के निर्देशन में डेल्ही 6 और भाग मिल्खा भाग फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

शर्माजी नमकीन फिल्म बनकर लगभग तैयार है। फिल्म में पहले ऋषि कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पिछले साल उनके निधन के बाद परेश रावल को यह भूमिका निभाने के लिए चुना गया। परेश इस भूमिका को निभाना किसी चुनौती से कम नहीं मानते।

# ऋषि कपूर अभिनीत किरदार निभाना बड़ी जिम्मेदारी थी

किसी दूसरे कलाकार द्वारा निभाए किरदार को आगे बढ़ाना हर कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जब वह किरदार ऋषि कपूर जैसे अभिनेता ने निभाया हो तो यह चुनौती के साथ-साथ जिम्मेदारी भी बन जाती है। कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं अभिनेता परेश रावल फिल्म शर्माजी नमकीन को लेकर। इस फिल्म में पहले ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे, लेकिन पिछले साल उनके निधन के बाद परेश रावल ने उनके द्वारा अभिनीत किरदार निभाकर हाल ही में फिल्म के अंतिम 22 दिनों की शूटिंग पूरी की। इस बारे में दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में परेश ने कहा, 'शर्माजी नमकीन ऋषि द्वारा चुनी गई सबसे बेहतरीन स्क्रिप्टस में से एक थी। उनके द्वारा अभिनीत किरदार को निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन काश वह (ऋषि) इस फिल्म को पूरा कर पाते। जब उनका रोल निभाने का मौका मिला तो मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी का अहसास हुआ। फिल्म में उनके फुटेज देखने के बाद मुझे पता चला कि इस किरदार के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है और इस किरदार को पकड़ने में फिल्म की टीम ने भी मेरी बहुत मदद की है।' बता दें कि ऋषि और परेश ने एक साथ पटेल की पंजाबी शादी, दामिनी और हथियार जैसी कई फिल्मों में काम किया है। हितेश भाटिया निर्देशित फिल्म शर्माजी नमकीन की रिलीज के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म में परेश के साथ सतीश कौशिक और जूही चावला भी अहम भूमिकाओं में हैं।



ऋषि के निधन के बाद परेश ने पूरी की फिल्म • टीम परेश

# डिजिटल पर आएगी सोनाक्षी की ककुड़ा

**हारर कामेडी फिल्मों** में अब ककुड़ा फिल्म का नाम भी जुड़ गया है। इस हारर कामेडी फिल्म की शूटिंग सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख और साकिब सलीम ने जयपुर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार से शुरू भी कर दी है। मराठी फिल्में क्लासमेट्स, मौली और फास्टर फेने बना चुके आदित्य सरपोतदार फिल्म का निर्देशन करेंगे। यह उनके निर्देशन में बनने वाली पहली हिंदी फिल्म होगी। फिल्म का निर्माण रॉनी स्क्रूवाला करेंगे। हारर कामेडी फिल्म में काम करने को लेकर सोनाक्षी ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि इस मुश्किल माहौल में कामेडी फिल्मों की जरूरत है। मुझे ककुड़ा की स्क्रिप्ट उसी समय पसंद आ गई थी, जब मैंने इसे पढ़ा था। मैं खुद इस फिल्म को बतौर दर्शक देखना चाहूंगी। रितेश ने भी हारर-कामेडी जानर को अपना पंसदीदा बताया। निर्देशक आदित्य कहते हैं कि यह बड़े पैमाने पर बनने वाली कामर्शियल फिल्म से कम नहीं होगी। फिल्म की कास्टिंग एकदम सही है। फिल्म की कहानी सोचने पर मजबूर करेगी। ककुड़ा फिल्म एक गांव के अजीब अभिशाप की है, जहां इस तिकड़ी का सामना एक भूत से होगा। फिल्म डायरेक्ट-टू-डिजिटल यानी सीधे डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज होगी। अगले साल फिल्म को रिलीज किए जाने की योजना है।



« हारर कामेडी फिल्म में होंगी सोनाक्षी • इंस्टाग्राम

# शिल्पा की शूटिंग पर अनिश्चितता का साया



पति की गिरफ्तारी के बाद शूटिंग पर नहीं पहुंचीं शिल्पा शेट्टी • इंटरनेट मीडिया

**सोमवार रात** मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से शिल्पा शेट्टी की शूटिंग पर भी अनिश्चितता का साया मंडराने लगा है। सोनी टीवी के शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की जज शिल्पा के लिए शूटिंग मुश्किल नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को शिल्पा शूटिंग पर नहीं पहुंचीं। 14 साल बाद हंगामा 2 से फिल्मों में वापसी कर रही शिल्पा के लिए फिल्म का प्रमोशन भी आसान नजर नहीं लग रहा है। बताया जा रहा है कि शिल्पा की जगह सुपर डांसर चैप्टर 4 में अभिनेत्री करिश्मा कपूर बतौर मेहमान जज शामिल हुईं। मिल रही खबरों के मुताबिक जब तक शिल्पा शो पर नहीं लौटती हैं, तब तक अनुराग बासु और गीता कपूर के साथ शो आगे बढ़ेगा, करिश्मा बतौर मेहमान शो पर होंगी। शिल्पा अभिनय में वापसी को लेकर काफी उत्साहित थीं। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा था कि बेटे वियान के कहने पर उन्होंने फिल्मों में वापसी की है।

# जल्द शाह रुख संग टाइगर 3 की शूटिंग करेंगे सलमान

**कोरोना संक्रमण की** दूसरी लहर के बाद अभिनेता सलमान खान अपनी एक था टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर है कि वह 23 जुलाई से मुंबई स्थित यशराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू करेंगे। टाइगर 3 में सलमान के साथ अभिनेता शाह रुख खान भी मेहमान भूमिका में होंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग के लिए यशराज स्टूडियो में विशेष सेट तैयार किया गया है। जहां सलमान और अभिनेत्री कट्रीना कैफ इस सप्ताहांत तक शूटिंग शुरू कर देंगे। खलनायक का किरदार निभा रहे इमरान हाशमी अगले सप्ताह टीम से जुड़ेंगे। खास बात यह है कि इस फिल्म के सेट से कुछ कदम दूर यशराज स्टूडियो में ही शाह रुख भी अपनी आगामी फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में शाह रुख जल्द ही सलमान के साथ टाइगर 3 में अपने कैमियो (मेहमान) रोल की भी शूटिंग कर सकते हैं। सेट पर दोनों सुपरस्टार्स की मौजूदगी को देखते हुए निर्माता आदित्य चोपड़ा भी इसके लिए सबसे उचित वक्त मान रहे हैं। बता दें कि पठान और टाइगर 3 दोनों फिल्मों की टीमें अगस्त मध्य तक यशराज स्टूडियो में शूटिंग करेंगी। टाइगर 3 और पठान दोनों जासूसी थ्रिलर फिल्में हैं। फरवरी में सलमान ने भी पठान के लिए अपने कैमियो रोल की शूटिंग पूरी की थी।



फिल्म में एजेंट अविनाश उर्फ टाइगर के किरदार में होंगे सलमान • जागरण आर्काइव »